RNI No. DELMUL/2012/47011

20 जून, 2026 शनिवार

नई दिल्ली
मूल्य : 01 रुपए
पृष्ठ : 08
वर्ष : 14
अंक : 80

अनोखे अंदाज़ और निराले टेवर के साथ इन्साफ की डगर

टाइम्स ऑफ़ पीडिया

www.timesofpedia.com

Email : timesofpedia@gmail.com

महिला टी20 विश्व कप : टीम इंडिया की स्टार गेंदबाज श्रेयंका पाटिल टूर्नामेंट से बाहर 07

सार समाचार

कतर से 110 दिनों के लंबे इंतजार के बाद एलएनजी लेकर दिशा टैंकर दहेज बंदरगाह पर पहुंचा

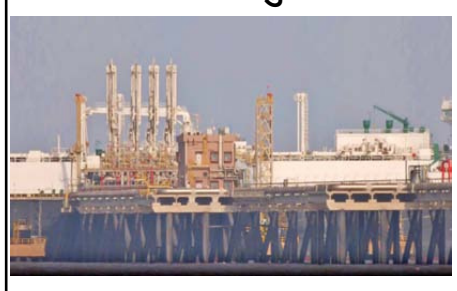

दाहेज (एजेंसी) ।मिडिल ईस्ट में बढ़ते सैन्य तनाव के कारण पिछले 110 दिनों से बंद पड़ी एलएनजी की आपूर्ति पुनः बहाल हो गई है।कतर से 62,370 मीट्रिक टन गैस लेकर चला विशाल टैंकर दिशा होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे संवेदनशील समुद्री मार्ग को सुरक्षित पार करते हुए दाहेज एलएनजी टर्मिनल पहुंच गया है।अमेरिका और ईरान के बीच हालिया शांति समझौते ने इस व्यापारिक मार्ग को पुनर्जीवित करने में अहम भूमिका निभाई है।भारत की प्रमुख एलएनजी आयातक कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी के लिए यह खेप अत्यंत महत्वपूर्ण है।मार्च महीने से बाधित इस आपूर्ति ने देश की ऊर्जा सुरक्षा पर चिंता बढ़ा दी थी, क्योंकि कतर भारत का सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता है।शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित इस टैंकर का पहुंचना पेट्रोनेट एलएनजी के साथ हुए दीर्घकालिक अनुबंध की सफलता और निरंतरता का प्रमाण है।दाहेज टर्मिनल की 22.5 मिलियन टन की वार्षिक क्षमता को देखते हुए, यह आपूर्ति देश के औद्योगिक और बिजली उत्पादन क्षेत्रों के लिए एक बड़ा बूस्ट साबित होगी। विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक ईंधन संकट के बीच इस खेप का पहुंचना भारत की सक्रिय कूटनीतिक रणनीति का परिणाम है।अब भविष्य में एलएनजी की नियमित आपूर्ति से देश में निर्बाध ऊर्जा उत्पादन सुनिश्चित होने की प्रबल उम्मीद है।

सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी 2026 की याचिकाओं पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार किया

नई दिल्ली (एजेंसी) ।उच्चतम न्यायालय ने मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश परीक्षा, नीट-यूजी की दोबारा परीक्षा को लेकर चिंता जताने वाली याचिकाओं पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया।न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि इस परीक्षा से जुड़ी सभी याचिकाएं पहले से ही न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा के नेतृत्व वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध हैं।यह परीक्षा आगामी 21 जून को आयोजित होने जा रही है।नीट परीक्षार्थियों का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ताओं ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के समक्ष जब इस मुद्दे का उल्लेख किया तो मुख्य न्यायाधीश ने कहा, नीट से जुड़े सभी मामले न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ के पास जाएंगे।इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है।इसके बाद, एक अन्य अधिवक्ता ने लगभग 1,600 नीट परीक्षार्थियों की चिंताओं की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया।उन्होंने दलील दी कि सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों और दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष चल रही कार्यवाही के कारण छात्र भारी तनाव और अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं।वकील ने तर्क दिया कि कथित पेपर लीक की रिपोर्टों और परीक्षा प्रक्रिया को लेकर चल रही चचाओं के कारण छात्र भारी दबाव और चिंता में हैं।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारतीय वायुसेना तैयार, देशभर में होंगे विशेष योग कार्यक्रम

नई दिल्ली (एजेंसी) ।अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को लेकर भारतीय वायुसेना ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं।रक्षा मंत्रालय के अनुसार, भारतीय वायुसेना इस अवसर पर कॉमन योग प्रोटोकॉल का आयोजन करेगी और फिटनेस, मानसिक मजबूती तथा समग्र स्वास्थ्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराएगी।भारतीय वायुसेना का मानना है कि शारीरिक फिटनेस, मानसिक दृढ़ता और आंतरिक संतुलन हर एयर वॉरियर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं।इन्हीं मूल्यों को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष भी वायुसेना पूरे उत्साह के साथ योग दिवस मनाने जा रही है।योग दिवस के अवसर पर देश के अलग-अलग हिस्सों में विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।यह आयोजन उत्तर में लेह के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर दक्षिण में कार निकोबार के समुद्री तटों तक, पूर्व में तवांग की सीमाओं से लेकर पश्चिम में पवित्र नगरी द्वारका तक फैला होगा।इस तरह भारतीय वायुसेना देश के लगभग हर भौगोलिक क्षेत्र में योग का संदेश पहुंचाएगी।

56 साल के हुए राहुल गांधी, 20 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति घोषित

नई दिल्ली (एजेंसी) ।लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शुक्रवार को 56 वर्ष के हो गए।वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को दिए गए उनके हलफनामे के अनुसार, उनके पास कुल 20.4 करोड़ रुपए की संपत्ति है।इसमें शेयर बाजार में निवेश, म्यूचुअल फंड और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड शामिल हैं।चुनाव आयोग को सौंपे गए इस हलफनामे में 15 मार्च 2024 तक की उनकी वित्तीय संपत्तियों का विवरण दिया गया है।हलफनामे के अनुसार, राहुल गांधी की चल संपत्तियों का कुल मूल्य 9.25 करोड़ रुपए था, जबकि अचल संपत्तियों का मूल्य 11.15 करोड़ रुपए दर्ज किया गया।राहुल गांधी के पास 24 सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 4.33 करोड़ रुपए है।उनके पोर्टफोलियो में सबसे बड़ा निवेश पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में है, जिसकी कीमत 42.27 लाख रुपए है।इसके बाद बजाज फाइनेंस में 35.89 लाख रुपए, नेस्ले इंडिया में 35.67 लाख रुपए, एशियन पेंट्स में 35.30 लाख रुपए और टाइटन कंपनी में 32.59 लाख रुपए का निवेश है।इसके अलावा, उनके पास हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीआईसीआई बैंक, इंफोसिस, आईटीसी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), एलटीआईमाइंडट्री, डिवीज लैबोरेट्रीज, दीपक नाइट्राइट, जीएमएम फाउडलर, गारवेयर टेक्निकल फाइबर्स, एल्काइल एमाइन्स केमिकल्स, फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज, सुप्रजीत इंजीनियरिंग, मोल्ड-टेक पैकेजिंग, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया, डॉ. लाल पैथलैब्स, इंफो एज, विनाइल केमिकल्स और वर्टोज एडवरटाइजिंग जैसी कंपनियों में भी हिस्सेदारी है।

महाभारत का उदाहरण देकर गृह मंत्री अमित शाह ने समझाई डेटा से इंटेलिजेंस की ताकत

नई दिल्ली (एजेंसी) । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन-2026 को संबोधित किया। इस सम्मेलन में एनसीआरबी के डायरेक्टर आलोक रंजन, सीएफएसएल के निर्देशक एसके जैन, एनसीआरबी के संयुक्त निर्देशक संजय माथुर मौजूद रहे। वहीं, कई राज्यों की पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी वर्चुअल रूप से जुड़े।गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, साक्ष्य इकट्ठा करके और चार्जशीट तक हमें ट्रेनिंग देना होगा। तीन नए कानून से वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य को साबित करना होगा। कोर्ट में सूचना को इंटेलिजेंस में परिवर्तित करने की कवायद बहुत जरूरी होती है।उन्होंने कहा कि महाभारत में कौरव पांडवों से कहीं ज्यादा मजबूत थे लेकिन पांडवों के साथ श्रीकृष्ण थे, जो सूचना को इंटेलिजेंस में परिवर्तित करते थे। इसी कारण पांडवों ने कृष्ण की वजह से युद्ध जीता था। डेटा इंटेलिजेंस में जैसा ही परिवर्तित होता है, ऐसा होने के बाद एआई के जरिए डेटा का आंकलन होना चाहिए, फिर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के अपराधियों को पकड़ने में इसका इस्तेमाल करना चाहिए।गृह मंत्री ने कहा कि आज जहां तक आपराधिक न्याय प्रणाली का सवाल है, हमारा देश परिवर्तन के कालखंड से गुजर रहा है। एक जमाने में थाना कानून और व्यवस्था को संभालकर रखने का उपकरण माना जाता था। कहीं पर कोई विवाद होता था तो थानेदार साहब मामला सुलझाते थे, नहीं तो न्यायालय में केस होता था और सालों-साल तक मामले लंबित रहते थे।आजादी की यात्रा में हम आगे बढ़े। थाने का स्वरूप अपराध नियंत्रण के रूप में विकसित होने लगा। जांच-पड़ताल शुरू हुई, अपराधी पकड़े गए और उन्हें कोर्ट के सामने पेश करने से लेकर जेल तक पहुंचाने में थाने की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई। अब समय आ गया है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को हम देश के हर नागरिक को हमारे संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाएं।अमित शाह ने कहा, ऐसे ढेरों केस हैं, जिनमें राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (एनएफआईएस-नफिस) के माध्यम से जटिल से जटिल मामलों को सरल करने में बड़ी मदद मिली है। लेकिन मैं अभी भी मानता हूं कि नफिस का उपयोग केवल 10 फीसदी ही हो रहा है। नफिस का उपयोग सिर्फ अपराधी को ढूंढने के लिए नहीं करना है। नाफिस तभी सफल हो सकता है, जब आप हर क्राइम सीन से प्राप्त फिंगरप्रिंट के माध्यम से नाफिस के डेटा को समृद्ध करें। यह एक टू-वे सिस्टम है। यह अपराधी को सिद्ध करने में बहुत उपयोगी है, लेकिन अपराध तभी सिद्ध हो सकता है, जब डेटा जनरेट हो।गृह मंत्री ने कहा, हमारा प्रशिक्षण केवल ऐप के उपयोग तक सीमित नहीं होना चाहिए। ऐप का उपयोग करके वैज्ञानिक साक्ष्य सृजित करने और चार्जशीट तक की प्रक्रिया की भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। इसके बाद अभियोजन और न्यायपालिका को भी प्रशिक्षित करना पड़ेगा कि यदि इतने साक्ष्य उपलब्ध हैं तो अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जरूरी जितने भी बदलाव थे, न्यायपालिका के काम को सरल बनाने और अभियोजन को भी सुगम बनाने के लिए जिन आवश्यकताओं की जरूरत थी, उन्हें हमने नए कानूनों में समाहित कर लिया है।

21 जून को नौसेना को मिलेगा बड़ा तोहफा

पीएम मोदी एक साथ शामिल करेंगे तीन स्वदेशी युद्धपोत

नई दिल्ली। भारतीय नौसेना नीले समंदर में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लगातार स्वदेशी युद्धपोतों को बेड़े में शामिल कर रही है। एक के बाद एक आधुनिक वॉरशिप नौसेना को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में 30 मार्च का दिन ऐतिहासिक बन गया था, जब एक ही दिन में नौसेना को तीन स्वदेशी जहाज सौंपे गए थे। 21 जून का दिन भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन ही में तीन वॉरशिप को नेवी में शामिल करेंगे।कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट में आयोजित एक खास समारोह में इन तीनों वॉरशिप को नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। इनमें एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट दूनागिरी, दूसरा एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट अग्रेह और तीसरा सर्वे वेसेल लार्ज संशोधक है। हालांकि, यह पहला मौका नहीं है जब एक ही दिन में तीन वॉरशिप नौसेना में शामिल किए जा रहे हैं। इससे पहले 15 जनवरी 2025 को मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नीलगिरी क्लास का पहला स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस नीलगिरी, डिस्ट्रॉयर आईएनएस सूरत और पनडुब्बी आईएनएस वागशीर भारतीय नौसेना में शामिल किए गए थे।इसी साल 30 मार्च को गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) ने प्रोजेक्ट 17ए के तहत निर्मित पांचवां गाइडेड स्टेल्थ फ्रिगेट दूनागिरी भारतीय नौसेना को सौंपा था। दूनागिरी, पूर्ववर्ती आईएनएस दूनागिरी का आधुनिक स्वरूप है, जो लींडर क्लास का फ्रिगेट था और 5 मई 1977 से 10 अक्टूबर 2010 तक नौसेना का हिस्सा रहा।यह 16 महीनों में भारतीय नौसेना को सौंपा गया पी17ए श्रेणी का पांचवां वॉरशिप है। पहले चार जहाजों के निर्माण से मिले अनुभव के आधार पर इसका निर्माण समय 93 महीनों से घटाकर 80 महीने कर दिया गया। प्रोजेक्ट 17ए के तहत कुल सात नीलगिरी क्लास फ्रिगेट बनाए जा रहे हैं।इनमें से पहला आईएनएस नीलगिरी जनवरी 2025 में नौसेना में शामिल हुआ था।

कोलकाता में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने दौड़ से ध्यान मैराथन को दिखाई हरी झंडी

कोलकाता (एजेंसी) । पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने शुक्रवार सुबह कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से राइटर्स बिल्डिंग तक दौड़ से ध्यान मैराथन को हरी झंडी दिखाई।

इस कार्यक्रम में मंत्री इंद्रनील खान, अग्निमित्रा पॉल, तापस रॉय, विधायक विजय ओझा, मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल और अन्य लोग शामिल हुए।मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने एक्स पर लिखा, सिटी ऑफ जॉय फिटनेस और वेलनेस के लिए दौड़ रही है। 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 से पहले आज सुबह मैंने कोलकाता में सिटी ऑफ जॉय -दौड़ से ध्यान 2026 मैराथन को हरी झंडी दिखाई। स्वच्छता से स्वागत कार्यक्रम के तहत शुरू की गई यह शानदार पहल स्वास्थ्य, स्वच्छता, नागरिक जिम्मेदारी और समग्र कल्याण जैसे अहम मूल्यों को एक साथ लाती है।

केदारनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब

दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 12.70 लाख पार

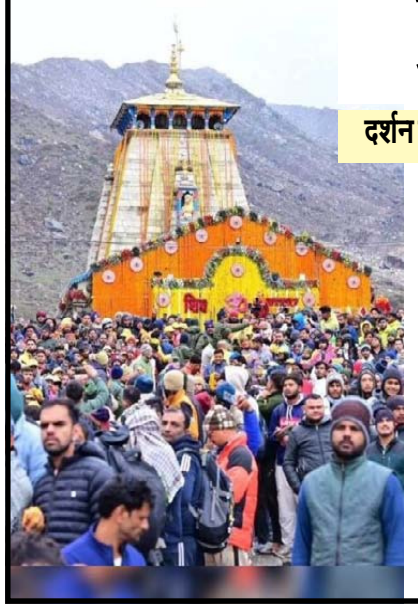

देहरादून। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में इन दिनों श्रद्धालुओं की यात्रा अपने चरम पर है। वीकेंड और छुट्टियों के चलते धाम में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।

आंकड़ों की बात करें तो गुरुवार शाम 5 बजे तक करीब 12 लाख 70 हजार 903 श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं।केदारनाथ धाम पहुंच रहे श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। कई श्रद्धालुओं ने बताया कि वर्षों की मनोकामना पूरी होने के बाद उन्हें बाबा केदार के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दर्शन के बाद श्रद्धालु भावुक भी नजर आए और उन्होंने इसे अपने जीवन का यादगार एवं आध्यात्मिक अनुभव बताया।

उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन तीन दिवसीय दौरे पर पहुंचे लद्दाख, पारंपरिक तरीके से हुआ स्वागत

नई दिल्ली (एजेंसी) । उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन अपनी प्रथम आधिकारिक लद्दाख यात्रा पर शुक्रवार को कुशोक बकुला रिनपोछे हवाई अड्डे पहुंचे। यहां लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (एलएएचडीसी) कारगिल के मुख्य कार्यकारी पार्षद डॉ. मोहम्मद जाफर अखून, लद्दाख से लोकसभा सांसद मोहम्मद हनीफा तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने हवाई अड्डे पर उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। इसके साथ ही पारंपरिक तरीके से भी उपराष्ट्रपति का भव्य स्वागत किया गया।गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 19 से 21 जून तक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति 20 जून को लुकुंग गांव की यात्रा करेंगे, जहां वे स्थानीय स्वयं सहायता समूहों के साथ संवाद करेंगे और जीवंत गांव कार्यक्रम के तहत सीमावर्ती क्षेत्र में की जा रही विकासपरक पहल का अवलोकन करेंगे। इसी दिन उपराष्ट्रपति युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।उपराष्ट्रपति 21 जून को लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। इसमें युवा, सशस्त्र बल के जवान और विभिन्न संगठनों के सदस्य योग द्वारा समग्र स्वास्थ्य और कल्याण के संदेश को बढ़ावा देने के लिए भाग लेंगे।

तमिलनाडु विधानसभा का मेकेदाटु बांध परियोजना पर विशेष प्रस्ताव, केंद्र से मंजूरी न देने की मांग

चेन्नई। कर्नाटक सरकार की प्रस्तावित मेकेदाटु बांध परियोजना के खिलाफ तमिलनाडु विधानसभा में शुक्रवार को एक विशेष प्रस्ताव पेश किया गया। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने सदन में प्रस्ताव रखते हुए केंद्र सरकार से आग्रह किया कि मेकेदाटु बांध निर्माण के लिए किसी भी प्रकार की तकनीकी, प्रशासनिक अथवा पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान न की जाए।तमिलगा वेट्री कड़गम (टीवीके) सरकार के सत्ता में आने के बाद विधानसभा का पहला सत्र गुरुवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ था। सत्र के दूसरे दिन आज राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा स्थगित कर सरकार का विशेष प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया।बैठक की शुरूआत पूर्व विधायकों सी. रामासामी, डी. वीरासामी, सी. स्वामीनाथन, एच.जी. आरुमुगम, पी. कन्नन और ए. नंजिल मुरुगेशन के निधन पर शोक प्रस्ताव के साथ हुई। इसके बाद राजस्व मंत्री एवं सदन के नेता के.ए. सेंगोट्टैयन ने विशेष प्रस्ताव को चर्चा के लिए लाने का प्रस्ताव रखा।मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि कर्नाटक सरकार कावेरी नदी पर मेकेदाटु में बांध निर्माण के लिए एकतरफा प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि यह कदम पांच फरवरी 2007 को कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम निर्णय तथा 16 फरवरी 2018 को उच्चतम न्यायालय के फैसले की भावना के विपरीत है। साथ ही, संबंधित राज्यों की सहमति और केंद्र सरकार की स्वीकृति के बिना इस परियोजना को आगे बढ़ाने का प्रयास स्वीकार्य नहीं है।उन्होंने कहा कि कावेरी न्यायाधिकरण और उच्चतम न्यायालय ने कावेरी जलग्रहण क्षेत्र को जल-अभाव वाला क्षेत्र मानते हुए उपलब्ध जल का बंटवारा संबंधित राज्यों के बीच कर दिया है। ऐसे में इस जलग्रहण क्षेत्र में किसी नई परियोजना या अतिरिक्त जल भंडारण योजना को लागू नहीं किया जा सकता।मुख्यमंत्री ने कहा कि कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों राज्यों के लिए अत्यंत संवेदनशील विषय है। इसलिए केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करे कि अन्य जलग्रहण राज्यों की सहमति और उसकी अनुमति के बिना मेकेदाटु अथवा कावेरी बेसिन के किसी अन्य हिस्से में कोई नया बांध या जलाशय परियोजना शुरू न की जाए।विशेष प्रस्ताव में केंद्रीय जल आयोग से भी अनुरोध किया गया कि वह कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पर विचार न करे, उस पर कोई कार्रवाई न करे और किसी प्रकार की स्वीकृति प्रदान न करे।

नीट री-एग्जाम से पहले केजरीवाल का छात्रों को संदेश, बोले- तनाव छोड़ें, मेहनत पर रखें भरोसा

नई दिल्ली (एजेंसी) । 21 जून को दोबारा होने वाली नीट-यूजी की परीक्षा से पहले आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने छात्रों के लिए संदेश जारी किया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने छात्रों को शुभकामनाएं दीं और उनसे कहा कि वे तनाव को दूर रखें और अपनी कड़ी मेहनत पर भरोसा रखें।

अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, हेलो बच्चो, आपकी नीट परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। सारा तनाव अब साइड में रख दो। अपनी मेहनत पर भरोसा रखो और बिल्कुल शांत मन से परीक्षा देना। आप यह कर सकते हैं।इसके साथ ही, केजरीवाल ने एक वीडियो संदेश भी शेयर किया। उन्होंने शुरूआत में अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य और परीक्षा की तैयारियों को लेकर पूछा। केजरीवाल ने कहा, हैलो बच्चो, कैसे हो? रविवार को नीट की परीक्षा है। तैयारी हो गई?छात्रों को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा, मैं जानता हूं कि आप लोगों ने बहुत कुछ सहन किया है। एक महीने में दो-दो बार पेपर देना कोई मजाक नहीं है।एक बार नीट की परीक्षा देने में ही नानी याद आ जाती है। खैर, ये सारी बातें छोड़ें। अच्छे से मन लगाकर पढो।उन्होंने छात्रों से शांत दिमाग से पेपर देने की अपील की। अपने संदेश में केजरीवाल ने कहा, कुछ घटे रह गए हैं। बहुत शांत दिमाग से पेपर देकर आना।केजरीवाल ने छात्रों की क्षमताओं पर भरोसा जताया और उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया।

मिजोरम में 4.75 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त, तस्करी में तीन महिलाएं गिरफ्तार

आइजोल। म्यांमार से ड्रग्स की तस्करी के काम में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। सुरक्षा बलों ने मिजोरम में तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया और उनके पास से 4.75 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की।रक्षा विभाग के प्रवक्ता ने शुक्रवार को बताया कि उत्तरी मिजोरम के सैतुअल जिले के केइफांग इलाके में नशीले पदार्थों की तस्करी के बारे में पक्की खुफिया जानकारी मिलने पर असम राइफल्स के जवानों ने मिजोरम पुलिस के साथ मिलकर केइफांग में एक संयुक्त चेकपोस्ट बनाया।इस ऑपरेशन के दौरान, संयुक्त टीम ने तीन महिलाओं को पकड़ा और 634 ग्राम हेरोइन बरामद की, जिसकी कीमत अवैध बाजार में 4.755 करोड़ रुपए आंकी गई है।बरामद नशीले पदार्थों और गिरफ्तार की गई तीनों महिलाओं को आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए सैतुअल जिले में मिजोरम पुलिस को सौंप दिया गया।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश बढ़ रहा विकसित भारत की ओर : रक्षा खडसे

सूरत (गुजरात) (एजेंसी) । केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों की राज्यमंत्री रक्षा खडसे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस लक्ष्य को हासिल करने में युवा शक्ति तथा नारी शक्ति की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है।केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे शुक्रवार को अपने सूरत दौरे के दौरान वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुईं।

प्रधानमंत्री मोदी के सफल कार्यकाल के उपलक्ष्य में आयोजित सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत उन्होंने स्वच्छता अभियान में भाग लेकर स्वयं झाड़ू लगाई तथा पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधरोपण भी किया।

संपादकीय

ईरान और अमरीका का सहमति पत्र

युद्ध का हजार्ना बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। यूएसए तीन सौ बिलियन डालर देने पर सहमत हो गया है। यह ठीक है कि सहमति पत्र में इसे निर्माण कार्यों के लिए दी जाने वाली राशि कहा गया है। लेकिन सब जानते और मानते हैं कि यह यूएसए द्वारा दिया जा रहा हजार्ना ही है। लड़ाई के लिए जो देश जिम्मेदार ठहराया जाता है, वह हजार्ना देता है, यह पुरानी परंपरा है। इसका अर्थ है कि अमरीका ने मान लिया है कि बिना किसी कारण से लड़ाई यूएसए ने छेड़ी थी और ईरान पीड़ित पक्ष है। इस तमाम हलचल से जिसमें हजारों लोग मारे गए, यूएसए को क्या मिला? खाड़ी देशों में उसके दबदबे और प्रतिष्ठा को ठेस लगी। इन देशों को महसूस होने लगा कि वाशिंगटन के भरोसे नहीं रहा जा सकता। मध्य पूर्व में ईरान की शक्ति का प्रदर्शन हो गया, जबकि यूएसए अपने इस अभियान से ईरान के प्रभाव को कम करना चाहता था। अमरीका महाशक्ति है और पूरी दुनिया को वह अपने प्रभाव में ला सकता है, इस भ्रम को ट्रंप ने यत्नपूर्वक तोडने में सफलता प्राप्त की है यूएसए और ईरान में प्रमुख मुद्दों को लेकर आपसी सहमति बन गई है। सहमति शुरू ही यहां से होती है कि इन मुद्दों पर केवल यूएसए और ईरान ही नहीं बल्कि दोनों के पक्ष के अन्य देश भी इस सहमति पत्र से सहमत हैं। लेकिन सहमति पत्र में कहीं भी सहयोगी देशों के नामों का उल्लेख नहीं है। अलबत्ता दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ सैनिक कार्रवाई बंद कर देंगे, इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया गया है। पर इसके साथ एक दूसरा उल्लेख है कि लेबनान के खिलाफ भी सैनिक कार्रवाई खत्म की जाएगी। लेकिन लेबनान के खिलाफ सैनिक कार्रवाई तो यूएसए कर ही नहीं रहा था। लेबनान पर कार्रवाई इजरायल कर रहा है जिसका कारण वहां हिजबुल्लाह की आतंकी गतिविधियां हैं। यूएसए ने माना है कि वह ईरान को तीन सौ बिलियन डालर देगा ताकि वहां निर्माण कार्य फिर से शुरू हो सके। ईरान की मुख्य मांग यह भी थी कि अमरीका युद्ध में हुए नुकसान का हजार्ना दे। यूएसए ने यह भी मान लिया है कि वह ईरान पर लगाए गए तमाम प्रतिबंधों को समाप्त करेगा और ईरान अपना तेल अपने हिसाब से बेच सकता है। दरअसल यूएसए का राष्ट्रपति सार्वजनिक रूप से कह रहा था कि ईरान की सरकार बदली जाएगी। इस सहमति पत्र में यूएसए ने माना है कि वह ईरान के आंतरिक मामलों में दखलअंदाजी नहीं करेगा। मुख्य मसला होर्मुज का बन गया था। ईरान ने वहां से समुद्री जहाजों की आवाजाही ही बंद नहीं की थी, बल्कि उन पर शुल्क लगाना शुरू कर दिया था। इसके उत्तर में यूएसए ने ईरान के समुद्री मार्गों की ही घेराबंदी कर ली थी। इस सहमति पत्र में यूएसए ने अपनी घेराबंदी समाप्त करने की बात मान ली है। ईरान भी इस बात पर सहमत हो गया है कि वह ओमान के साथ बैठ कर होर्मुज का मसला सुलझाएगा। यूएसए अपने टैरिफ भी खत्म करेगा। मुख्य मसला ईरान द्वारा परमाणु बम बनाने को लेकर था। यूएसए ने ईरान पर जो सैनिक कार्रवाई शुरू की थी, उसका कारण भी यही बताया गया था। सहमति पत्र में इस मामले को लेकर ईरान ने इस बात पर सहमति जताई है कि वह परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ईरान इस बात पर सहमत हो गया है कि उसके पास संवर्धित यूरेनियम का जो भंडार है, उसका समाधान अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संगठन की निगरानी में निकालेगा। दोनों देश परमाणु ऊर्जा से जुड़े मुद्दों की संवेदनशीलता पर भी सहमत हो गए हैं। परमाणु ऊर्जा से संबंधित मसलों पर जो सहमति अब दिखाई जा रही है, ईरान युद्ध से पूर्व भी इन पर लगभग सहमत ही था। इसमें कोई नई बात दिखाई नहीं दे रही। केवल भाषा और वाक्य ही नए हैं। तब प्रश्न उठेगा ही कि यूएसए को इस सारे अभियान से क्या हासिल हुआ? ईरान की सरकार को वह बदल नहीं सका। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनई को उसने अवश्य मारने में सफलता हासिल की लेकिन उसके उत्तर में ईरान ने भी ट्रंप पर ईनाम की घोषणा कर दी है। इस सहमति पत्र में वह वापस नहीं ली गई है। जहां तक परमाणु हथियारों का सवाल है, ईरान ने उनसे जुड़े जिन मुद्दों पर सहमति जताई है, उन पर वह युद्ध से पहले भी सहमत ही था। अलबत्ता इस सैन्य कार्रवाई से होर्मुज का नया मसला खड़ा हो गया है। ईरान पर अनेक प्रतिबंध लगाने के बावजूद अंत में अमरीका को पीछे हटना पड़ा। युद्ध का हजार्ना बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। यूएसए तीन सौ बिलियन डालर देने पर सहमत हो गया है। यह ठीक है कि सहमति पत्र में इसे निर्माण कार्यों के लिए दी जाने वाली राशि कहा गया है। लेकिन सब जानते और मानते हैं कि यह यूएसए द्वारा दिया जा रहा हजार्ना ही है। लड़ाई के लिए जो देश जिम्मेदार ठहराया जाता है, वह हजार्ना देता है, यह पुरानी परंपरा है। इसका अर्थ है कि अमरीका ने मान लिया है कि बिना किसी कारण से लड़ाई यूएसए ने छेड़ी थी और ईरान पीड़ित पक्ष है। इस तमाम हलचल से जिसमें हजारों लोग मारे गए, यूएसए को क्या मिला? खाड़ी देशों में उसके दबदबे और प्रतिष्ठा को ठेस लगी। इन देशों को महसूस होने लगा कि वाशिंगटन के भरोसे नहीं रहा जा सकता। मध्य पूर्व में ईरान की शक्ति का प्रदर्शन हो गया, जबकि यूएसए अपने इस अभियान से ईरान के प्रभाव को कम करना चाहता था। अमरीका महाशक्ति है और पूरी दुनिया को वह अपने प्रभाव में ला सकता है, इस भ्रम को ट्रंप ने यत्नपूर्वक तोडने में सफलता प्राप्त की है। यूक्रेन में उलझा कर अमरीका जो घाव रूस को देना चाहता था, वह घाव उसने ईरान में उलझ कर अपनी छाती पर सहेज लिया। इजरायल ने इस सहमति पत्र से दूरी बना ली और उसका कहना है कि वह लेबनान पर तब तक हमले जारी रखेगा जब तक वहां से हिजबुल्ला की कमर नहीं टूट जाती। इससे लगता है अपनी स्वयं की बनाई जिस दलदल से ट्रंप निकलना चाह रहे हैं, वह पूरी तरह निकल नहीं पाएंगे। भारत को इस बात का श्रेय दिया जाएगा कि उसने सभी सम्बन्धित पक्षों से मधुर संबंध रखते हुए भी अपने आप को उस दलदल से बचाए रखा। ट्रंप ने जब युद्ध शुरू किया था, तब कहा था कि वह ईरान को कुछ ही दिनों में मिटा सकते हैं। लेकिन ईरान ने अमरीका को यह एहसास करवा दिया कि वह उतना कमजोर नहीं है, जितना ट्रंप सोच रहे थे। जब ईरान अमरीका के समक्ष मजबूती से खड़ा रहा, तो अमरीका ने समझ लिया कि इसे मिटाना इतना आसान नहीं है। खुद अमरीका को इस लड़ाई में काफी नुकसान हुआ। ट्रंप के अपने लोग ही उन्हें लड़ाई शुरू करने के लिए जिम्मेवार मानने लगे। जब चहुं ओर से ऐसी आलोचना होने लगी तो ट्रंप ने इस लड़ाई से बाहर निकलना ही उचित समझा। हालांकि यह बात भी सत्य है कि ट्रंप कभी समझौते की बात करने लगते हैं, तो कभी बार-बार ईरान को धमकियां देने भी लग जाते हैं। वह किस ओर चलना चाहते हैं, यह समझना किसी के लिए भी आसान नहीं है। वह बार-बार अपना स्टैंड बदलते रहे हैं। इसलिए निश्चित रूप से कुछ कह पाना संभव नहीं है। फिर भी यह कामना की जा सकती है कि यह लड़ाई जल्द से जल्द बंद हो।

हाथों की खूबसूरती के अलावा बहुत सारी चीजों में काम आती है नेल पेंट

नाखूनों पर लगी नेल पेंट हाथों की सुंदरता तो बढ़ाती ही है लेकिन क्या आपको पता इसका इस्तेमाल आप हाथों के अलावा इस तरह भी कर सकते हैं। चलिए जानते इसके होने वाले अन्य इस्तेमाल।

1. त्वचा को एलर्जी से बचाएं

अगर आपको गहने पहनने से एलर्जी होती है तो अपने गहनों के अंदर की तरफ पारदर्शी नेलपॉलिश का इस्तेमाल करें जिससे स्किन पर एलर्जी या निशान नहीं पड़ेगा।

2. लिफाफा सील करें

लिफाफा चिपकाने के लिए नेलपॉलिश ग्लू का काम करती है। इससे लिफाफा ठीक से बंद हो जाएगा और खुलेगा भी नहीं।

3. स्मजप्रूफ स्टिकर

नेलपॉलिश को आप चाभियों के गुच्छे में भी लेबल कर सकते हैं। ऐसे में चाभी के गुच्छे में चाभी ढूंढने पर परेशानी नहीं होगी।

4. जंग से बचाए

दरवाजे और खिड़की को जंग से बचाने के लिए नेलपॉलिश का इस्तेमाल करें फिर इसमें सालों तक जंग लगने की समस्या नहीं होगी।

5. आसानी से पिरोएं धागा

अगर आप सूई में धागा नहीं पिरोह पाते तो नेलपॉलिश का इस्तेमाल करें। धागा पिरोने के लिए धागे के सिरे पर नेल पॉलिश लगाकर सूखा ले। फिर धागे को सुई में पिरोए।

क्या निजीकरण से सुधरेगी स्वास्थ्य व्यवस्था?

राजु कुमार

जन स्वास्थ्य अभियान, मध्यप्रदेश सहित स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे कई संगठनों ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। उनकी मांग है कि सरकार को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। उनका कहना है कि समस्या की पहचान सही है, लेकिन समाधान पर गंभीर सवाल है। यदि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों और विशेषज्ञों की कमी है तो प्राथमिकता उन कमियों को दूर करने की होनी चाहिए। मध्यप्रदेश सरकार ने रीवा, देवास और गुना जिलों में कुछ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के संचालन के लिए आउटसोर्स प्रणाली पर आधारित एक पायलट परियोजना को मंजूरी दी है। मंत्रि-परिषद के अनुसार यह व्यवस्था उन स्वास्थ्य केंद्रों में लागू की जाएगी जहां चिकित्सकों के अधिकांश पद लंबे समय से रिक्त हैं। सरकार का दावा है कि इससे आम लोगों को स्थानीय स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी और छोटी-मोटी बीमारियों के उपचार के लिए जिला अस्पतालों पर निर्भरता कम होगी। सरकार ने इस व्यवस्था को पांच वर्ष की पायलट परियोजना के रूप में लागू करने का निर्णय लिया है। इसके परिणामों का मूल्यांकन किया जाएगा और अनुभव सकारात्मक रहने पर इसे प्रदेश के अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक विस्तारित किया जा सकता है। जन स्वास्थ्य अभियान, मध्यप्रदेश सहित स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे कई संगठनों ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। उनकी मांग है कि सरकार को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। उनका कहना है कि समस्या की पहचान सही है, लेकिन समाधान पर गंभीर सवाल है। यदि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों और विशेषज्ञों की कमी है तो प्राथमिकता उन कमियों को दूर करने की होनी चाहिए, न कि संस्थानों के संचालन को

आउटसोर्स व्यवस्था के हवाले करने की। यह बहस केवल तीन जिलों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक सीमित नहीं है। इसके केंद्र में यह सवाल है कि स्वास्थ्य सेवाओं में मौजूद कमियों का समाधान सरकारी संस्थाओं को मजबूत करके किया जाएगा या उनके संचालन की जिम्मेदारी धीरे-धीरे निजी क्षेत्र को सौंपी जाएगी। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से ही अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के ताजा आंकड़े बताते हैं कि कुपोषण के साथ-साथ मोटापा, मधुमेह और हृदय रोग जैसी गैर-संचारी बीमारियां भी बढ़ रही हैं। शिशु और मातृ स्वास्थ्य से जुड़े कई संकेतकों में भी प्रदेश को अभी लंबा रास्ता तय करना है। ऐसे समय में सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की जरूरत और बढ़ जाती है। ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी के अनुसार प्रदेश में 4134 उप स्वास्थ्य केंद्रों, 1045 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और 245 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की कमी है। इसके साथ ही चिकित्सकों, विशेषज्ञों, नर्सिंग और पैरामेडिकल कर्मचारियों के बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों के अधिकांश पद खाली होने के कारण बड़ी संख्या में मरीजों को जिला अस्पतालों के लिए रेफर करना पड़ता है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में जिला अस्पताल 100 से 200 किलोमीटर दूर हैं, जिससे उपचार में देरी और मरीजों की परेशानी बढ़ जाती है। यही वह पृष्ठभूमि है जिसमें सरकार का नया निर्णय सामने आया है। लेकिन इसे लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सिस्ट) का कहना है कि यदि समस्या डॉक्टरों और विशेषज्ञों की कमी है तो उसका समाधान नियमित भर्ती, बेहतर पदस्थापना, ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा के लिए प्रोत्साहन और स्वास्थ्य संस्थानों की क्षमता बढ़ाने में खोजा जाना चाहिए। उनका मानना है कि सरकारी व्यवस्था की कमियों को दूर करने के बजाय संचालन की जिम्मेदारी किसी बाहरी एजेंसी को सौंपना स्थायी समाधान नहीं माना जा सकता। मध्यप्रदेश में यह पहला अवसर नहीं है जब स्वास्थ्य संस्थानों को निजी भागीदारी के माध्यम से संचालित करने की कोशिश की गई हो। वर्ष 2015 में अलीराजपुर जिला अस्पताल और जोबट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऐसा प्रयोग किया गया था। जन स्वास्थ्य अभियान के अनुसार वह मॉडल अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाया और क्षेत्र के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं देखा गया, नतीजतन सरकार को इसे वापस लेना पड़ा था। इसी तरह वर्ष 2024 में जिला अस्पतालों को पीपीपी मॉडल के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों से जोड़ने के प्रस्ताव पर भी व्यापक विरोध हुआ था। तब चिकित्सक संगठनों और नागरिक समाज के विभिन्न वर्गों ने आशंका जताई थी कि इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था कमजोर होगी। इसी कारण वर्तमान निर्णय को भी कई लोग एक अलग प्रशासनिक प्रयोग के बजाय स्वास्थ्य सेवाओं में निजी भागीदारी बढ़ाने की व्यापक प्रक्रिया के हिस्से के रूप में देख रहे हैं। उनकी चिंता यह है कि यदि यह मॉडल सफल घोषित किया गया तो भविष्य में इसका दायरा और बढ़ सकता है। स्वास्थ्य सेवा को सामान्य बाजार व्यवस्था की तरह नहीं देखा जा सकता। शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसे क्षेत्र हैं जहां राज्य की भूमिका केवल नियामक की नहीं बल्कि सेवा प्रदाता की भी होती है। संविधान के नीति-निदेशक सिद्धांत भी जनस्वास्थ्य के संरक्षण और सुधार की जिम्मेदारी राज्य पर डालते हैं। इसलिए स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े किसी भी बड़े फैसले का मूल्यांकन केवल प्रशासनिक सुविधा के आधार पर नहीं किया जा सकता। डॉक्टरों की कमी, विशेषज्ञ सेवाओं का अभाव और प्रबंधन की कमजोरियां वास्तविक समस्याएं हैं। लेकिन यह भी उतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यदि किसी सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं हैं तो समाधान डॉक्टरों की नियुक्ति है या अस्पताल का संचालन निजी हाथों को सौंप देना। यदि स्कूलों में शिक्षकों की कमी हो तो उसका समाधान स्कूलों का निजीकरण नहीं माना जाता। यदि पुलिस बल में रिक्तियां हों तो थानों का संचालन निजी एजेंसियों को नहीं सौंपा जाता। उसी प्रकार स्वास्थ्य संस्थानों की समस्याओं का स्थायी समाधान भी उनकी क्षमता बढ़ाने, रिक्त पद भरने और संसाधनों को मजबूत करने में ही निहित है। मध्यप्रदेश जैसे राज्य में, जहां बड़ी आबादी आज भी सरकारी अस्पतालों पर निर्भर है, इस प्रश्न का महत्व और बढ़ जाता है। स्वास्थ्य व्यवस्था की चुनौतियां वास्तविक हैं और उनका समाधान भी आसान नहीं है। फिर भी दीर्घकाल में सबसे भरोसेमंद व्यवस्था वही होगी जिसमें सरकार अपनी संस्थाओं को मजबूत करे, रिक्त पद भरे, विशेषज्ञ सेवाओं का विस्तार करे और लोगों का भरोसा सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र पर कायम रखे। आखिरकार एक कल्याणकारी राज्य की पहचान केवल योजनाएं बनाने से नहीं, बल्कि अपनी सार्वजनिक संस्थाओं को सक्षम और सुलभ बनाए रखने से भी होती है।

19 जून : विश्व सिकल दिवस

सिकल सेल रोग: विश्व सिकल दिवस, सिकल सेल : समानता का हकदार

डॉ.ए.आर.दल्ला

प्रति वर्ष 19 जून को विश्व सिकल दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वर्ष 2026 के लिए एक थीम चर्चा का विषय दी है- जीवन रक्षा की खाई को भरें सिकल सेल पर समानता सुनिश्चित करें। यह दिन जीवन के प्रबंधन की गुणवत्ता में सुधार लाने और बेहतर सुविधाओं की वकालत करने का एक वैश्विक अभियान भी है। पहले इसे सिर्फ अश्वेत अफ्रीकन (नीग्रो) लोगों का रोग माना जाता था। चिकित्सा विज्ञान की प्रगति से मालूम हुआ कि यह विकृति भारत, अरब, और मेडीटेरियन अफ्रीका के अन्य देशों में भी व्याप्त है। रोजी-रोटी की तलाश में जाने वाले प्रवासी अश्वेत नीग्रों के माध्यम से यह रोग अमेरिका और यूरोप के अन्य देशों में भी पहुंचा। यहां यह जानना जरूरी है कि विश्व के विकसित और विकासशील देशों में स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर में बहुत अंतर है- इसमें आर्थिक संसाधनों की एक बड़ी कमी की समस्या भी सामने आती है। इसी संदर्भ में इस वर्ष 2026 में विश्व-स्वास्थ संगठन ने एक सामायिक थीम दी है- जीवन रक्षा की खाई को भरें। समानता सुनिश्चित करें। विश्व सिकल दिवस के अवसर विश्व समुदाय एकजुट होकर लाखों सिकल ग्रसित

परिवारों को संबल प्रदान करता है-जो इस अनुवांशिक व्याधि से व्यथित है। संयुक्त राष्ट्र संगठन ने विशेष रूप से कहता है कि सभी प्रभावित देशों एवं पंजीकृत सेवा संस्थाओं को एकजुट होकर सिकल रोग पर जन-चेतना का प्रसार और इलाज का प्रयास करना होगा। हमें सब मिलकर अनुसंधान, नवाचार और आवश्यक वित्तीय सहायता को बढ़ावा देना होगा। भारतवर्ष में सिकल सेल-वर्ष 1952 तक भारतवर्ष में इस बीमारी पर जानकारी का अभाव था। समय के साथ ज्ञात हुआ कि भारत के कुछ प्रदेशों के आदिवासी पिछड़े और वंचित लोगों का एक बड़ा वर्ग इस अनुवांशिक व्याधि से प्रभावित है। यहां यह बतलाना आवश्यक है कि विकसित और विकासशील देशों में स्वास्थ्य सेवाओं और आर्थिक बजट में एक बहुत बड़ा अन्तर है। हमें एकजुट होकर सिकल रोग से व्याधित व्यक्तियों के परिवारों को संबल और सहायता पहुंचाना है। जो इस वंशानुगत रक्त विकार के साथ जी रहे हैं। वर्ष 2026 का विश्व सिकल दिवस का दिन सिर्फ जनजागरण का दिन नही हैं

संयुक्त राष्ट्र संगठन ने विशेष रूप से कहता है कि सभी प्रभावित देशों एवं पंजीकृत सेवा संस्थाओं को एकजुट होकर सिकल रोग पर जन-चेतना का प्रसार और इलाज का प्रयास करना होगा। हमें सब मिलकर अनुसंधान, नवाचार और आवश्यक वित्तीय सहायता को बढ़ावा देना होगा। भारतवर्ष में सिकल सेल-वर्ष 1952 तक भारतवर्ष में इस बीमारी पर जानकारी का अभाव था। समय के साथ ज्ञात हुआ कि भारत के कुछ प्रदेशों के आदिवासी पिछड़े और वंचित लोगों का एक बड़ा वर्ग इस अनुवांशिक व्याधि से प्रभावित है। यहां यह बतलाना आवश्यक है कि विकसित और विकासशील देशों में स्वास्थ्य सेवाओं और आर्थिक बजट में एक बहुत बड़ा अन्तर है।

बल्कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और बेहतर सुविधाओं की वकालत के लिए एक वैश्विक अभियान भी है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के साथ ही राज्य में सिकल सेल व्याधि पर संज्ञान लिया गया। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में वर्ष 2008 को सर्वसम्मति से सिकल सेल विकृति पर नियंत्रण का संकल्प भी सर्वसम्मति से पास हुआ। रायपुर में सिकल सेल रोग पर एक अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस के आयोजन में विश्व का ध्यान आकर्षित करने का प्रस्ताव पारित कर भारत के महामहिम राष्ट्रपति को सौंपा गया। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर सिकल कार्यों को प्रगति तब मिली जब भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने इसका संज्ञान लिया। विगत वर्ष सिकल सेल विकृति की रोकथाम के लिये ह्यमिशन मोडइ पर वृहत प्रयास का प्रारंभ करते हुये, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मध्यप्रदेश के शहडोल में एक विशेष ह्यसिकल नियंत्रण केन्द्रइ की स्थापना की। प्रारंभिक तौर पर यह भारतवर्ष के 17 प्रभावित राज्य के 275 जिलों के आदिवासी क्षेत्रों में सिकल रोग सर्वेक्षण रोकथाम एव जनजागरण का प्रयास मिशन मोड में करेगा। प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2047 तक सिकल सेल व्याधि के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। आइए, हम सब मिलकर अनुसंधान, नवाचार, और आवश्यक वित्तीय सहायता को बढ़ावा देने का प्रयास करें ताकि प्रत्येक रोगी को वह गुणवत्ता पूर्ण देखभाल और उपचार मिल सके- जिसका वह हकदार है।

करो योग, रहो निरोग

योग के नियमों का पालन करने के बाद अगर यौगिक क्रियाओं को किया जाता है तो मानव में शारीरिक व मानसिक स्तर पर आश्चर्यजनक रूप से अलौकिकता का सुधार होता है। आज आधुनिकता की इस अंधी दौड़ में इनसान को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है आज भागती दौड़ती दिनचर्या में समय का बहुत अभाव है। ऐसे में हमारे शरीर की फिटनेस के लिए योग जैसा कार्यक्रम चाहिए जो कम समय में बिना कोई धन खर्च किए आसानी से उपलब्ध हो। शहर तो शहर, ग्रामीण परिवेश में भी दैनिक जीवन की भौतिक सुख-सुविधाओं का विकास तो हुआ है, मगर इस सबसे मानव फिटनेस में काफी कमी आई है। हमारा पैदल चलना अब बहुत कम हो गया है। रक्त वाहन करने वाली शिराओं के लिए कोई भी कार्यक्रम नहीं है जो उन्हें ठीक रख सके। इसलिए अच्छे फिटनेस कार्यक्रम की जरूरत भी महसूस हो रही है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। बिना अच्छे स्वास्थ्य के धन दौलत, पद प्रतिष्ठा व अन्य भौतिक सुख सुविधाएं सब बेमानी लगती हैं। लोगों का स्वास्थ्य उत्तम हो, इस सबके लिए इस कॉलम के माध्यम से बार बार योग के बारे में जानकारी देकर योग को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता रहा है। योग हर उम्र के लोग आसानी से थोड़ी सी जगह में भी कर सकते हैं। वर्तमान जीवन शैली के कारण मनुष्य के पास अपने स्वास्थ्य के लिए कोई भी कार्यक्रम नहीं है जो उनके स्वास्थ्य को सुधार कर व्यवस्थित रख सके। आज मानव ने विज्ञान में नए-नए शोध कर प्रौद्योगिकी व चिकित्सा क्षेत्र में इतनी प्रगति कर ली है कि इसके कारण जीवन काफी आसान तो हो गया है, मगर शारीरिक श्रम जो पहले यूं ही दिनचर्या में आसानी से हो जाता था, अब उसके लिए आज अलग से फिटनेस कार्यक्रम चाहिए होता है। ९समय बचाती दुनिया के लिए योग मुख्य विकल्प है, जो कम श्रम कर अधिक फिटनेस दे सकता है। इसलिए अब आम जनमानस के लिए योग के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। सैकड़ों वर्ष पूर्व महर्षि पतंजलि ने योग को लिखित रूप में संग्रहित किया और योग सूत्र की रचना की। योग सूत्र की रचना के कारण पतंजलि को योग का जनक कहा जाता है। इस योग के महान ग्रंथ में योग के बारे में कहा गया है कि मन की वृत्तियों पर नियंत्रण करना ही योग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि, यह अष्टांग योग के आठ सूत्र हैं। आठों अंगों में प्रथम दो यम व नियम को नैतिक अनुशासन, आसन, प्राणायाम व प्रत्याहार को शारीरिक अनुशासन व धारणा, ध्यान, समाधि को मानसिक अनुशासन बताया गया है।

योग हमें यम एवं नियम द्वारा व्यक्ति के मन और मस्तिष्क को ठीक करने की सलाह देता है। आसन और प्राणायाम करने से पूर्व यदि व्यक्ति यम एवं नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसे योग से पूर्ण स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल सकता है। यम और नियम की विस्तार से चर्चा जरूरी है। संयम मन, वचन और कर्म से होना चाहिए। इसका पालन न करने से व्यक्ति का जीवन व समाज दोनों दुष्प्रभावित होते हैं। इससे मन मजबूत और पवित्र होता है तथा मानसिक शक्ति बढ़ती है। सत्य, अहिंसा, असतेय, ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह यह नियम व्यक्तिगत नैतिकता के हैं। मनुष्य को कर्तव्य परायण बनाने तथा जीवन को

सुव्यवस्थित करने हेतु पांच नियमों का विधान किया गया है। ये नियम हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय व ईश्वर प्राणिधान। यम यानी मन, वचन एवं कर्म से सत्य का पालन व मिथ्या का त्याग। जिस रूप में देखा, सुना एवं अनुभव किया हो उसी रूप में उसे बतलाना सत्य है। अहिंसा दूसरा सूत्र है। इसमें किसी को मारना ही केवल हिंसा का रूप नहीं है, बल्कि किसी भी प्राणी को कभी भी किसी प्रकार का दुख न पहुंचाना अहिंसा है।असतेय अर्थात चोरी न करना। छल से, धोखे से, झूठ बोलकर, बेईमानी से किसी चीज को प्राप्त करना भी चोरी है। जिस पर अपना अधिकार नहीं, उसे लेना भी इसी श्रेणी में आता है। ब्रह्मचर्य : मन वचन एवं कर्म से यौन संयम अथवा मैथुन का सर्वथा त्याग करना ब्रह्मचर्य है। सभी इंद्रिय जनित सुखों में संयम बरतना। अपरिग्रह : अपने स्वार्थ के लिए धन, संपत्ति एवं भोग की सामग्री में संयम न बरतना परिग्रह है। इसका अभाव अपरिग्रह है। आवश्यकता से अधिक संचय करना अपरिग्रह है। दूसरों की वस्तुओं की इच्छा न करना। मन, वचन एवं कर्म से इस प्रवृत्ति को त्यागना ही अपरिग्रह है। नियमों में शौच के अंतर्गत पानी मिट्टी आदि के द्वारा शरीर, वस्त्र, भोजन, मकान आदि के मल को दूर करना बाह्य शुद्धि माना जाता है। सद्भावना, मैत्री, करुणा आदि से की जाने वाली शुद्धि आंतरिक शुद्धि मानी जाती है। केवल अपने भौतिक शरीर का ध्यान रखना पर्याप्त नहीं है। बल्कि अपने मन के विचारों को पहचान कर उन्हें दूर करने का प्रयास करना जरूरी है। शरीर और मन दोनों की शुद्धि। संतोष दूसरा नियम है। इसमें कत्र्तव्य का पालन करते हुए जो कुछ उपलब्ध हो, जो कुछ प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहना। किसी प्रकार की तृष्णा न करना। तीसरा नियम है तप, इस नियम में अपने वर्ण, आश्रम, परिस्थिति और योग्यता के अनुसार स्वधर्म का पालन करना। व्रत, उपवास आदि भी इसी में शामिल किया जाता है। यानी कि स्वयं से अनुशासित दिनचर्या में रहना है। स्वाध्याय चौथा नियम है। जिससे कत्र्तव्य का बोध हो सके, मतलब शास्त्र का अध्ययन करना। महापुरुषों के वचनों का अनुपालन भी स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। ईश्वर प्राणिधान पांचवां नियम है। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण व संपूर्ण श्रद्धा रखना। फल की इच्छा का परित्याग पूर्वक समस्त कर्मों का ईश्वर को समर्पण करना ईश्वर प्राणिधान कहलाता है। हजारों साल पहले भारतीय शोधकताओं ने योग की क्रियाओं से होने वाले लाभों को समझ लिया था जो आज की चिकित्सा व खेल विज्ञान में योग का प्रयोग खूब हो रहा है। योग के नियमों का पालन करने के बाद अगर यौगिक क्रियाओं को किया जाता है तो मानव में शारीरिक व मानसिक स्तर पर आश्चर्यजनक रूप से अलौकिकता का सुधार होता है। आज आधुनिकता की इस अंधी दौड़ में इनसान को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। आज जब मनुष्य के पास हर सुख सुविधा आसानी से उपलब्ध है, मगर समय का अभाव सब के सामने है, ऐसे में फिटनेस को बनाए रखने के लिए योग सबसे बढिया है जो प्रतिदिन आधा घंटा देकर उत्तम स्वास्थ्य दे सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि करो योग, रहो निरोग।

मोदी-ट्रम्प भेंट

भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बीच बहुप्रतीक्षित द्विपक्षीय मुलाकात फ्रांस में हुई। अवसर था- जी-7 शिखर सम्मेलन का जिसमें भारत को ब्राजील, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया के साथ विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। दोनों ने एक दूसरे की हमेशा की तरह प्रशंसा की परन्तु भारत-अमेरिका के बीच जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन पर कोई खास प्रगति होती नहीं दिखी। इसलिये इसका हासिल भारत को क्या होगा- यह फिलहाल सामने आना है, लेकिन इस मायने में भेंट को महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि करीब डेढ़ वर्ष बाद दोनों की मुलाकात ढीले पड़ चुके सम्बन्धों की नयी शुरूआत कही जा सकती है। उभय देशों के बीच कई तरह के मसले हैं जिन पर स्पष्ट बात न होना या कम से कम उनका सार्वजनिक न करना, इस वार्ता को संदेहों के घेरों से नहीं निकाल पायेगा। इसलिये भारत सरकार स्पष्ट करे कि इस बातचीत का आखिर हासिल क्या है और वह किस तरह से भारत के पक्ष में है। मुलाकात में क्या हुआ, इसकी सारी जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति ने ही दी। मोदी पूरे वक्त उनकी बगल में तो बैठे रहे परन्तु उन्होंने ट्रम्प के बयान में न कोई शब्द जोड़ा, न कहीं सफाई दी अथवा मुद्दे को विस्तार देने की जरूरत समझी। हालांकि ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है जब मोदी किसी अन्य देश के प्रमुख से मिले परन्तु अपनी ओर से पत्रकारों के किसी सवाल का जवाब दिया हो। भारत का नजरिया जो मोदी या कोई भारतीय कूटनीतिज्ञ स्पष्ट कर सकता है, वह भला दूसरे देश का प्रमुख किस प्रकार विश्व मीडिया के आगे रख पाएगा। इसलिये ऐसी मुलाकातों के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय या उस देश के भारतीय दूतावास से जारी प्रेस बयानों से ऐसी भेंट का निष्कर्ष सामने आ पाता है। भारत में मोदी-ट्रम्प की मुलाकात का सिर्फ इसलिये बेसब्री से इंतजार नहीं था कि यह दोनों के बीच लम्बे समय बाद होने वाली द्विपक्षीय वार्ता थी, बल्कि अनेक ऐसे मुद्दे इस समय हैं जो परस्पर रिश्तों को प्रभावित कर रहे हैं- इनमें से ज्यादातर तो भारत के लिये तल्खी लाने वाले ही हैं। सबसे ताजा मुद्दा है कुछ दिन पहले विवादग्रस्त होर्मुज स्ट्रेट के पास तीन भारतीय नाविकों की अमेरिकी गोलाबारी से मौत। उस मामले को भारत सरकार की ओर से मजबूत तरीके से तो क्या औपचारिक रूप से भी अमेरिका के सामने नहीं उठाया गया था। स्वयं नरेन्द्र मोदी ने इस पर एक वाक्य का तक बयान नहीं दिया। हालांकि एक पत्रकार द्वारा इस बाबत पूछे गये सवाल पर ट्रंप ने कह दिया कि, ह्यनाविकों का पेशा खतरे से भरा होता ही है। यह भारतीयों के लिये वैसे ही निराशाजनक रहा जिस प्रकार करीब दो-ढाई साल पहले अमेरिका ने भारत से डंकी रूट से गये लोगों की हथकड़ियां और कमर में जंजीरें बांधकर वायु सेना के जहाजों में गुलामों की तरह वापस भेज दिया था। इस मामले को लेकर देश भर में लोगों में दुख और उग्रता थी। भारत सरकार की ओर से विरोध में कोई बयान तक नहीं दिया गया। उल्टे विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर अमेरिका के इस कदम को यह कहकर तर्कसंगत बताया था कि हर देश के इमिग्रेशन सम्बन्धी कुछ नियम होते हैं। इस बातचीत के दौरान ऐसे कोई संकेत या साझा बयान देखने को नहीं मिल रहे हैं जो उन बिन्दुओं को स्पष्ट करे जिनका सम्बन्ध हाल के कुछ घटनाक्रमों से है। पाकिस्तान के साथ हुए ऑपरेशन को रोकने का श्रेय अमेरिकी राष्ट्रपति कई बार सार्वजनिक रूप से ले चुके हैं। उन्होंने न जाने कितनी बार कहा कि उन्होंने मोदी को निर्देश देकर यह रूकवाया था। जबकि इधर भारत में मोदी और उनकी सरकार का दावा रहा है कि लड़ाई को खुद भारत ने रोका था। इसके अलावा लम्बे समय तक ट्रम्प द्वारा दोनों देशों के बीच टैरिफ-टैरिफ का खेल खेला गया था।

दिल्ली सरकार ने शीतकालीन वायु गुणवत्ता प्रबंधन व्यवस्था को किया अधिसूचित

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए शीतकालीन वायु गुणवत्ता प्रबंधन व्यवस्था अधिसूचित कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि अब सरकार सर्दियों की शुरुआत से कई महीने पहले ही यह स्पष्ट कर रही है कि नवंबर से फरवरी के दौरान प्रदूषण बढ़ने की स्थिति में कौन-कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, किन व्यवस्थाओं को लागू किया जा सकता है और विभिन्न क्षेत्रों से क्या अपेक्षाएं रहेंगी। इससे नागरिकों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों (आरडब्ल्यूए), उद्योगों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, निर्माण एजेंसियों और सरकारी विभागों को अग्रिम योजना बनाने और आवश्यक तैयारियां करने का पर्याप्त समय मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को एक विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि दिल्ली में पिछले कई वर्षों से नवंबर से फरवरी के बीच वायु गुणवत्ता गंभीर रूप से प्रभावित होती रही है और एअर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) अक्सर 'बहुत खराब' और 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच जाता है। यह हालात हर वर्ष पैदा हो रहे हैं, इसलिए दिल्ली सरकार ने केवल आपातकालीन प्रतिक्रिया पर निर्भर रहने के बजाय अग्रिम तैयारी, समयबद्ध हस्तक्षेप और बेहतर समन्वय पर आधारित रणनीति अपनाई है। यह फ्रेमवर्क पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित किया गया है और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा जारी संशोधित ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) के पूरक के रूप में कार्य करेगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी विभाग और एजेंसियां सर्दियों के महीनों में निरंतर तैयार रहें और प्रदूषण नियंत्रण उपाय प्रतिकूल परिस्थितियों के आने से पहले ही लागू किए जा सकें न कि केवल ग्रैप लागू होने के बाद। मुख्यमंत्री ने बताया कि अधिसूचित व्यवस्था के तहत दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों पर केवल उन्हीं वाहनों को ईंधन मिलेगा, जिनके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) होगा। इसके अतिरिक्त 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर बीएस-VI डीजल वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। लेकिन सीएनजी, इलेक्ट्रिक, आपातकालीन सेवाओं और सरकारी कार्यों से जुड़े वाहनों को इस व्यवस्था से छूट दी जाएगी। सर्दियों के दौरान वायु गुणवत्ता सुधारने और निजी वाहनों के अत्यधिक उपयोग को कम करने के उद्देश्य से 1 नवंबर से 28 फरवरी तक अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने कह कि यातायात दबाव कम करने, आवागमन को अधिक व्यवस्थित बनाने और प्रदूषण नियंत्रण प्रयासों को प्रभावी बनाने के लिए चरणबद्ध कार्यालय समय की व्यवस्था लागू की जाएगी। इस व्यवस्था के तहत सरकारी व निजी कार्यालयों में अधिकतम 50 प्रतिशत भौतिक उपस्थिति संबंधी प्रावधान लागू रहेंगे और शेष कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से कार्य कर सकेंगे। आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं को इससे छूट रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण और ध्वस्तीकरण गतिविधियां शहरी विकास के लिए आवश्यक हैं, लेकिन सर्दियों के दौरान धूल प्रदूषण को नियंत्रित करना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए परियोजना संचालकों, ठेकेदारों और नागरिकों को अपनी गतिविधियों की योजना पहले से तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है ताकि अत्यधिक प्रदूषण वाले समय में अतिरिक्त प्रदूषण भार न बढ़े। इसी के मद्देनजर 1 नवंबर से 31 जनवरी तक निर्माण एवं ध्वस्तीकरण गतिविधियों को निर्धारित पर्यावरणीय मानकों और धूल नियंत्रण उपायों के अनुरूप संचालित करना होगा। विशेष रूप से 10 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच, जब प्रदूषण का स्तर अधिक रहने की संभावना होती है, तब जनस्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के हित में निर्माण एवं ध्वस्तीकरण गतिविधियों पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आवश्यक और आपातकालीन परियोजनाओं को इससे छूट दी जा सकती है। उच्च प्रदूषण अवधि के दौरान निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही को भी विनियमित (रेगुलेट) किया जा सकता है। साथ ही, बड़े वाणिज्यिक ऊंचे भवनों और प्रमुख निर्माण स्थलों पर एंटी-स्मॉग गन, मिस्ट सप्रेशन सिस्टम और अन्य धूल नियंत्रण उपायों की स्थापना एवं संचालन अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए खुले में कचरा, पत्तियां या अन्य सामग्री जलाने की घटनाओं पर रोक लगाना अत्यंत आवश्यक है। सभी आरडब्ल्यूए, संस्थानों, प्रतिष्ठानों, ठेकेदारों और एजेंसियों को अपने क्षेत्रों में खुले में जलाने की गतिविधि को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे।

साइबर ठगी के शिकार 34 लोगों को मिली राहत, एमआरएम के जरिए लौटाए गए 3.59 लाख रुपये

नई दिल्ली। साइबर ठगी के शिकार लोगों को राहत पहुंचाने के लिए मध्य रेंज पुलिस ने मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल (एमआरएम) के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) के सहयोग से अब तक 34 मामलों में साइबर ठगी के पीड़ितों को कुल 3,59,178 रुपये वापस दिलाए गए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, एमआरएम एक विशेष व्यवस्था है, जिसे गृह मंत्रालय के तहत कार्यरत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) ने विकसित किया है। इसका उद्देश्य साइबर ठगी के मामलों में बैंकिंग हस्तक्षेप के जरिए सुरक्षित की गई 50 हजार रुपये तक की राशि को पीड़ितों को जल्द वापस दिलाना है। संयुक्त पुलिस आयुक्त (मध्य रेंज) मधुर वर्मा ने बताया कि इस प्रणाली के तहत प्राप्त होने वाले मामलों का निस्तारण तय प्रक्रिया और समय-सीमा के भीतर किया जाता है, ताकि पीड़ितों को जल्द से जल्द आर्थिक राहत मिल सके।

पुलिस के अनुसार, पिछले सप्ताह तक आई4सी की ओर से मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल के तहत कुल 70 अनुरोध प्राप्त हुए थे। इनमें से 34 मामलों में आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर उनका सत्यापन किया गया और उन्हें एमआरएम पोर्टल पर अपलोड किया गया। इसके बाद संबंधित पीड़ितों को कुल 3,59,178 रुपये की राशि वापस दिलाई गई। हालांकि, 22 मामलों में बहाली की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि शिकायतकर्ता बार-बार संपर्क करने और याद दिलाने के बावजूद पुलिस थाने नहीं पहुंचे। शेष मामलों में आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। पुलिस के मुताबिक, एमआरएम से जुड़े अनुरोध आई4सी की ओर से आधिकारिक ई-मेल के माध्यम से साझा किए जाते हैं। अनुरोध मिलने के बाद संबंधित पीड़ित से फोन पर संपर्क कर पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी जाती है। राशि बहाल कराने के लिए शिकायतकर्ता को स्वयं पुलिस थाने पहुंचना अनिवार्य होता है। इसके लिए उसे 10 रुपये के स्टांप पेपर और पैन कार्ड की प्रति साथ लानी होती है। थाने में शिकायतकर्ता की पहचान सत्यापित की जाती है और निर्धारित प्रारूप में क्षतिपूर्ति बांड (इंडेम्निटी बॉन्ड) भरवाया जाता है। सभी दस्तावेजों की जांच के बाद उन्हें एमआरएम पोर्टल पर अपलोड किया जाता है, जिसके बाद सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी मिलने पर राशि बहाल की जाती है। पुलिस ने बताया कि साइबर ठगी के पीड़ितों को जल्द राहत पहुंचाने के लिए एमआरएम से जुड़े मामलों की निगरानी के लिए एक समर्पित कर्मचारी को विशेष रूप से नियुक्त किया गया है। यह कर्मचारी शिकायतकर्ताओं से संपर्क करने, दस्तावेज जुटाने, मामलों की प्रगति पर नजर रखने और पोर्टल पर आवश्यक जानकारी अपलोड करने की जिम्मेदारी निभा रहा है।

कांग्रेस ने राहुल गांधी के जन्मदिन पर मेगा रोजगार मेले का किया आयोजन

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन पर तालकटोरा स्टेडियम में मेगा रोजगार मेला का आयोजन किया। इस मेले में 150 से अधिक अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों ने अपने-अपने स्टाल लगाकर युवाओं के साक्षात्कार करके उनकी योग्यता अनुसार मौके पर ही 6500 से अधिक युवाओं को नौकरी के लिए नियुक्त किया। कंपनियों ने सैंकड़ों युवाओं को दूसरे साक्षात्कार के लिए भी बुलाया है। यह जानकारी प्रदेश कांग्रेस ने विज्ञप्ति जारी करके दी।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि बेरोजगारी युवाओं को रोजगार मेले के के जरिए नौकरी दी गई। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को पेपर लीक की समस्या का स्थायी समाधान मिलना चाहिए, इसके लिए सरकार कानूनी तरीका अपना कर युवाओं को पेपर लीक की समस्या से निजात दे। देवेंद्र यादव ने कहा कि जब विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस हजारों युवाओं को रोजगार देने का काम कर सकती है, तो सत्ता में आने पर निश्चित ही देश के करोड़ों युवाओं को उनकी शैक्षणिक योग्यता अनुसार रोजगार देकर फिर एक बार देश से बेरोजगारी को पूरी खत्म करने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हमेशा सरकारी विभागों में खाली पड़े लाखों पदों को भरने की मांग केंद्र सरकार से लगातार करते रहे है। मेगा रोजगार मेले में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव, राष्ट्रीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानू चिब, दिल्ली प्रभारी काजी निजामुद्दीन मौजूद रहे।

दिल्ली के पहले महिला पुलिस स्टेशन का शुभारंभ

नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने शुक्रवार को उत्तरी दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पहले महिला पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया। इस कदम का मकसद महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करना और उनके ख़िलाफ होने वाले अपराधों से निपटने के तरीके को बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि सुरक्षित और सशक्त महिला ही प्रगतिशील समाज की नींव होती है। इस मौके पर दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा, पुलिस अधिकारी और महिला पुलिस स्टेशन की एसएचओ लक्ष्मी सिंह मौजूद रहीं।

उपराज्यपाल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इस विजन से प्रेरित होकर कि 'नारी शक्ति' ही राष्ट्र-निर्माण की आधारशिला है, यह महत्वपूर्ण संस्थान महिलाओं को बिना किसी डर के अपनी शिकायतें दर्ज कराने, न्याय पाने और सहायता प्राप्त करने के लिए एक सहयोगी और सुरक्षित वातावरण प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस की महिला-सुरक्षा से जुड़ी प्रमुख पहलों, जैसे 'पिंक बूथ' और 'सशक्ति' अभियान की भी समीक्षा की। पुलिस बल को राजधानी में ऐसे और केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए, ताकि महिला-अनुकूल पुलिसिंग और तत्परता से कानून लागू करने की दिशा में एक नया मानक स्थापित किया जा सके। उपराज्यपाल ने कहा कि एक सुरक्षित और सशक्त महिला ही प्रगतिशील समाज की नींव होती है। हम सब मिलकर एक सुरक्षित, समावेशी और सशक्त विकसित दिल्ली के निर्माण की दिशा में काम करते रहेंगे। अगर हम कोई अपराध होते या अपनी माताओं, बहनों और परिवार के साथ अन्याय होते देखें तो जरूर आवाज उठाएं या पुलिस को सूचित करें। यह एक ऐसा सीधा जरिया है जो महिलाओं के खिलाफ होने वाले किसी भी अपराध से सीधे निपटेगा।

पॉक्सो मामले में फरार आरोपित उत्तराखंड से गिरफ्तार

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली की वेलकम थाना पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के एक मामले में फरार चल रहे आरोपित को उत्तराखंड से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित पर युवती को हथियार के बल पर धमका कर दुष्कर्म करने, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और लगातार पीछा करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार चार अप्रैल 2026 को 21 वर्षीय युवती ने वेलकम थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि वर्ष 2023 में आरोपित ने पिस्तौल दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। आरोपित ने घटना का वीडियो भी बना लिया और उसे वायरल करने की धमकी देकर लंबे समय तक उसका यौन शोषण करता रहा। आरोप है कि वह युवती का ट्यूशन जाते समय पीछा करता था और उसके साथ-साथ परिवार के सदस्यों को भी गंभीर परिणाम भुगतने की धमकियां देता था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)(एम), 78, 351(3) और 126(2) के तहत मामला दर्ज किया। जांच के दौरान पता चला कि घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी। इसके बाद मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा-6 भी जोड़ दी गई।

मामला दर्ज होने के बाद से आरोपित फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई संभावित ठिकानों पर छापेमारी की। तकनीकी निगरानी, कॉल डिटेल रिकॉर्ड विश्लेषण, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और स्थानीय मुखबिरों की मदद से आरोपी की तलाश की जा रही थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी हासिल किए थे और उसे घोषित अपराधी घोषित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी। एसीपी भजनपुरा सहदेव कुमार राणा की निगरानी और थाना प्रभारी रूपेश कुमार खत्री के नेतृत्व में एएसआई बिजेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल हरेंद्र कुमार, कुलदीप और ललित, कांस्टेबल लोकेश तथा महिला कांस्टेबल शिवानी की टीम ने लगातार प्रयास किए। पुलिस को मिली विशेष सूचना के आधार पर टीम ने उत्तराखंड के भगवानपुर में छापेमारी कर 26 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी वेलकम इलाके का रहने वाला है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपित पहले भी गैर इरादतन हत्या और जुआ अधिनियम से जुड़े मामलों में संलिप्त रह चुका है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।

महापौर ने मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम एवं जन जागरूकता का प्रचार करने के लिए ऑटो रैली को किया रवाना

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने शुक्रवार को मच्छर जनित बीमारियों को रोकथाम एवं उनके प्रति जन जागरूकता का प्रचार करने के लिए ऑटो रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर 450 कर्मियों सहित 100 ऑटो रिक्शा को रवाना किया गया। प्रत्येक ऑटो रिक्शा पर महापौर का मच्छर जनित बीमारियों से बचाव हेतु किए जाने वाले उपायों का संदेश प्रसारित किया जाएगा एवं ऑटोरिक्शा पैम्फलेट,बैनर एवं फॉगिंग मशीन से लैस किए गए हैं। महापौर प्रवेश वाही ने बताया कि आज सिविक सेंटर स्थित दिल्ली नगर निगम के मुख्यालय से ऑटो रिक्शा रैली का शुभारंभ किया है जो नगर निगम के प्रत्येक 250 वार्डों में जाएगी। उन्होंने कहा कि यह ऑटो रिक्शा फॉगिंग मशीन एवं जन जागरूकता सामग्री जैसे मच्छर जनित बीमारियों से बचने के तरीके बताने वाले संदेश, पैम्फलेट एवं बैनर प्रसारित करेगी।

प्रवेश वाही ने कहा कि मच्छर जनित बीमारियों के लिए निगम द्वारा किए जा रहे प्रयासों एवं फील्ड विजिट के अतिरिक्त यह रैली आयोजित की जा रही है। इस अवसर पर महापौर द्वारा फॉगिंग अभियान का भी शुभारंभ किया गया। प्रवेश वाही ने कहा कि नरेन्द्र मोदी के देश के प्रधानमंत्री के रूप में 12 वर्ष पूर्ण करने के उपलक्ष में नगर निगम द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में आज मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए इस ऑटो रिक्शा रैली का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि इस रैली का आदर्श वाक्य 'जीतेगी दिल्ली हारेगा डेंगू मलेरिया' महज एक नारा न होकर हमारी प्रतिबद्धता है। महापौर ने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी को बेहतर शहर बनाने के लिए संकल्पित है और नगर निगम उनके इस संकल्प को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। महापौर ने दिल्ली की जनता से मच्छर जनित बीमारियों से बचाव एवं रोकथाम के लिए त्रिस्तरीय प्रयास करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह त्रिस्तरीय प्रयास है ढको, साफ करो, सूखा रखो। उन्होंने कहा कि हमें अपने घरों में पानी के पात्रों एवं टंकियों को ढक कर रखना है। अपने आस-पास सफाई रखनी है क्योंकि मच्छर गंदगी में पनपते हैं और इसके साथ ही अपने आस पास पानी इकठ्ठा नहीं होने देना एवं अपने आस पास की जगह को सूखा रखना है। इस अवसर पर दिल्ली नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त डॉ सतेंद्र सिंह दुर्सावत, निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अशोक रावत, डॉ लल्लन राम वर्मा एवं दिल्ली नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।

स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने नागरिकों से अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग से जुड़ें रहने की अपील की

नई दिल्ली। 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के मुख्यालय, सिविक सेंटर के प्रांगण में शुक्रवार को योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर निगम की इस वर्ष के योग दिवस की थीम 'योग फॉर हेल्दी एजिंग' है। इस अवसर पर एमसीडी की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा, एमसीडी में आयुष विभाग के निदेशक हरीश कश्यप एवं दिल्ली नगर निगम के अधिकारी उपस्थित रहे।

योग सत्र का शुभारंभ प्रात:काल सूर्य नमस्कार से हुआ, जिसके उपरांत विभिन्न योगासन, प्राणायाम और ध्यान क्रियाएं कराई गईं। इस अवसर पर स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने योगाभ्यास भी किया। इस अवसर पर स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने नागरिकों से अपील की कि वो अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग से जुड़ें एवं अपने परिवारों को भी जोड़ें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अथक प्रयासों की वजह से योग को अंतरराष्ट्रीय पटल पर ख्याति मिली है एवं विश्व के 180 से भी ज्यादा देशों में योग को नई पहचान मिली है। सत्या शर्मा ने कहा कि योग हमारी संस्कृति एवं परंपरा से जुड़ा प्राचीन शास्त्र है। सभी रोजमर्रा की दिनचर्या का हिस्सा बना कर अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में आयोजित कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों में योग के प्रति जागरूकता फैलाना और स्वस्थ जीवनशैली को प्रोत्साहित करना था। उन्होंने कहा कि नगर निगम योग के प्रचार एवं प्रसार के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है एवं नागरिकों के मध्य इसे लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयासरत है।

एमसीडी के प्राथमिक विद्यालयों में तारामंडल एवं प्रधानमंत्री संग्रहालय भ्रमण कार्यक्रम का शुभारंभ

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने शुक्रवार को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए तारामंडल एवं प्रधानमंत्री संग्रहालय भ्रमण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि दिल्ली नगर निगम विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि विद्यार्थियों को व्यावहारिक एवं अनुभवात्मक शिक्षा के अवसर भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इसी उद्देश्य से निगम विद्यालयों के विद्यार्थियों को तारामंडल एवं प्रधानमंत्री संग्रहालय का भ्रमण कराया जा रहा है।

महापौर ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को तारामंडल की विशेषताओं, अंतरिक्ष विज्ञान की रोचक जानकारियों तथा विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में भारत की निरंतर प्रगति के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति बच्चों में जिज्ञासा और वैज्ञानिक सोच विकसित करना समय की आवश्यकता है। साथ ही प्रधानमंत्री संग्रहालय के भ्रमण से विद्यार्थियों को देश के सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान, उनके नेतृत्व में हुए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विकास कार्यों तथा भारत की प्रगति की ऐतिहासिक यात्रा को समझने में सहायता मिलेगी। महापौर ने कहा कि दिल्ली नगर निगम भविष्य में भी विद्यार्थियों के लिए इस प्रकार के शैक्षणिक, प्रेरणादायक एवं ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का आयोजन निरंतर करता रहेगा, ताकि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ व्यापक ज्ञान और अनुभव भी प्राप्त हो सके।

दिल्ली नगर निगम की शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा ने बताया कि नगर निगम देश की पहली ऐसी शैक्षणिक संस्था बनी है जिसने प्रधानमंत्री के इस संदेश को धरातल पर उतारते हुए निगम विद्यालयों के बच्चों को तारामंडल का भ्रमण कराने की पहल की है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को प्रधानमंत्री संग्रहालय भी दिखाया गया, जहां भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन, उनके योगदान और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका से संबंधित विस्तृत एवं प्रेरणादायक जानकारी उपलब्ध है। योगेश वर्मा ने कहा कि निगम विद्यालयों में अध्ययनरत अधिकांश विद्यार्थी ऐसे परिवारों से आते हैं जिनकी पहुंच सामान्यत: इस प्रकार के ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक कार्यक्रमों तक नहीं हो पाती। ऐसे में यह भ्रमण उनके लिए एक अनूठा और अविस्मरणीय अनुभव सिद्ध हुआ है। इस शैक्षणिक यात्रा के माध्यम से बच्चों को विज्ञान, अंतरिक्ष अनुसंधान, तकनीकी विकास और भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के बारे में नई जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। उन्होंने बताया कि यह संपूर्ण कार्यक्रम एसएएआरडी संस्था के सहयोग से आयोजित किया गया है, जिसके कारण दिल्ली नगर निगम पर किसी प्रकार का वित्तीय भार नहीं आया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के अंतर्गत आज 200 विद्यार्थियों को तारामंडल एवं प्रधानमंत्री संग्रहालय का भ्रमण कराया गया, जबकि आगामी दिवस पर भी 200 विद्यार्थियों को इस शैक्षणिक यात्रा में शामिल किया जाएगा। सभी विद्यार्थियों के लिए नि:शुल्क परिवहन, भ्रमण एवं रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। योगेश वर्मा ने कहा कि यह कार्यक्रम केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि एक अत्यंत आकर्षक, प्रेरणादायक एवं ज्ञानवर्धक पहल है। इस दौरान बच्चों ने चित्रों, प्रदर्शनों, डिजिटल माध्यमों तथा वैज्ञानिक प्रस्तुतियों के जरिए अनेक नई जानकारियां प्राप्त कीं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं राष्ट्रीय चेतना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अंत में योगेश वर्मा ने सुधीर भटनागर एसएएआरडी एनजीओ तारामंडल के अधिकारी रवि किरण व प्रेरणा एवं अन्य अधिकारियों का इस सफल आयोजन में सहयोग हेतु धन्यवाद व्यक्त किया।

ऑपरेशन विश्वास : 15 दिन में 168 खोए मोबाइल बरामद, बिहार-उप्र समेत कई राज्यों से तलाशकर 88 फोन मालिकों को लौटाए

नई दिल्ली, एजेंसी। मध्य जिला पुलिस ने तकनीक आधारित पुलिसिंग और अंतरराज्यीय समन्वय का बेहतरीन उदाहरण पेश करते हुए 'ऑपरेशन विश्वास' के तहत महज 15 दिनों में 168 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बरामद मोबाइल फोन में से 88 हैंडसेट को अनब्लॉक कर स्वामित्व सत्यापन के बाद उनके असली मालिकों को सौंप दिया गया। पुलिस का कहना है कि इस विशेष अभियान ने न केवल लोगों को उनके महंगे मोबाइल वापस दिलाए, बल्कि उनमें मौजूद महत्वपूर्ण निजी और पेशेवर डेटा को भी सुरक्षित लौटाने में अहम भूमिका निभाई है।

पुलिस की ओर से शुक्रवार को जारी बयान के अनुसार यह अभियान वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में चलाया गया। इसका उद्देश्य खोए हुए मोबाइल फोन को तकनीकी सहायता और समन्वित पुलिसिंग के जरिए ट्रेस कर उन्हें उनके वास्तविक मालिकों तक पहुंचाना था। ऑपरेशन विश्वास के तहत केंद्रीय जिले की स्पेशल स्टाफ टीम और सभी थानों के नामित नोडल अधिकारियों ने संयुक्त रूप से काम किया। टीमों ने खोए हुए मोबाइल फोन से संबंधित शिकायतों का विश्लेषण किया और प्रत्येक मामले में लगातार फॉलोअप किया। मोबाइल फोन की बरामदगी में तकनीकी विश्लेषण और डिजिटल ट्रैकिंग ने अहम भूमिका निभाई। पुलिस ने उपलब्ध तकनीकी संसाधनों और विश्लेषणात्मक उपकरणों की मदद से मोबाइल फोन की लोकेशन, उनकी गतिविधियों और वर्तमान उपयोगकर्ताओं की पहचान की। जांच के दौरान हर सुराग की बारीकी से पड़ताल की गई। पुलिस के अनुसार कई मोबाइल फोन एक से अधिक लोगों के हाथों में पहुंच चुके थे और दिल्ली से बाहर विभिन्न राज्यों में इस्तेमाल किए जा रहे थे। इसके बावजूद पुलिस टीमों ने लगातार तकनीकी निगरानी और स्थानीय पुलिस इकाइयों के सहयोग से मोबाइल फोन का पता लगाया। जांच में सामने आया कि खोए हुए मोबाइल फोन बिहार, उप्र और देश के अन्य हिस्सों में पहुंच चुके थे। ऐसे में केंद्रीय जिला पुलिस ने संबंधित राज्यों की स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर बरामदगी अभियान चलाया। अंतरराज्यीय सहयोग और लगातार फील्ड वर्क के चलते 168 मोबाइल फोन बरामद करने में सफलता मिली। पुलिस ने बताया कि बरामद किए गए सभी मोबाइल फोन का स्वामित्व सत्यापित किया गया। आवश्यक दस्तावेजों और औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद 88 मोबाइल फोन को सफलतापूर्वक अनब्लॉक किया गया और उनके असली मालिकों को सौंप दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि कई मोबाइल फोन सीईआईआर (सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर) पोर्टल पर ब्लॉक किए गए थे, जिन्हें बरामदगी के बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत दोबारा सक्रिय किया गया। पुलिस के मुताबिक बरामद मोबाइल फोन में केवल महंगे उपकरण ही नहीं, बल्कि लोगों का महत्वपूर्ण व्यक्तिगत और पेशेवर डेटा भी सुरक्षित था। इनमें बैंकिंग एप्लीकेशन, वित्तीय जानकारी, व्यावसायिक दस्तावेज, व्यक्तिगत तस्वीरें, संपर्क सूची और परिवार से जुड़ी अनमोल यादें शामिल थीं। मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने पुलिस टीमों के प्रयासों की सराहना की और कहा कि फोन के साथ उनका महत्वपूर्ण डेटा भी सुरक्षित लौट आया, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली है।

सिकल सेल रोग जनजातीय समाज के सामाजिक-आर्थिक विकास से जुड़ी गंभीर चुनौती : मंगुभाई पटेल

- ओंकारेश्वर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के मुख्यमंत्री में विश्व सिकल सेल दिवस पर हुआ भव्य कार्यक्रम

भोपाल। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि सिकल सेल रोग केवल स्वास्थ्य की समस्या नहीं, बल्कि विशेष रूप से जनजातीय समाज के सामाजिक और आर्थिक विकास से जुड़ी गंभीर चुनौती है। राज्यपाल पटेल शुक्रवार को खण्डवा जिले के ओंकारेश्वर में विश्व सिकल सेल दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के मुख्य आतिथ्य में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सिकल सेल उन्मूलन को राष्ट्रीय मिशन का स्वरूप दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वर्ष 2023 में शहडोल से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन-2047 का शुभारंभ किया गया। मध्य प्रदेश में इस अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ संचालित किया जा रहा है।राज्यपाल पटेल ने बताया कि मध्य प्रदेश में अब तक एक करोड़ 32 लाख से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है और लगभग 95 से 96 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। आगामी दो से तीन महीनों में शेष कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। इस अभियान ने जनजातीय क्षेत्रों में बीमारी के प्रति जागरूकता और सतर्कता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में एलोपैथिक उपचार के साथ आयुर्वेदिक दवाओं के उपयोग पर भी कार्य किया जा रहा है और इसके प्रारंभिक परिणाम सकारात्मक रहे हैं। उन्होंने सिकल सेल रोगियों से अपील की कि उपचार में दोनों पद्धतियों का समन्वित उपयोग करें। उन्होंने डिजिटल जेनेटिक कार्ड को विवाह संबंधों के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि यह जन्म कुंडली की तरह उपयोगी है और विवाह से पूर्व इसका मिलान आवश्यक है। इससे भावी पीढ़ियों को इस आनुवंशिक बीमारी से बचाया जा सकेगा।

सिकल सेल उन्मूलन मिशन भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का संकल्प : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आदि शंकराचार्य की तपोभूमि और जननायक टंट्या मामा की कर्मस्थली पर आयोजित यह कार्यक्रम केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का संकल्प है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन से जनजागरूकता बढ़ाकर इस गंभीर बीमारी की रोकथाम की दिशा में देश और प्रदेश मिलकर कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान आने वाली पीढ़ियों को सिकल सेल जैसी घातक बीमारी से बचाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि इस बीमारी का प्रभाव केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरा परिवार और कई पीढ़ियां इसकी पीड़ा झेलती हैं। इसलिए इसे रोकना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राष्ट्रपति मुर्मु की उपस्थिति को प्रेरणादाई बताते हुए उनका अभिनंदन किया और कहा कि उनके सान्निध्य में यह संकल्प और अधिक मजबूत हुआ है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वर्ष 2023 में शहडोल से शुरू किए गए राष्ट्रीय सिकल सेल मिशन का उल्लेख करते हुए कहा कि आज यह अभियान राष्ट्रीय स्तर पर जनआंदोलन का रूप ले चुका है।मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश में गर्भवती महिलाओं की पहचान कर परामर्श, जेनेटिक कॉउंसलिंग और सिकल सेल कार्ड वितरण जैसे कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। प्रदेश में 3700 से अधिक सिकल मित्र भी जन-जागरूकता के इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार मजबूत कर रही है। उन्होंने बताया कि जहां पहले प्रदेश में केवल पांच मेडिकल कॉलेज थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 32 तक पहुंच रही है। आयुर्वेदिक चिकित्सा शिक्षा में भी तेजी से विस्तार किया जा रहा है।मुख्यमंत्री ने जनजातीय विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि खरगौन में क्रांतिसूर्य टंट्या मामा के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना कर राज्य सरकार विकास के सभी पैमाने पर आगे बढ़ रही है। वीरांगना रानी दुर्गावती और राजा भभूत सिंह जैसे महान नायकों के नाम पर कैबिनेट बैठकें आयोजित की गई हैं। छिंदवाड़ा में बादल भोई और जबलपुर में राजा शंकर शाह-रघुनाथ शाह संग्रहालय का लोकार्पण किया है। सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करने के लिए जनजातीय पर्व भगोरिया को राजकीय उत्सव का दर्जा दिया गया है। कन्या छात्रावासों के नाम भी जनजातीय नायकों के नाम पर रखे गए हैं। जनजातीय भाई-बहनों का कल्याण और उनका समग्र विकास सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सिकल सेल के खिलाफ यह लड़ाई समाज के हर वर्ग की भागीदारी से ही जीती जा सकेगी। उन्होंने माँ नर्मदा और ओंकारेश्वर महाराज की पावन धरती पर संकल्प लेते हुए कहा कि जब तक सिकल सेल उन्मूलन अभियान पूरी तरह सफल नहीं होगा, तब तक यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का प्रदेश आगमन के लिए आभार व्यक्त किया।उप-मुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि मध्य प्रदेश ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन-2047 में सबसे अच्छा कार्य किया है। सिकल सेल को जड़ से खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2023 में शहडोल से एक मिशन की शुरूआत की थी। इसे राज्यपाल पटेल के प्रयासों ने और गति प्रदान की है। प्रदेश के जनजातीय बहुल जिलों में अब तक 1 करोड़ 32 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। मध्य प्रदेश सिकल सेल एमीनिया की स्क्रीनिंग के मामले में अग्रणी राज्य है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार ने वर्ष 2026 के अंत तक 1 करोड़ 60 लाख स्क्रीनिंग का लक्ष्य रखा है। अब कुंडली से पहले सिकल सेल स्क्रीनिंग कार्ड का मिलान किया जाने लगा है। इसके लिए प्रदेशभर में जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है, जिससे कोई भी सिकल सेल का वाहक न बने।

राष्ट्रपति ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर प्रदेश में संचालित योजनाओं की सराहना की

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने ओंकारेश्वर में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के अंतर्गत आयोजित विश्व सिकलसेल दिवस-2026 के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी के अवलोकन के दौरान राष्ट्रपति ने सिकलसेल उन्मूलन मिशन-2047 के तहत मध्य प्रदेश में किए जा रहे कार्यों, नवाचारों एवं जन-जागरूकता अभियानों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने सिकलसेल रोग की रोकथाम, समय पर जांच, उपचार तथा प्रभावित परिवारों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम में आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार, जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर डॉ. विजय शाह, धार्मिक न्यास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेंद्र सिंह लोधी, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्यमंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायकगण सहित जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और सिकलसेल उन्मूलन मित्र उपस्थित थे।

सार समाचार

उज्जैन पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, हेलीपैड पर हुआ भव्य स्वागत

उज्जैन। मध्यक प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय ऊर्जा एवं आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर शुक्रवार को हेलीकॉप्टर से उज्जैन पहुंचे। उनके साथ नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे।उज्जैन हेलीपैड पहुंचने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भी अतिथियों का अभिनंदन किया।हेलीपैड पर विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, विधायक जितेंद्र पंड्या, हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष ओम जैन, महापौर मुकेश टटवाल, नगर निगम सभापति कलावती यादव, भाजपा नगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।इस दौरान सुरक्षा एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी भी तैनात रहे।

मप्र के खरगोन में जल संकट से जूझ रहे किसानों ने खंडवा-वडोदरा हाईवे पर किया चक्का जाम

खरगोन। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में पेयजल और सिंचाई संकट से जूझ रहे किसानों का आक्रोश शुक्रवार को सड़क पर दिखाई दिया। ग्राम बिलाली और आसपास के गांवों के किसानों ने तालाबों का पानी नदी-नालों और जलापूर्ति व्यवस्था में छोड़ने की मांग को लेकर खंडवा-वडोदरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्काजाम कर दिया।दरअसल, मध्य प्रदेश में मानसून की बेरुखी और प्री-मानसून की मार ने किसानों को संकट में डाल दिया है। प्रदेश में मानसून की देरी के कारण जहां एक जून से अब तक सामान्य से 39% कम बारिश हुई है और खरीफ की बुवाई अटक गई है, वहीं बड़वानी में आई तेज आंधी-बारिश से केले की फसल तबाह हो गई। सूखे के इसी संकट के बीच खरगोन में नहर से पानी छोड़ने की मांग को लेकर आक्रोशित किसानों ने खंडवा-बड़ौदा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैलगाड़ियां खड़ी कर चक्काजाम कर दिया। जानकारी के अनुसार, शुक्रवार सुबह ग्राम बिलाली सहित आसपास के सात गांवों के किसान बड़ी संख्या में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एकत्रित हुए। किसानों ने अपने वाहन सड़क पर खड़े कर यातायात पूरी तरह बाधित कर दिया। देखते ही देखते हाईवे पर ट्रक, बसों और चारपहिया वाहनों की लंबी लाइन लग गई। जाम के चलते यात्रियों को घंटों परेशानी का सामना करना पड़ा।

110 करोड़ की आसन सिंचाई परियोजना पर लापरवाही का ग्रहण, 12 साल बाद भी अधूरा विस्थापन

मुरैना। मध्य प्रदेश में किसानों को राहत देने और मुरैना-भिंड क्षेत्र की हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई आसन सिंचाई परियोजना सरकारी लापरवाही के कारण अधर में लटकी नजर आ रही है। करीब 110 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी परियोजना का वास्तविक लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पाया है।आसन नदी पर जौरा क्षेत्र के हथरिया गांव के पास वर्ष 2018 में आसन वेराज का निर्माण पूरा हुआ था। 30 एमसीएम जल क्षमता वाले इस बांध में छह इलेक्ट्रॉनिक गेट लगाए गए हैं, लेकिन निर्माण के वर्षों बाद भी इन गेटों को एक बार भी बंद नहीं किया जा सका। इसके कारण बांध में पानी का भंडारण नहीं हो पाया और 5500 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई का इंतजार है।निर्माण एजेंसी की गारंटी अवधि भी वर्ष 2022 में समाप्त हो चुकी है, लेकिन परियोजना की मुख्य समस्या अब तक दूर नहीं हो सकी है।परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले गदाल का पुरा गांव के विस्थापन का मामला सबसे बड़ा अड़ंगा बना हुआ है। करीब 12 साल बाद भी 200 परिवारों का पूरी तरह विस्थापन नहीं हो पाया है।प्रशासन द्वारा 158 परिवारों को जमीन और आवास के लिए पांच-पांच लाख रुपये की सहायता राशि दी गई है, लेकिन 43 परिवारों ने नकद राशि लेने से इनकार करते हुए प्लॉट की मांग रखी है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी पूरी जमीन का मुआवजा नहीं मिला और शेष जमीन तक पहुंचने के लिए रास्ते की व्यवस्था भी नहीं की गई।प्रशासन ने ग्रामीणों के पुनर्वास के लिए मुरैना में एनएच-44 के किनारे प्लॉट देने की योजना बनाई है, लेकिन ग्रामीण इसकी गुणवत्ता और सुविधाओं को लेकर सवाल उठा रहे हैं।

इंदौर में नीट की तैयारी कर रही छात्रा चौथी मंजिल से गिरी, इलाज के दौरान मौत

इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के न्यू बर्ग कॉलोनी क्षेत्र में गुरुवार देर रात मेडिकल प्रवेश परीक्षा (नीट) की तैयारी कर रही एक छात्रा की चौथी मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल छात्रा को पहले निजी अस्पताल और बाद में एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शुक्रवार तड़के उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान अवंतिका मोर्य के रूप में हुई है, जो न्यू बर्ग कॉलोनी स्थित एक निजी बिल्डिंग के प्रथम तल पर किराए से रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। गुरुवार रात करीब 11:30 बजे वह मोबाइल फोन पर बातचीत करते हुए बालकनी में टहल रही थी। इसके बाद वह बात करते हुए बिल्डिंग की ऊपरी मंजिलों की ओर चली गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ देर बाद चौथी मंजिल से गिरने की तेज आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तत्काल परिजनों को सूचना दी गई। घटना के बाद गंभीर हालत में अवंतिका को उसके पिता डॉ. बंशीलाल मोर्य निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे एमवाय अस्पताल रेफर कर दिया, जहां शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। अवंतिका इंदौर में अपनी बड़ी बहन के साथ रह रही थी। उसकी बड़ी बहन चिकित्सक है, जबकि पिता डॉ. बंशीलाल मोर्य भी डॉक्टर हैं। परिवार मूल रूप से धार जिले का निवासी है। जानकारी के अनुसार डॉ. मोर्य की इन दिनों एमवाय अस्पताल में ट्रेनिंग चल रही है, जिसके चलते वे करीब पांच दिन पहले ही इंदौर आए थे।

सूचना प्रवाह यूट्यूब चैनल का शुभारंभ

सरकारी योजनाओं की पहुंचेगी जनता तक जानकारी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने डिजिटल संचार को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल सूचना प्रवाह का शुभारंभ किया। लोक भवन, लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में सूचना निदेशक विशाल सिंह और अपर सूचना निदेशक अरविंद कुमार मिश्र ने चैनल का उद्घाटन किया।इस अवसर पर निमार्ता फिल्म अभय कुमार श्रीवास्तव, फिल्म निर्माण प्रबंधक संदीप पांडेय तथा विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।सूचना प्रवाह के माध्यम से प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास परियोजनाओं, महत्वपूर्ण निर्णयों, उपलब्धियों और जनहित कार्यक्रमों से जुड़ी प्रमाणिक एवं त्वरित जानकारी आम जनता तक पहुंचाई जाएगी। साथ ही विभाग द्वारा निर्मित वृत्तचित्र, विशेष रिपोर्ट, प्रेरणादायी वीडियो और सरकारी अभियानों का भी नियमित प्रसारण किया जाएगा।सूचना निदेशक विशाल सिंह ने कहा कि डिजिटल मीडिया आज जनसंचार का सबसे प्रभावी माध्यम है और यह चैनल सरकार तथा जनता के बीच संवाद का सशक्त सेतु बनेगा। वहीं अपर निदेशक अरविंद कुमार मिश्र ने कहा कि ह्यसूचना प्रवाहह्ण प्रदेश की विकास यात्रा और सरकारी योजनाओं की जानकारी व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

रीवा में ईडी की बड़ी कार्रवाई: तीन ठेकेदारों और स्टोन क्रेशर संचालक के ठिकानों पर छापेमारी

रीवा। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में शुक्रवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। ईडी की अलग-अलग टीमों ने शहर के तीन बड़े ठेकेदारों और स्टोन क्रेशर संचालक के ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। कार्रवाई के दौरान टीम ने कई दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच शुरू की है, हालांकि अभी तक छापे की आधिकारिक वजह सामने नहीं आई है।जानकारी के अनुसार ईडी की टीम ने रीवा की पद्मधर कॉलोनी, इंद्रा नगर और जनता कॉलेज क्षेत्र स्थित ठेकेदारों के आवासों पर सुबह-सुबह पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। टीमों के पहुंचते ही इलाके में हलचल मच गई। बताया जा रहा है कि ईडी अधिकारियों ने घर और कार्यालयों में मौजूद दस्तावेज, लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड और अन्य कागजातों की जांच शुरू की है।

सूत्रों के अनुसार कुछ दिन पहले रीवा में ठेकेदारों और निर्माण एजेंसियों से जुड़े लोगों के खिलाफ आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने भी मामला दर्ज किया था। यह कार्रवाई घटिया डामर के उपयोग से जुड़े मामले को लेकर हुई थी, जिसके बाद ठेकेदारों में काफी नाराजगी भी देखी गई थी। अब ईडी की कार्रवाई को भी उसी प्रकरण से जोड़कर देखा जा रहा है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। बताया गया कि सुबह करीब 5 बजे पद्मधर कॉलोनी में ठेकेदार केके सोहगौरा के निवास पर ईडी की टीम पहुंची। शुरूआत में परिवार के लोगों ने टीम से पहचान और जांच संबंधी दस्तावेज दिखाने की मांग की। पुष्टि होने के बाद टीम ने घर के अंदर प्रवेश कर जांच शुरू की।वहीं इंद्रा नगर निवासी ठेकेदार त्रिवेणी प्रसाद मिश्रा के यहां भी ईडी की कार्रवाई जारी है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना सहित कई बड़े निर्माण कार्य किए हैं। इसके अलावा जनता कॉलेज क्षेत्र में रहने वाले ठेकेदार रामसज्जन शुक्ला के ठिकाने पर भी जांच की जा रही है। वे कई निर्माण कार्यों से जुड़े रहे हैं।

ईडी की कार्रवाई को लेकर अलग-अलग चर्चाएं चल रही हैं। कुछ लोग इसे निर्माण कार्यों में अनियमितता से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हो सकता है। हालांकि ईडी की ओर से अभी तक कार्रवाई के कारणों या जांच के विषय को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई है।फिलहाल ईडी की टीम सभी ठिकानों पर दस्तावेजों की जांच और पूछताछ में जुटी हुई है। कार्रवाई पूरी होने के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

उज्जैन बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल

उज्जैन। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल शुक्रवार तड़के मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल होकर दर्शन-पूजन किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। भक्ति और आध्यात्मिकता से सराबोर इस विशेष अवसर पर चहल करीब दो घंटे तक नंदी हॉल में बैठकर भस्म आरती के साक्षी बने।शुक्रवार तड़के सुबह करीब 3 बजे मंदिर पहुंचे चहल ने विधि-विधान से भगवान महाकाल के दर्शन किए। भस्म आरती के दौरान वे पूरी श्रद्धा के साथ बाबा महाकाल की भक्ति में लीन दिखाई दिए।

चुनौतियों से मुकाबला कर पत्रकारिता की साख बचाएं- मंत्री पाण्डेय पाण्डेय

●-मथुरा के पत्रकारों की समस्याओं का समाधान मुख्यमंत्री से करायेंगे- कैबिनेट मंत्री
-पत्रकार अपनी खबरों में भी ब्रजभाषा का समावेश करें :डा .बबीता
-एआई पत्रकारों को बेरोजगार बना रहा-हेमंत तिवारी

मथुरा। ब्रज प्रेस क्लब एवं नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स इंडिया संगोष्ठी का भव्य आयोजन एक होटल में हुआ। इसमें मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के खाद्य रसद एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री मनोज कुमार पाण्डेय ने कहा कि पत्रकारों का अतीत स्वर्णिम था जबकि आज के दौर में पत्रकारों के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं। पत्रकारों को इन चुनौतियों का ईमानदारी एवं निर्भीकता के साथ मुकाबला करके स्वर्णिम भविष्य बनाने की जिम्मेदारी है। उन्होंने

प्रेस क्लब अध्यक्ष डॉ. कमलकांत उपमन्यु की पत्रकारों के लिए जगह उपलब्ध कराने की मांग के संबन्ध में कहा कि मथुरा के पत्रकारों की समस्याओं का समाधान कराने के लिए मुख्यमंत्री से मिलेंगे और प्रेस क्लब के लिए जगह की व्यवस्था कराने का प्रयास भी करेंगे।उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा डा.बबीता सिंह चौहान ने सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मैं भी ब्रज की ही बेटी हूं व ब्रज की महिला पत्रकारों व अन्य सभी पत्रकारों के साथ खड़ी हुई हूं। ब्रज संघर्ष की नगरी है और पत्रकार अपनी खबरों में ब्रजभाषा का समावेश करें। उनका कहना था कि कई महिला पत्रकारों की समस्याओं को खत्म कराने के लिए मैं लड़ी हूँ और आगे भी उनके साथ खड़ी रहूँगी।उत्तर प्रदेश राज्य मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति के अध्यक्ष हेमन्त तिवारी ने कहा कि आज का एआई का युग पत्रकारों को बेरोजगार कर रहा है। पत्रकारों को आईना दूसरों को दिखाने के साथ ही खुद भी समय-समय पर आईना देखना चाहिए। उन्होंने कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पाण्डेय से कहा कि इस कार्यक्रम में लगभग ढाई घंटे में 72 बार लाइट गुल हुई है आप (मनोज कुमार पाण्डेय) अपने मित्र ऊर्जा मंत्री एके शर्मा से कहकर विद्युत व्यवस्था में धार करवाएँ।एनयूजेआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रास बिहारी ने कहा कि वर्तमान फर्जी पत्रकार तथा फर्जी पत्रकार संगठन हैं। सही पत्रकारों के हितों के संरक्षण के लिए कोई विशेष कानून नहीं है जिससे पत्रकारों पर हमलों में बढ़ोत्तरी हुई है। उन्होंने देशभर में पत्रकार सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग की।

जिलाधिकारी चंदप्रकाश सिंह ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में पत्रकारों को देखकर अच्छा महसूस हो रहा है। समाजहित में पत्रकार इसी प्रकार से कार्य करते रहें।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार का मानना था कि पत्रकार समाज का दर्पण हैं।समारोह को दिल्ली जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश थपलियाल, एनयूजेआई चुनाव आयोग के अध्यक्ष दधिबल यादव, राजस्थान जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश संयोजक राकेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष संजय सैनी, विश्वहिन्दू परिषद के ब्रज प्रांत अध्यक्ष कन्हैया लाल अग्रवाल, समाजसेवी प्रमोद कसेरे ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया।

एनयूजे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और ब्रज प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉ.कमल कान्त उपमन्यु एडवोकेट ने कैबिनेट मंत्री मनोज पाण्डेय के पूर्व मंत्रित्व काल (2014) में उनके द्वारा किए गए वायदे को याद दिलाते हुए ब्रज प्रेस क्लब बनवाने की पुनः मांग की।

उपमन्यु ने पाण्डेय को बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जगह की मंजूरी दी थी। ग्रांट भी आई थी, लेकिंग जगह नहीं मिली। उपमन्यु ने संगोष्ठी में आए सभी पत्रकारों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया और आभार जताया। मंच का संचालन अनूप शर्मा ने किया।

इस अवसर पर किशन चतुर्वेदी, सीपी सिंह सिकरवार, दिलीप चतुर्वेदी, भोलेश्वर उपमन्यु, मोहनश्याम शर्मा, मोहनश्याम रावत, गौरव चौधरी, धाराजीत सारस्वत, मदन गोपाल शर्मा, ठा.प्रकाश सिंह, धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, गोविन्द भारद्वाज, रामगोपाल चौधरी, राजेश भाटिया, मोहन श्याम रावत, नागेन्द्र राठौर, रामकुमार रौतेला, गिरधारी लाल श्रोत्रिय, यतीश शर्मा, राजेश सोलंकी, ऋषि भारद्वाज, डा. विवेक प्रिय आर्य, मनीष सक्सेना, सोनू व्यास, मोहित गौड़, परीक्षित कौशिक, दिनेश तरकर, राजकुमार तौमर, गिरधर पचौरी, नीरज चौधरी, डा. विनोद जिंदल, कृष्णा शर्मा, शिवांगी चौधरी, उमर कुरैशी, फैसल कुरैशी, निर्मल राजपुर, राजू चौहान, गिरीश ठाकुर, श्याम जोशी, सुरेश सैनी, सुरेश पचहरा, गिरीश कुमार, बाला अरोड़ा, परवेज अहमद, अभिषेक चतुर्वेदी, रईस कुरेशी, अनिल अग्रवाल, आरती शर्मा, पल्लवी शर्मा, रेनू गोला, विष्णु गुप्ता, विष्णु शर्मा, सुनील शर्मा, महेश मीणा, सतीश कुमार, पिंटू सिंह, अनिल शर्मा, राजू पंडित, बॉबी जादौन, कृष्णा गुप्ता, केके अरोड़ा, शिवशंकर पाराशर, प्रशांत वार्ष्णेय, राजीव अग्रवाल, शिवशंकर शर्मा, भागवताचार्य पूर्णप्रकाश महाराज, विहिप जिलाध्यक्ष रनवीर कमान्डो, भूपेश अग्रवाल, मनोज शर्मा बॉबी, राजू पण्डित, चिंताहरण चतुर्वेदी, राया के पूर्व चेयरमैन राकेश शर्मा, अजय शर्मा, योगेश तिवारी, सरोज गोला, सतीश शर्मा, विनोद दीक्षित, सौरभ गुप्ता एडवोकेट, इकरार अली, राहुल शर्मा, मनोज वार्ष्णेय, धनीराम खंडेलवाल, विष्णु शर्मा, चन्द्रपाल सिंह पौनिया, प्रतीक चतुर्वेदी, अमन मिश्रा, रामप्रसाद सिंह, सुरेश पचहरा, वीरेन्द्र चौधरी, सुशील गौतम, गुलाब चौधरी, कुशल प्रताप सिंह, लोकेन्द्र, तुलसीराम अग्रवाल, राजेश पाठक, विवेक चतुर्वेदी, भूपेन्द्र चौधरी, अनिल कुमार, राकेश पचौरी, विशाल पाराशर, अंकुर देवा प्रधान, शुभम अग्रवाल, मनोज नागर, रवि श्रीवास्तव, राजेंद्र सौनी, ललित गुप्ता आदि सैकड़ों पत्रकार एवं समाजसेवी-समाजसेविकाएँ सम्मानित हुए। समारोह का शुभारंभ अतिथियों ने मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्ज्वलन एवं माल्यार्पण कर किया।

संक्षिप्त समाचार

भारत के बिमल पटेल न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल लॉ ऑफ सी ट्रिब्यूनल के जज चुने गए

संयुक्त राष्ट्र,एजेंसी। भारत के बिमल पटेल को इंटरनेशनल लॉ ऑफ सी ट्रिब्यूनल (अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण) का न्यायाधीश निर्वाचित किया गया है। उनके चुनाव के बाद वे गुरुवार को यहां यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा चुने जाने के बाद सितंबर में न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) में कार्यभार संभालेंगे। उनके चयन के साथ भारत की प्रतिनिधित्व निरंतरता बनी रहेगी, क्योंकि वर्तमान न्यायाधिकरण की उपाध्यक्ष नीरू चड्ढा सितंबर में अपना नौ वर्षीय कार्यकाल पूरा करेंगी।

बिमल पटेल एक अंतरराष्ट्रीय विधिवेत्ता हैं और वर्तमान में यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल लॉ कमीशन के सदस्य तथा गुजरात स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति (वाइस चांसलर) हैं। वे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य भी हैं। उन्होंने नीदरलैंड की लेडन यूनिवर्सिटी और जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी से अंतरराष्ट्रीय कानून में पीएचडी की है। भारत के संयुक्त राष्ट्र मिशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा कि बिमल पटेल का चुनाव 'बहुपक्षवाद और समुद्री कानून के प्रति भारत की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाता है। भारतीय राजनयिकों ने पिछले वर्ष से ही संयुक्त राष्ट्र में उनके चुनाव के लिए अभियान चलाया था। इस वर्ष ट्रिब्यूनल की सात सीटों में से दो एशियाई क्षेत्र के लिए थीं, जो पटेल और वियतनाम की नैग्यून लन अन थी को मिलीं। थाईलैंड के उम्मीदवार क्रियांग्सक किटिचासरी, जो मौजूदा न्यायाधीश थे और जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, चुनाव हार गए, जबकि इंडोनेशिया ने मतदान से पहले अपना उम्मीदवार वापस ले लिया। बिमल पटेल को कुल 168 वैध मतों में से 115 मत प्राप्त हुए। यह चुनाव समुद्री कानून सम्मेलन के 36वें सत्र के दौरान हुआ, जिसमें 172 सदस्य देश शामिल हैं। जर्मनी के हैम्बर्ग स्थित यह न्यायाधिकरण समुद्रों और महासागरों से जुड़े विवादों का निपटारा करता है और समुद्री कानून की व्याख्या करता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर उन्हें बधाई देते हुए यूएनसीएलओएस सदस्य देशों का धन्यवाद किया।

संयुक्त राष्ट्र ने युगांडा में इबोला से निपटने के प्रयासों में मदद को 40 लाख अमेरिकी डॉलर किए आवंटित

संयुक्त राष्ट्र,एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों और आपातकालीन राहत समन्वयक के अवर महासचिव टॉम फ्लेचर ने युगांडा में इबोला के खिलाफ सरकार की प्रतिक्रिया को समर्थन देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के केंद्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया कोष (सीईआरएफ) से 40 लाख अमेरिकी डॉलर आवंटित किए हैं। यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र के एक प्रवक्ता ने दी। इंटरनेशनल आर्गनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रमुख प्रवेश बिंदुओं पर जांच (स्क्रीनिंग), निगरानी और आवागमन प्रबंधन को मजबूत कर रहे हैं, जबकि यूनिसेफ सामुदायिक सहभागिता, जोखिम संबंधी जागरुकता और आवश्यक सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने में सहयोग कर रहा है।

इसके अलावा, विश्व खाद्य कार्यक्रम ने मरीजों, पृथकवास (आइसोलेशन) में रखे गए संपर्कों और अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्यकर्मियों को 6,000 से अधिक भोजन पैकेट उपलब्ध कराए हैं। साथ ही, संगठन आवश्यक राहत एवं चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति भी सुनिश्चित कर रहा है। इस बीच, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो में संयुक्त राष्ट्र और उसके सहयोगी संगठनों ने इस सप्ताह 16 मीट्रिक टन से अधिक चिकित्सा सामग्री पहुंचाई। दुजारिक के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र के साझेदारों ने निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एनजिली इंटरनेशनल एयरपोर्ट किंशासा में नई स्वास्थ्य जांच सुविधाएं भी स्थापित की हैं। संयुक्त राष्ट्र के आपातकालीन राहत समन्वयक ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक से परामर्श के बाद जूलियन हार्नेस को वरिष्ठ इबोला समन्वयक नियुक्त किया है। दुजारिक के अनुसार, उनका दायित्व इबोला प्रतिक्रिया से जुड़े विभिन्न प्रयासों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना, परिचालन संबंधी चुनौतियों का समाधान करना और जरूरतमंद लोगों तक सहायता को यथासंभव शीघ्र पहुंचाना होगा। इबोला, जिसे इबोला वायरस रोग भी कहा जाता है, एक दुर्लभ लेकिन अक्सर घातक रक्तस्रावी बुखार (हेमरेजिक फीवर) है, जो ऑर्थोइबोलावायरस के कारण होता है। यह मुख्य रूप से उप सहारा अफ्रीका में पाया जाता है और संक्रमित मनुष्यों या जानवरों के शारीरिक द्रवों अथवा दूषित सतहों के सीधे संपर्क से फैलता है। इसकी औसत मृत्यु दर लगभग 50 प्रतिशत है।

कांगो में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, इबोला के मामले बढ़कर 896 हुए

किंशासा,एजेंसी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (डीआरसी) में इबोला के पुष्ट मामलों की संख्या बढ़कर 896 हो गई है, जिनमें 232 लोगों की मौत हो चुकी है। डीआरसी के सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने यह जानकारी दी। बुधवार को पूर्वी प्रांतों इटुरी और नार्थ किवू में इबोला के 21 नए पुष्ट मामले सामने आए, जिनमें छह मौतें शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी दैनिक रिपोर्ट में यह जानकारी दी। मंत्रालय के अनुसार, बंडिबुग्यो इबोला वायरस से फैले इस प्रकोप ने पूर्वी डीआरसी के तीन प्रांतों इटुरी, नॉर्थ किवु और साउथ किवु के 33 स्वास्थ्य क्षेत्रों को प्रभावित किया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि 383 मरीज या तो आइसोलेशन में हैं या अस्पतालों में भर्ती हैं जबकि 78 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इनमें 11 ऐसे मरीज भी शामिल हैं जिन्हें नियंत्रण जांच (कंट्रोल टेस्ट) में नकारात्मक परिणाम आने के बाद स्वस्थ घोषित किया गया।

बुधवार को 151 संदिग्ध मामले भी दर्ज किए गए, जिनमें 35 मौतें शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार, तीनों प्रांतों में कुल 6,367 संपर्कों (कॉन्टैक्ट्स) की निगरानी की जा रही है। इनमें से 4,525 लोगों तक रिपोर्टिंग अवधि के दौरान पहुंच बनाई गई, जो 71.1 प्रतिशत की फॉलो-अप दर को दर्शाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुष्ट मामलों की संख्या सप्ताह-दर-सप्ताह लगातार बढ़ रही है, जो समुदाय स्तर पर संक्रमण के जारी रहने का संकेत देती है। रिपोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि यदि सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को शीघ्रता से लागू नहीं किया गया, तो संक्रमण का भौगोलिक विस्तार तेजी से हो सकता है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, डीआरसी में यह मौजूदा प्रकोप इबोला का 17वां प्रकोप है, जिसे आधिकारिक रूप से 15 मई को घोषित किया गया था। इबोला रोग पहली बार वर्ष 1976 में दो समानांतर प्रकोपों के दौरान सामने आया था। पहला प्रकोप सूडान वायरस रोग का था, जो नजारा (वर्तमान साउथ सूडान) में हुआ था जबकि दूसरा इबोला वायरस रोग का प्रकोप यामबुकु (वर्तमान डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो) में हुआ था। यह प्रकोप इबोला नदी के निकट स्थित एक गांव में फैला था, जिसके नाम पर इस बीमारी का नाम रखा गया।

राष्ट्रपति ट्रंप ने तीन अमेरिकी सैनिकों को उनकी वीरता और जज्बे के लिए मेडल ऑफ ऑनर से किया सम्मानित

वाशिंगटन,एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वियतनाम युद्ध और अफगानिस्तान युद्ध में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए रिटायर्ड मरीन मेजर जेम्स कैपर्स जूनियर, रिटायर्ड आर्मी मेजर निकोलस डॉकरी और मरणोपरांत मरीन कर्नल जॉन डब्ल्यू. रिप्ले को अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान 'मेडल ऑफ ऑनर' दिया। व्हाइट हाउस में समारोह के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने तीनों सैनिकों को हिम्मत और कुर्बानी की मिसाल बताया, जो अमेरिकी सुरक्षा बलों की पहचान है। ट्रंप ने कहा, 'अमेरिकी सुरक्षा बलों के कमांडर इन चीफ के तौर पर सेवा करने से बड़ा कोई खास मौका मेरे लिए नहीं है। धरती पर अब तक के सबसे बहादुर और महान हीरो की 250 साल की परंपरा। लेकिन कुछ ही लोगों को हमारा सबसे बड़ा सैन्य सम्मान, कांग्रेसनल मेडल ऑफ ऑनर मिला है। कैपर्स को 1967 में वियतनाम में चार दिन के टोही मिशन के दौरान उनके कामों के लिए पहचान मिली थी।

व्हाइट हाउस के मुताबिक, उस समय के सेकंड लेफ्टिनेंट कैपर्स और उनकी टीम ने उत्तरी वियतनामी रेजिमेंटल बेस कैंप का पता लगाने की कोशिश में दुश्मन की बड़ी सेना से बार-बार भिड़ंत की। एक हमले में कई गंभीर चोटें लगने के बावजूद, उन्होंने अपने सैनिकों का नेतृत्व करना जारी रखा, सपोर्टिंग फायर को कोऑर्डिनेट किया और उन्हें निकालने का काम निर्देशित किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि कैसे कैपर्स बुरी तरह घायल होने के बावजूद लड़ते रहे। उन्होंने कहा, 'उनके सभी साथी घायल हो गए, लेकिन जेम्स एक पैर पर उठ खड़े हुए और आगे बढ़ते गए। उनका एक पैर उनकी पूरी वजन नहीं उठा सकता था। मुश्किल से होश में आने पर, उन्होंने पूरे एक घंटे तक क्लोज एयर सपोर्ट के लिए कॉल किया। बता दें कि क्लोज एयर सपोर्ट एक सैन्य हवाई रणनीति है, जिसमें लड़ाकू विमानों (फिक्स्ड-विंग) और हेलीकॉप्टरों (रोटरी-विंग) द्वारा दुश्मन के उन ठिकानों पर सटीक हमले किए जाते हैं, जो जमीन पर लड़ रहे मित्र देशों की सेनाओं के बहुत करीब होते हैं। राष्ट्रपति ने बताया कि कैपर्स को असल में 1967 में मेडल ऑफ ऑनर के लिए रिकमेंड किया गया था, लेकिन पेपरवर्क पूरा होने से पहले उनके कमांडिंग ऑफिसर की मौत हो जाने के बाद अवॉर्ड प्रोसेस रुक गया। ट्रंप ने कहा, 'जेम्स, देश ने तुम्हें बहुत लंबा इंतजार करवाया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, बधाई हो, तुम कर पाए।'

कर्नल जॉन डब्ल्यू. रिप्ले को यह सम्मान मरणोपरांत 2 अप्रैल, 1972 को उत्तरी वियतनाम के एक बड़े हमले के दौरान उनके कामों के लिए मिला। उस समय के कैप्टन रिप्ले, एक सीनियर मरीन सलाहकार के तौर पर, दुश्मन की तेज फायरिंग के बीच एक पुल के नीचे बार-बार चढ़े और 500 पाउंड से ज्यादा विस्फोटक रखे, जिससे पुल का ढांचा नष्ट हो गया और आगे बढ़ रही दुश्मन सेना रुक गई। ट्रंप ने कहा, 'लगातार पांच घंटे तक, वह एक्सप्लोसिव ले गए, चार्ज लगाए और हर एक तक एक प्राइमर कॉर्ड पहुंचाया। जब जॉन ने एक्सप्लोसिव ब्लास्ट किया, तो पुल नदी में गिर गया, जिससे आगे बढ़ रहे लोग मारे गए। डॉकरी को अक्टूबर 2012 में अफगानिस्तान के कपिसा प्रांत में तालिबान के हमले के दौरान की गई कार्रवाई के लिए सम्मानित किया गया था। व्हाइट हाउस ने कहा कि घायल सैनिकों को बचाने, जवाबी हमलों का नेतृत्व करने और हवाई मदद का निर्देशन करते समय उन्होंने बार-बार दुश्मन की गोलीबारी का सामना किया।

ट्रंप ने बताया कि कैसे निकोलस डॉकरी ने ना केवल घायल साथियों को बचाया, बल्कि उन्हें दुश्मन के हमलों से सुरक्षित किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, 'जब उनके चारों ओर मोर्टार फायर की गड़गड़ाहट हो रही थी, निक ने अपने घायल साथी को अपने शरीर से कवर कर लिया। मेजर डॉकरी, आप उस दिन युद्ध के मैदान से जाने वाले आखिरी आदमी थे और आप इसे एक लीजेंड और हीरो के तौर पर छोड़ गए। समारोह खत्म करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि देश उन सैनिकों का कर्जदार है जिन्होंने लड़ाई में अपनी जान जोखिम में डाली। उन्होंने कहा, 'जैसे-जैसे हम अपनी स्थापना की 250वीं सालगिरह के करीब पहुंच रहे हैं, हमें याद है कि हम उन जैसे हीरो के लिए सब कुछ कर्जदार हैं जिनका हम आज जश्न मना रहे हैं। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। मेडल ऑफ ऑनर अमेरिकी सुरक्षा बलों के उन सदस्यों को दिया जाता है जो ड्यूटी से हटकर अपनी जान जोखिम में डालकर 'वीरता और निडरता' से अपनी अलग पहचान बनाते हैं। यह अमेरिकी सरकार द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा सैन्य सम्मान है। ये सम्मान ऐसे समय में दिए जा रहे हैं जब अमेरिका 2026 में अपनी स्थापना की 250वीं सालगिरह मनाने की तैयारी कर रहा है। अपने पूरे इतिहास में, मेडल ऑफ ऑनर उन सेवा सदस्यों को दिया गया है जिनके लड़ाई में किए गए कामों को सैन्य हिम्मत और कुर्बानी के सबसे ऊंचे स्टैंडर्ड को दिखाने वाला माना जाता है।

डेमोक्रेट सीनेटर ने ईरान के साथ ज्ञापन समझौते पर उठाए सवाल, कहा कि इस डील से कई अहम मुद्दे अनसुलझे रह गए

वाशिंगटन। डेमोक्रेटिक के वरिष्ठ नेता मार्क वार्नर ने अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ नए साइन किए गए समझौते की रणनीतिक मूल्यों पर सवाल उठाया है। डेमोक्रेटिक नेता का कहना है कि इस समझौते से तेहरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, क्षेत्रीय प्रॉक्सी नेटवर्क और भविष्य की परमाणु गतिविधियां अनसुलझी रहेंगी, जबकि ईरानी सरकार को इससे काफी आर्थिक राहत मिलेगी।

वार्नर ने मीडिया को बताया कि ट्रंप और ईरान के बीच एक दिन पहले हस्ताक्षर किया गया ज्ञापन समझौता उन कई मकसदों को हासिल करने में विफल रहा, जिन्हें सरकार ने लड़ाई की शुरुआत में बताया था। वार्नर ने कहा, 'हम इस लड़ाई में 111 दिन से हैं। एक बात जो हम बिल्कुल जानते हैं, वह यह है कि अमेरिका बेहतर नहीं हुआ है, हमारे लोग बेहतर नहीं हुए हैं, हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर नहीं हुई है। सीनेट इंडिया कॉकस के वर्तमान सह-अध्यक्ष और इंटेलिजेंस पर सीनेट की खुफिया मामलों की चयन समिति के उप-उपाध्यक्ष वार्नर ने कहा कि ईरान इस लड़ाई से कई लोगों की उम्मीद से ज्यादा मजबूत स्थिति में उभरा है। उन्होंने कहा, 'ईरान ने अमेरिका और इजरायल दोनों का सामना किया और कम से कम उन्हें टाई तक खेला। और दुर्भाग्य से, मुझे लगता है कि हमें इसकी कीमत लंबे समय तक चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा, 'ईरान ने अमेरिका और इजरायल, दोनों का मुकाबला किया और कम से कम मुकाबले को बराबरी पर ला खड़ा किया। दुर्भाग्य से हमें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और मेरा मानना है कि इसका प्रभाव लंबे समय तक देखने को मिलेगा। वार्नर ने कहा कि समझौते का यह नियम कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, तेहरान की लंबे समय से चली आ रही पब्लिक पोजीशन से बहुत कम बदलाव दिखाता है।

पाकिस्तानी-अमेरिकी समुदाय के नेता को 3.8 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप में किया गया गिरफ्तार

न्यूयॉर्क,एजेंसी। अमेरिका में डे केयर सेंटर से 3.8 करोड़ डॉलर के मेडिकेड धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बुजुर्गों के लिए डेकेयर सेंटर्स से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में एक जाने-माने पाकिस्तानी-अमेरिकी समुदाय के नेता को गिरफ्तार किया गया है। अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क पोस्ट की ओर से साझा जानकारी के अनुसार, स्थानीय समयानुसार गुरुवार को पाकिस्तानी अमेरिकी नेता परवेज सिद्दीकी समेत सात साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि परवेज सिद्दीकी न्यूयॉर्क शहर के ब्रुकलिन बरो में एक कम्युनिटी बोर्ड के सदस्य हैं।

अमेरिकी मीडिया ने बताया कि परवेज पर फेडरल वकीलों ने सरकारी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम 'मेडिकेड' के मामले में धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। इसमें 'ब्रुकलिन में दो सोशल एडल्ट डे केयर सेंटर, अपना एडल्ट डेकेयर और आशियाना सोशल एडल्ट डेकेयर के जरिए एक गलत बिलिंग स्कीम' चलाई गई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, वह और सात अन्य लोग कथित तौर पर ऐसे व्यक्तियों की भर्ती में शामिल थे, जिन्हें वयस्क दिव्यांगों या गंभीर रूप से बीमार लोगों के लिए संचालित कार्यक्रमों में शामिल दिखाया गया। आरोप है कि इन केंद्रों ने उन लोगों के नाम पर बिल जमा किए, जिन्होंने वास्तव में कार्यक्रमों में भाग नहीं लिया था या जिन्हें इन सेवाओं की आवश्यकता ही नहीं थी।

न्यूयॉर्क पोस्ट ने कहा कि 2019 से पिछले साल दिसंबर तक, उन्होंने मेडिकेड को उन सेवाओं के लिए बिल भेजा, जिनके बारे में कहा गया कि संबंधित केंद्रों ने उनके द्वारा भर्ती किए गए लोगों को उपलब्ध कराई थीं। फेडरल अभियोजकों के मुताबिक, आरोपियों ने इस राशि का एक हिस्सा उन लोगों को दिया और बदले में उनकी पहचान का इस्तेमाल कर फर्जी बिल दाखिल किए गए। पोस्ट के अनुसार, इस मामले में परवेज के साथ शाजिया बीबी (जिन्हें शाज़िया वद्दू के नाम से भी जाना जाता है), अब्दुल अजीज, शायर अली, जेबुन अहमद, जोसना बेगम, सायरा खातून और अतिया शहनाज का नाम शामिल है। न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार, चार्जशीट में कहा गया है कि उन्होंने पाकिस्तान-बेस्ड बिलिंग स्टाफ का इस्तेमाल किया और शेल कंपनियों के जरिए पैसे की लॉन्ड्रिंग करते समय 'लड्डू' जैसे कोड वर्ड का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि सेंटर्स पर कार्यक्रमों के लिए नकली साइन-इन शीट्स में सुविधाओं की क्षमता से ज्यादा लोग शामिल होते दिखे। कार्यक्रम में शामिल होने वाले कुछ लोग पाकिस्तान में थे। अमेरिका में गरीबों के लिए सरकारी बीमा योजना मेडिकेड है। इसका इन आरोपियों ने कथित तौर पर नकली बिलिंग के लिए फायदा उठाया; यह बुजुर्गों या बीमार लोगों के लिए लंबे समय तक देखभाल के कार्यक्रमों के लिए पेमेंट करता है और हर व्यक्ति के लिए पेमेंट 6,000 डॉलर प्रति माह तक हो सकता है। न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार, दिसंबर में अधिकारियों ने कथित स्कैम से जुड़ी जगहों पर रेड मारी थी। 78 साल के परवेज सिद्दीकी की न्यू जर्सी में करीब 15 फार्मेसी हैं। वह अमेरिकी पाकिस्तानी पब्लिक अफेयर्स कमेटी से जुड़े हैं, जिससे उन्हें न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी और दूसरे अधिकारियों तक पहुंच मिली। दूसरी आरोपी शाजिया बीबी कम्युनिटी बोर्ड की सदस्य भी हैं। अमेरिकी मीडिया के अनुसार, चार्जिंग डॉक्यूमेंट्स में फार्मेसी का नाम नहीं है। शाजिया बीबी ने 2022 में सिटी काउंसिल के सामने एक गवाही के दौरान कहा, 'हम एक पाकिस्तानी अमेरिकी समुदाय और एक मुस्लिम अमेरिकी के तौर पर अलग-थलग महसूस करते हैं क्योंकि हमें एक समुदाय के तौर पर कोई संसाधन नहीं मिल सका। एक अलग मामले में, जाकिया खान और अहसान इजाज को एक फेडरल कोर्ट में दूसरे मेडिकेड प्रोग्राम में नकली बिलिंग के जरिए सरकार से 68 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी करने का दोषी पाया गया।

भारत ने जम्मू-कश्मीर पर पाकिस्तान, ओआईसी की टिप्पणियों को किया खारिज, देश का अभिन्न अंग बताया

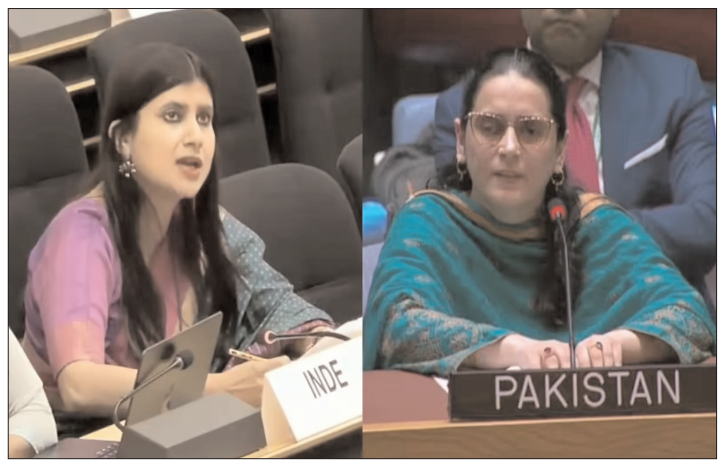

जिनेवा,एजेंसी। भारत ने पाकिस्तान के बेबुनियाद और गलत इरादे वाले आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। इसके साथ ही, इस्लामी सहयोग संगठन (ओआईसी) की तरफ से भारत के केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को लेकर किए गए जिक्र को भी खारिज कर दिया। भारत ने दोहराया कि यह इलाका देश का 'एक अभिन्न और अविभाज्य' हिस्सा है।

संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत के स्थानीय मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा, 'भारत को लेकर पाकिस्तान और ओआईसी द्वारा की गई टिप्पणियों के जवाब में भारत अपना उत्तर देने के लिए बाध्य है। हम पाकिस्तान के लगाए बेबुनियाद और गलत इरादे वाले आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। हम ओआईसी की तरफ से जम्मू और कश्मीर को लेकर की गई टिप्पणी को भी पूरी तरह से खारिज करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान का यह प्रचार उसके घरेलू मोर्चे पर विफलताओं और आतंकवाद को दिए जा रहे समर्थन को छिपाने की कोशिश है। ओआईसी समन्वयक की भूमिका का उसका दुरुपयोग केवल इस भ्रामक अभियान को और उजागर करता है। ऐसे प्रचार को महत्व देने की हमारी कोई इच्छा नहीं है। उन्होंने कहा, 'लेकिन, हम कुछ बातें कहना चाहेंगे। रिकॉर्ड के लिए, जम्मू और कश्मीर भारत का एक जरूरी और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। एकमात्र अनसुलझा मुद्दा भारतीय इलाकों पर पाकिस्तान का गैरकानूनी कब्जा और उसे वापस करना है। पाकिस्तान का प्रोपेगैंडा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में दमन की सच्चाई को छिपा नहीं सकता।

अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में फैली अशांति दशकों के दबाव, सैन्य नियंत्रण और बुनियादी अधिकारों से वंचित करने का नतीजा है। गैरकानूनी और गलत तरीके से किया गया नियंत्रण सिर्फ ताकत के दम पर ही कायम रह सकता है। उन्होंने कहा, 'रावलकोट में चल रही दुखद घटना, सैकड़ों आम लोगों की हत्या और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में बेरहमी से कार्रवाई, जबरदस्ती कब्जे और दबाव के जरिए बनाए गए सिस्टम का नतीजा है। दशकों से पाकिस्तानी सेना जमीन पर कब्जा, जनसंख्या संरचना में सुनियोजित बदलाव और बुनियादी आजादी से वंचित करने से हालात ऐसे हो गए हैं कि रोटी, बिजली, अधिकार और सम्मान की मांग कर रहे लोगों को भी गोलियों और क्रूरता का सामना करना पड़ रहा है। इससे किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। एक गैर-कानूनी कब्जा सिर्फ जबरदस्ती से ही बनाए रखा जा सकता है। सिंह ने पाकिस्तान पर यह भी आरोप लगाया कि वह आतंकवाद को सरकारी नीति के तौर पर अपना रहा है, जबकि साथ ही खुद को आतंकवाद का शिकार बता रहा है। भारत के स्थानीय मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा, 'यह वह देश है जहां के मौजूदा रक्षा मंत्री आतंकवादियों को आश्रय देने, प्रशिक्षण देने और तैनात करने को सरकारी नीति बताते हैं और फिर भी पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का पीड़ित कहता है। वास्तव में, यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे सिर्फ पाकिस्तान ही बनाए रख सकता है।

ईरान के साथ अगले चरण की वार्ता के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस की स्विट्जरलैंड यात्रा टली

वाशिंगटन,एजेंसी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ईरान के साथ तकनीकी बातचीत के लिए स्वीट्जरलैंड जाने वाले थे। फिलहाल इस योजना को टाल दिया गया है। हालांकि व्हाइट हाउस ने कहा है कि बातचीत की तैयारी जारी है और दोनों पक्ष हाल ही में हस्ताक्षर किए गए ज्ञापन समझौते को लागू करने के मकसद से बातचीत के अगले चरण को शुरू करने पर ध्यान दे रहे हैं।

व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने गुरुवार देर रात कहा, 'जैसा कि उपराष्ट्रपति ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आने वाली तकनीक बातचीत की योजना अभी तय नहीं हुए हैं और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल पहले मौके पर निकलने के लिए तैयार है, लेकिन इन बातचीत की व्यवस्था कभी भी आसान या अंदाजा लगाने लायक नहीं रही है। प्रवक्ता ने आगे कहा, 'फिलहाल के लिए उपराष्ट्रपति वेंस आज रात नहीं निकल रहे हैं। व्हाइट हाउस ने नए डिपार्चर शेड्यूल की घोषणा नहीं की, लेकिन कहा कि अधिकारी जल्द ही बातचीत शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने बताया कि जैसे ही हमें अगले चरण के बारे में कोई पक्का अपडेट मिलेगा, हम आपको बता देंगे। हम जल्द से जल्द तकनीकी बातचीत शुरू करने की उम्मीद करते हैं। यह देरी ऐसे समय में हो रही है जब वाशिंगटन और तेहरान समझौते से आगे बढ़कर लागू करने, सत्यापन और अनुपालन को लेकर विस्तृत बातचीत की ओर बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। गुरुवार को पहले, वेंस ने कहा था कि तकनीकी बातचीत कुछ ही दिनों में शुरू होने की उम्मीद है और यह शायद स्विट्जरलैंड में होगी।

व्हाइट हाउस में एक ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने मीडिया से कहा, 'हमें लगता है कि ये तकनीकी बातचीत इस हफ्ते के अंत में कभी भी शुरू हो सकती है।' उपराष्ट्रपति ने माना कि बातचीत का समन्वय मुश्किल साबित हुआ है। वेंस ने कहा, 'हमारा प्लान स्विट्जरलैंड जाने का है; मुझे ठीक से नहीं पता कब। यह बदल सकता है क्योंकि ईरान से बाहर निकलना आसान नहीं है और इसलिए हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह ठीक कब होगा। यह पूछे जाने पर कि क्या वह तुरंत यात्रा करेंगे, अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहा, 'हो सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि ईरानी वहां कब पहुंच सकते हैं। हम अभी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वेंस ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बातचीत के दौरान वह अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। बातचीत में तकनीकी मुद्दों पर फोकस रहने की उम्मीद है, जिनके बारे में अधिकारियों का कहना है कि इनसे यह तय होगा कि बड़े समझौते को सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है या नहीं। जिन विषयों पर बातचीत में सबसे ज्यादा ध्यान रहने की उम्मीद है, उनमें निगरानी की प्रक्रिया, सत्यापन तंत्र और ईरान के संवर्धित यूरेनियम के मलबे को संभालना शामिल है। वेंस ने कहा, 'आप इस बहुत ज्यादा संवर्धित यूरेनियम को कैसे खत्म करते हैं, ये सब चीजें हैं जिनकी आपको असल में बारीकियों में जाना है।'

राहुल गांधी के जन्मदिन पर यूथ कॉंग्रेस पार्टी ने लगाए पेड़

(मीरा-भाईंदर) महाराष्ट्र प्रदेश यूथ कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट और विपक्ष की नेता सैयद आफरीन मुजफ्फर हुसैन की पहल पर, मीरा-भाईंदर यूथ कांग्रेस ने राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर पेड़ लगाऐ गऐ। इस पहल को यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों, कार्यकताओं, स्थानीय नागरिकों और पर्यावरण प्रेमियों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला।मीरा रोड के आला हजरत मैदान इलाके में आयोजित इस प्रोग्राम में कई तरह के पेड़ लगाए गए। यह पहल पर्यावरण संरक्षण, ग्रीन डेवलपमेंट और आने वाली पीढ़ियों के लिए साफ और हेल्दी माहौल बनाने के मकसद से शुरू की गई थी।इस मौके पर पर्यावरण बचाने का मैसेज दिया गया और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने और बचाने की अपील की गई। पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ - हरा-भरा शहर, सुंदर शहर का मैसेज देते हुए, हिस्सा लेने वाले नागरिकों ने पर्यावरण बचाने की सामूहिक जिम्मेदारी निभाने का संकल्प लिया।इस मौके पर सैयद आफरीन मुजफ्फर हुसैन ने कहा कि यह राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर समाज सेवा के कामों को लागू करने की परंपरा को बनाए रखते हुए पेड़ लगाने जैसी पर्यावरण के अनुकूल गतिविधियों के जरिए समाज को एक अच्छा संदेश देने की कोशिश है।

रन फॉर योगा में शामिल हुए मुख्यमंत्री धामी, युवाओं से योग अपनाने का आह्वान

देहरादून। 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में पुलिस लाइन देहरादून में आयोजित रन फॉर योगा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह केवल एक दौड़ नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन, सकारात्मक सोच और योग को जन-जन तक पहुंचाने का सशक्त अभियान है।मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सदियों से योग, आध्यात्मिक साधना और ऋषि-मुनियों की तपस्थली रहा है। योग भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर है, जो शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग को वैश्विक पहचान मिली और आज 190 से अधिक देशों में करोड़ों लोग इसका अभ्यास कर रहे हैं।

उन्होंने युवाओं से नियमित योग और व्यायाम को दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड को योग, आयुर्वेद, वेलनेस और प्राकृतिक चिकित्सा का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कार्य कर रही है।कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, विधायक विनोद चमोली, देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल, सचिव आयुष रंजना राजगुरु, जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परमेंद्र डोभाल सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

हरिद्वार भूमि खरीद घोटाले में बड़ा एक्शन, 10 लोगों पर दर्ज होगा मुकदमा

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस के संकल्प के तहत हरिद्वार नगर निगम भूमि खरीद प्रकरण में बड़ा कदम उठाया गया है। विजिलेंस जांच में आपराधिक षड्यंत्र और धोखाधड़ी के जरिए भूमि खरीद-बिक्री कर नगर निगम को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए हैं।मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य सतर्कता समिति की संस्तुति पर मुख्यमंत्री ने मामले में संलिप्त 10 लोगों के खिलाफ अभियोग दर्ज करने को मंजूरी दे दी है। इनके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।जिन अधिकारियों और कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज होगा, उनमें तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी, सहायक नगर आयुक्त रविन्द्र कुमार दयाल, कर अधीक्षक लक्ष्मीकान्त भट्ट, सहायक एवं प्रभारी अधिशासी अभियंता आनन्द सिंह मिश्राण, सम्पत्ति लिपिक वेदपाल तथा मानचित्रकार दिनेश काण्डपाल शामिल हैं।वहीं भूमि विक्रेता और अन्य संबंधित व्यक्तियों में सुमन देवी, जितेन्द्र कुमार, अभिषेक यादव और सुजीत कुमार सिंह के खिलाफ भी अभियोग दर्ज किया जाएगा।राज्य सरकार ने दोहराया है कि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

सार समाचार

काकड़ीघाट और कैंची धाम में राज्यपाल ने की पूजा-अर्चना

नैनीताल। उत्तराखंड के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शुक्रवार को नैनीताल जनपद की सीमा से लगे अल्मोड़ा जनपद के काकड़ीघाट स्थित ऐतिहासिक ज्ञानवृक्ष (पीपल) और कर्कटेश्वर मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि एवं कल्याण की कामना की। इसके बाद न्होंने नैनीताल जनपद स्थित विश्वप्रसिद्ध कैंची धाम पहुंचकर बाबा नीब करौरी महाराज के आश्रम में दर्शन कर देश, प्रदेश तथा समस्त मानवता की सुख-शांति और कल्याण की प्रार्थना की। राज्यपाल ने कहा कि काकड़ीघाट आध्यात्मिक चेतना, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है। स्वामी विवेकानंद की साधना स्थली होने के कारण इसका महत्व और बढ़ जाता है। उन्होंने उस पावन स्थल के दर्शन को सौभाग्य बताते हुए ज्ञानवृक्ष के संरक्षण और वैज्ञानिक विधियों से उसके पुनर्जीवन के प्रयासों की सराहना की। राज्यपाल ने कहा कि यह स्थल आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। इधर कैंची धाम में उन्होंने बाबा नीब करौरी महाराज को नमन करते हुए कहा कि उनका जीवन सेवा, करुणा, भक्ति और मानव कल्याण के आदर्शों से परिपूर्ण रहा है तथा उनके संदेश आज भी समाज को सकारात्मक दिशा प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैंची धाम केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा, सेवा और लोकमंगल का जीवंत केंद्र है, जहां देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालु आत्मिक शांति का अनुभव करते हैं। राज्यपाल ने आश्रम परिसर का अवलोकन कर वहां संचालित आध्यात्मिक एवं सेवा गतिविधियों तथा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आश्रम प्रबंधन द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी सराहना की।

एसआईटी जांच से सामने आएगी सच्चाई, दोषी नहीं बचेगा : मुख्यमंत्री योगी

अयोध्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से जुड़े मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है और जांच में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि जांच पूरी होने तक किसी प्रकार की बयानबाजी न करें और यदि किसी के पास प्रमाण हों तो उन्हें एसआईटी को सौंपें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यदि कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।मुख्यमंत्री शुक्रवार को रुदौली विधानसभा क्षेत्र में 378 करोड़ रुपये से अधिक की 126 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय सहित विभिन्न परियोजनाओं की सौगात दी।योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि अयोध्या और राम मंदिर को बदनाम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को रामभक्तों और अयोध्या पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार अयोध्या के विकास और धार्मिक विरासत के संरक्षण के लिए लगातार कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के प्रयासों से अयोध्या का तेजी से विकास हुआ है। सोलर सिटी, बेहतर सड़क संपर्क, एयरपोर्ट और अन्य विकास कार्यों ने अयोध्या की पहचान को नई ऊंचाई दी है। मुख्यमंत्री ने लोगों से विकास कार्यों में सहयोग करने और प्रदेश की प्रगति में भागीदार बनने का आह्वान किया।

इस अवसर पर विधायक अमित सिंह चौहान, चंद्रभानु पासवान, अभय सिंह, विधान परिषद सदस्य हरिओम पांडेय, जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह, पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू, गोरखनाथ बाबा, भाजपा जिलाध्यक्ष राधेश्याम त्यागी आदि मौजूद रहे।

कांवड़ मेला-2026 की तैयारियां तेज, एसपी यातायात ने किया हाईवे और एक्सप्रेसवे मार्गों का स्थलीय निरीक्षण

हरिद्वार। आगामी कांवड़ मेला-2026 के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए हरिद्वार पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार नवनीत सिंह के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक यातायात निशा यादव ने राष्ट्रीय राजमार्ग-334, विभिन्न अंडरपास, फ्लाईओवरों तथा दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से हरिद्वार आने वाले मार्गों का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान सीओ यातायात बिपेन्द्र सिंह एवं यातायात निरीक्षक हितेश कुमार भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और संबंधित निर्माण एजेंसियों के अधिकारियों के साथ निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। पुलिस अधीक्षक यातायात ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कांवड़ मेले से पूर्व सभी आवश्यक निर्माण और सुधार कार्य समयबद्ध ढंग से पूर्ण किए जाएं, ताकि श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। हरि लोक तिराहा स्थित निर्माणाधीन फ्लाईओवर की एप्रोच वॉल के समीप मिट्टी की लेवलिंग कर पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित और सुगम मार्ग तैयार करने के निर्देश दिए गए। वहीं मोहनपुरी वाला और बहादराबाद बाईपास स्थित निर्माणाधीन फ्लाईओवरों के दोनों ओर सर्विस रोड की चौड़ाई बढ़ाने को कहा गया, जिससे यातायात संचालन अधिक सुचारु हो सके।

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से हरिद्वार पहुंच मार्ग पर निर्माणाधीन फ्लाईओवरों और टोल प्लाजा क्षेत्र में चल रहे कार्यों को कांवड़ मेले से पूर्व आगामी एक माह के भीतर पूरा करने के निर्देश भी संबंधित एजेंसियों को दिए गए। इसके अतिरिक्त पतंजलि से बढ़ेडी राजपूताना तक निर्माणाधीन फ्लाईओवरों के दोनों ओर सर्विस रोड को गड्ढामुक्त करने और उनकी चौड़ाई बढ़ाने का कार्य शीघ्र पूरा करने को कहा गया। बढ़ेडी राजपूताना से सालियर जंक्शन तक नव-निर्मित हाईवे पर शेष कार्यों को भी मेले से पहले पूरा करने के निर्देश दिए गए।

आज का दिव्य राशिफल

दिनांक : 20 जून- 2026, दिन शनिवार

मेष राशि

आज कार्यक्षेत्र में आपके प्रयास सफल होंगे। रुके हुए कार्यों में गति आएगी तथा आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा और किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। उपायः काले तिल का दान करें।

वृषभ राशि

आज व्यापार एवं नौकरी में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। मित्रों का सहयोग मिलेगा तथा नई योजनाओं पर कार्य आरंभ कर सकते हैं। दांपत्य जीवन मधुर रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। उपायः शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें।

मिथुन राशि

आज मानसिक तनाव कम होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। यात्रा के योग बन सकते हैं। उपायः काले उड़द का दान करें।

कर्क राशि

आज परिवार के साथ समय व्यतीत होगा। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उपायः हनुमान चालीसा का पाठ करें।

सिंह राशि

आज सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। व्यापार में नई उपलब्धियां मिल सकती हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात लाभदायक रहेगी। उपायः गरीबों को भोजन कराएं।

कन्या राशि

आज मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा। रुके हुए धन की प्राप्ति के योग हैं। विद्यार्थियों को सफलता मिल सकती है। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। उपायः शनिदेव के मंदिर में दीपक जलाएं।

तुला राशि

आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। अनावश्यक विवादों से दूर रहें। उपायः काले वस्त्र का दान करें।

वृश्चिक राशि

आज भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। व्यापार में लाभ होगा और नई योजनाएं सफल होंगी। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उपायः पीपल वृक्ष की पूजा करें।

धनु राशि

आज धैर्य और संयम से कार्य करें। आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत हैं। नौकरी में उन्नति के अवसर मिल सकते हैं। परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। उपायः शनि मंत्र का जप करें।

मकर राशि

आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा। करियर में प्रगति होगी तथा मान-सम्मान बढ़ेगा। धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा। उपायः काले तिल बहते जल में प्रवाहित करें।

कुंभ राशि

आज नई योजनाओं पर कार्य आरंभ कर सकते हैं। व्यापार में लाभ होगा और रुके हुए कार्य पूरे होंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा। यात्रा शुभ रहेगी। उपायः शनिदेव को नीले पुष्प अर्पित करें।

मीन राशि

आज आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। आर्थिक लाभ के योग हैं। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है। उपायः जरूरतमंदों को कंबल या वस्त्र दान करें।

-ज्योतिर्विद आचार्य विवेक शास्त्री जी
8000052721

निरोगी तन, निर्मल मन और जागृत आत्मा के संदेश संग

संत निरंकारी मिशन का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

दिल्ली,निरोगी तन, निर्मल मन और जागृत आत्मा के पावन संकल्प को साकार रूप देते हुए संत निरंकारी मिशन अंर्तराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक व्यापक योग एवं आध्यात्मिक चेतना अभियान का आयोजन कर रहा है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन आशीर्वाद एवं दूरदर्शी मार्गदर्शन में संचालित यह प्रेरणादायी अभियान मानव कल्याण, समग्र स्वास्थ्य और आत्मिक उत्थान की दिशा में एक सार्थक प्रयास है।

सतगुरु माता जी का प्रेरक संदेश - स्वस्थ मन, सहज जीवन इस सत्य को प्रतिपादित करता है कि जीवन की वास्तविक समृद्धि केवल शारीरिक स्वास्थ्य में नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक जागरूकता में निहित है। सतगुरु माता जी के अनुसार मानव शरीर परमात्मा की अनुपम देन है, जिस-ाकी देखभाल और सुदृढ़ता व्यक्ति को अपने आध्यात्मिक, सामाजिक एवं मानवीय उत्तरदायित्वों का श्रेष्ठ निर्वहन करने में सक्षम बनाती है। यह अभियान योग को मात्र शारीरिक व्यायाम न मानकर, आत्मबोध, आंतरिक शांति, मानवीय एकता और विश्वबंधुत्व की भावना को विकसित करने वाली एक समग्र जीवन साधना के रूप में अपनाने का संदेश देता हैइसी प्रेरणास्रोत भावना के अंतर्गत संत निरंकारी मिशन द्वारा रविवार, 21 जून 2026 को प्रातः 6:00 बजे भारतवर्ष के 1500 से अधिक केंद्रों पर एक साथ योग सत्र आयोजित किए जाएंगे। मिशन की विभिन्न शाख-ाओं में स्थानीय योग प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में खुले मैदानों एवं पार्कों में आयोजित इन कार्यक्रमों में श्रद्धालु, सेवादल स्वयंसेवक एवं स्थानीय नागरिक उत्साहपूर्वक सहभागी बनेंगे

इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंर्तराष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग है। यह संदेश हमें स्मरण कराता है कि वास्तविक स्वास्थ्य केवल रोग मुक्त शरीर का नाम नहीं, बल्कि मानसिक स्थिरता, भावनात्मक परिपक्वता, सामाजिक समरसता और आध्यात्मिक जागरूकता का समन्वित स्वरूप है। इसी दृष्टिकोण को अपनाते हुए संत निरंकारी मिशन योग को जीवन में संतुलन, सकारात्मकता और आत्मबोध का प्रभावी माध्यम मानकर समाज में जागरूकता का प्रसार कर रहा है।संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के सचिव जोगिन्दर सुखीजा ने बताया कि वर्ष 2015 से फाउंडेशन द्वारा योग दिवस का राष्ट्रव्यापी अभियान नियमित रूप से संचालित किया जा रहा है। योग भारत की प्राचीन एवं गौरवशाली धरोहर है, जो केवल शरीर को सशक्त ही नहीं बनाती, बल्कि मन को स्थिरता, विचारों को सकारात्मकता और आत्मा को चेतना प्रदान करती है। इसके नियमित अभ्यास से तनाव एवं जीवनशैली संबंधी चुनौतियों पर नियंत्रण प्राप्त कर व्यक्ति आत्मिक संतोष, मानसिक प्रफुल्लता और सामाजिक सद्भाव की दिशा में अग्रसर होता है।वर्तमान समय की व्यस्त और चुनौतीपूर्ण जीवनशैली में संत निरंकारी मिशन द्वारा ऐसे जनहितकारी प्रयासों का मूल उद्देश्य लोगों को अपने सर्वांगीण कल्याण के प्रति जागरूक करना है, ताकि वे योग को दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाकर स्वस्थ, संतुलित, ऊर्जावान एवं आनंदमय जीवन की ओर अग्रसर हो सकें।

नॉनवेज दुकानों को स्थानांतरित करने की मांग, हिंदू क्रांति दल ने दी आंदोलन की चेतावनी

हरिद्वार। हिंदू क्रांति दल ने नगर निगम के नगर आयुक्त नंदन कुमार को ज्ञापन सौंपकर ज्वालापुर क्षेत्र में संचालित नॉनवेज दुकानों को सराय रोड स्थित एक्कड़ क्षेत्र में बनी नई दुकानों में स्थानांतरित करने की मांग की है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि 10 दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं की गई तो नगर निगम कार्यालय के समक्ष धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।ज्ञापन में कहा गया है कि नगर निगम बोर्ड की बैठक में पूर्व में ही नॉनवेज कारोबार को सराय रोड एक्कड़ क्षेत्र में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। इसके बावजूद लंबे समय से इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि लगभग 60 दुकानें बनकर तैयार हैं।हिंदू क्रांति दल ने आरोप लगाया कि धर्मनगरी के ज्वालापुर क्षेत्र में बिना अनुमति के लगातार पशुओं का वध किया जा रहा है, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। संगठन ने मांग की कि सभी नॉनवेज दुकानों को निर्धारित स्थान पर शीघ्र स्थानांतरित किया जाए।ज्ञापन सौंपने वालों में प्रदेश सचिव कैप्टन विपिन जोशी, जिला अध्यक्ष राजेश चौहान उर्फ बक्शी, युवा मोर्चा अध्यक्ष कमल उनियाल, जिला कोषाध्यक्ष विशाल चौहान, राजेंद्र सिंह और अजय थापा सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल रहे।

नाबालिग बच्ची के यौन शोषण रैकेट का भंडाफोड़, आरोपी हुए गिरफ्तार

नवघर पुलिस थाने की बड़ी कामयाबी

मुंबई (मीरा भाइंदर) नवघर पुलिस ने एक संगठित मानव तस्करी और बाल यौन शोषण रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें वह मुख्य आरोपी भी शामिल है, जिसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म के लिए 50,000 अदा किए थे। बहु-राज्यीय पुलिस अभियान के बाद आखिरकार उसे दबोचा गया।

कैसे खुला मामला?

यह मामला 3 मार्च 2026, होली के दिन उजागर हुआ, जब भायंदर में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्यरत संजय देवनारायण गुप्ता (उम्र 54) ने नवघर पुलिस स्टेशन में एक नाबालिग बच्ची के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

जब बच्ची को ढूंढ निकाला गया, तो महिला पुलिसकर्मियों के समक्ष उसने जो बयान दिया, जिसने पुलिस को भी हिलाकर रख दिया।जांच में सामने आया कि संजय गुप्ता और उनकी पत्नी मधू गुप्ता ने पीड़िता के परिवार की आर्थिक मजबूरी का फायदा उठाया। बच्ची को हरियाणा से भायंदर लाते समय शिक्षा और देखभाल का वादा किया गया, लेकिन यहां पहुंचते ही उसे कई लोगों द्वारा यौन शोषण का शिकार बनाया गया।

शोषण का घिनौना जाल

मधू गुप्ता के मोबाइल फोन की जांच में कई महिलाओं की तस्वीरें और वित्तीय लेन-देन के रिकॉर्ड मिले, जो यह साबित करते हैं कि दंपती के आवास से ही एक सुनियोजित देहव्यापार रैकेट संचालित हो रहा था।पीड़िता को मसाज सेवा के नाम पर ग्राहकों के पास भेजा जाता था। डोंबिवली, बदलापूर, कुरार, अंबरनाथ, और उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से ग्राहकों को बुलाकर उससे दुराचार कराया गया। कई ग्राहकों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

एलआईसीवाला — एक दरिंदे का असली चेहरा

इस पूरे रैकेट का मुख्य सूत्रधार सविलयाप्रसाद श्रीवास्तव उर्फ एलआईसीवाला (उम्र 61) निकला, जिसने पीड़िता के साथ पहली बार दुष्कर्म करने के लिए 50,000 की रकम अदा की थी।पुलिस की विशेष टीम उसे पकड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के शहागंज तक पहुंची, लेकिन पुलिस की भनक लगते ही वह फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी निगरानी और मुखबिर तंत्र की मदद से उसका पीछा जारी रखा। जैसे ही सूचना मिली कि आरोपी मालाड से भाइंदर के बीच मंडरा रहा है – पुलिस ने जाल बिछाया और उसे धर दबोचा।इस रैकेट के पूरे नेटवर्क की जांच नवघर पुलिस द्वारा जारी है।

उपायुक्त जोन 1 राहुल चव्हाण ने कहा, नाबालिगों के यौन शोषण के प्रति हमारी नीति जीरो टॉलरेंस की है। आरोपियों ने एक गरीब बच्ची की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे दो राज्यों के पार तस्करी कर बेरहमी से उसका शोषण किया। हमारी टीम ने दो राज्यों में पीछा कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई एक स्पष्ट संदेश है — बच्चों का शिकार करने वालों को कहीं भी पनाह नहीं मिलेगी।

योग शिक्षकों ने सरकार पर लगाया उपेक्षा का आरोप

पौड़ी गढ़वाल। योग दिवस पर आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में सेवारत योग शिक्षक काला फीता बांधकर विरोध जताएंगे। सम्मानजनक वेतन देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर योग शिक्षकों ने सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। योग शिक्षकों का कहना है कि प्रदेश में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद योग शिक्षक नियमित बेहतर सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन उनकी उपेक्षा की जा रही है। उन्हें सम्मानजनक वेतन तक नहीं दिया जा रहा है। केवल पारिश्रमिक दिया जा रहा है। उन्होंने योग आयोग के गठन की मांग भी की है।योग अनुदेशक संघ की बैठक में संघ के पूर्व जिलाध्यक्ष विजय रतूड़ी ने कहा कि उत्तराखंड के समस्त आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में 500 योग शिक्षक तैनात हैं। जनपद पौड़ी में 68 योग शिक्षक सेवारत हैं। कहा कि योग शिक्षकों की नियुक्ति को आगामी 12वें विश्व योग दिवस पर 3 वर्ष 41 दिन की सेवाएं पूर्ण कर रहे हैं।

फीफा वर्ल्ड कप: कनाडा और कतर मुकाबले में बवाल

मैच के बाद मैदान पर भिड़े दोनों टीमों के खिलाड़ी

नई दिल्ली। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कनाडा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कतर को एकतरफा मुकाबले में 6-0 से हराया। वैंकूवर के बीसी प्लेस स्टेडियम में कनाडा टीम का प्रदर्शन दमदार रहा।

हालांकि, मैच के आखिरी सीटी बजने के बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच मैदान पर झड़प देखने को मिली। दरअसल, यह झड़प मैच खत्म होने के तुरंत बाद शुरू हुई। मैच के बाद कनाडा के मुख्य कोच जेसी मार्श कतर के मैनेजर जूलन लोपेटेगुई से हैंडशेक करने पहुंचे, लेकिन इसी दौरान दोनों के बीच बहस हो गई। कनाडा के कोच का बेरुखी भरा बर्ताव बेंच पर बैठे कतर के खिलाड़ियों को रास नहीं आया। इसके बाद अचानक से दोनों टीमों के खिलाड़ियों और स्टाफ सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई,जो धक्का-मुक्की में तब्दील हो गई। सुरक्षाकर्मियों की मदद से दोनों टीमों के खिलाड़ियों को अलग किया गया। माना जा रहा है कि कनाडा के खिलाड़ी टीम के मिडफील्डर इस्माइल कोन को कतर के प्लेयर असिम मदीबो द्वारा चोटिल किए जाने से काफी गुस्से में थे। इसी गुस्से के कारण यह पूरा विवाद शुरू हुआ, जो धक्का-मुक्की तक जा पहुंचा। दूसरे हाफ की शुरूआत में असिम मदीबो के खतरनाक टैकल पर इस्माइल कोन बुरी तरह से चोटिल हुए और उन्हें स्ट्रेचर की मदद से मैदान से बाहर लेकर जाना पड़ा। इस्माइल को दर्द से तड़पता देख कनाडा के खिलाड़ी भावुक नजर आए।

भारत की नजरें 3-0 की क्लीन स्वीप पर

चेन्नई। भारत शनिवार को एमए चिदंबरम स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे में जब जीतेगा, तो उसकी नजर सीरीज में जबरदस्त क्लीन स्वीप करने पर होगी। पहले दो मैचों में बड़ी जीत के साथ उसने तीन मैचों की सीरीज पहले ही 2-0 की अपराजेय बढ़त बनाकर अपने नाम कर ली है। मेजबान टीम पूरे दौरे में जबरदस्त फॉर्म में रही है, जिसकी शुरूआत धर्मशाला में सात विकेट से जीत से हुई और फिर लखनऊ में 170 रन की जबरदस्त जीत हासिल की, जहाँ उसने पहले बैटिंग करते हुए 400 रन का आंकड़ा पार किया। इन नतीजों ने भारत की बैटिंग की गहराई और बॉलिंग कंट्रोल को दिखाया है, जिससे अफगानिस्तान के पास सीरीज में वापसी करने के लिए बहुत कम मौके बचे हैं। भारत का टॉप ऑर्डर सबसे खास रहा है, जिसकी कप्तानी कप्तान शुभमन गिल कर रहे हैं, जिन्होंने लगातार दो असरदार पारियों के साथ अपना मजबूत वनडे रन जारी रखा है। उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप और टॉप पर तेजी से रन बनाने ने बड़े टोटल के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जबकि ईशान किशन ने दूसरे वनडे में सेंचुरी सहित जबरदस्त सपोर्ट दिया है।

सीनियर बैट्समैन रोहित शर्मा और केएल राहुल ने स्टेबिलिटी और फिनिशिंग स्ट्रेंथ जोड़ी है, जबकि इंडिया ने पूरी सीरीज में कॉम्बिनेशन के साथ एक्सपेरिमेंट किया है। सीरीज पहले ही पक्की हो चुकी है, इंडिया फिर से प्लेयर्स को रोटेट कर सकता है, जिससे यंग ऑप्शन्स को मौके मिलेंगे और साथ ही एक मजबूत कोर भी बना रहेगा। बॉल से भी इंडिया उतना ही असरदार रहा है। लेफ्ट-आर्म पेसर अर्शदीप सिंह ने लगातार ब्रेकथ्रू देकर पेस अटैक को लीड किया है, जबकि स्पिनर कुलदीप यादव ने अपनी वैरिएशन से बीच के ओवर्स को कंट्रोल किया है। सपोर्टिंग बॉलर्स ने भी खास मौकों पर मदद की है, जिससे यह पक्का हुआ कि अफगानिस्तान शायद ही कभी मोमेंटम बना पाया हो। इस बीच, अफगानिस्तान दोनों डिपार्टमेंट में स्ट्रगल करने के बाद आखिरी वनडे में एक मजबूत फिनिश की तलाश में उतरेगा। उनकी बैटिंग काफी हद तक ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज पर डिपेंड रही है, जो उनके सबसे खतरनाक प्लेयर रहे हैं और उन्होंने सीरीज में पहले सेंचुरी बनाई थी। हालांकि, मिडिल ऑर्डर से सपोर्ट की कमी ने बार-बार उनकी प्रोग्रेस को रोका है। अगर अफगानिस्तान को एक कॉम्पिटिटिव टोटल बनाना है तो बैट्समैन इब्राहिम जदरान और कैप्टन हशमतुल्लाह शाहिदी से इनिंग्स को संभालने की उम्मीद होगी, जबकि एक्सपीरियंस्ड स्पिनर राशिद खान बॉल से उनके लिए मेन खतरा बने हुए हैं। चेपॉक की पारंपरिक रूप से धीमी पिच पर अफगानिस्तान के स्पिन अटैक को मदद मिल सकती है, खासकर जब पिच घिस जाएगी। चेपॉक में चेन्नई की पिच से उम्मीद है कि शुरूआत में बैलेंस्ड मुकाबला होगा, फिर मैच आगे बढ़ने पर यह धीमी हो जाएगी और स्पिन को मदद मिलेगी। पहले, पहले बैटिंग करने वाली टीमें अक्सर वेन्यू पर टारगेट सेट करना पसंद करती थीं, लेकिन हाल के मैचों ने यह भी दिखाया है कि हालात के हिसाब से लाइट में भी टारगेट चेज किया जा सकता है। सीरीज पहले ही तय हो चुकी है, इसलिए आखिरी वनडे स्टैंडिंग से ज्यादा गर्व और मोमेंटम के लिए जरूरी है। भारत अपना दबदबा बनाए रखने और क्लीन स्वीप करने की कोशिश करेगा, जबकि अफगानिस्तान ज्यादा कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस देने और भारतीय जमीन पर 3-0 से हार से बचने की कोशिश करेगा।

अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे के लिए भारतीय टीम में शामिल हुए हर्षित राणा

नई दिल्ली। अफगानिस्तान के खिलाफ खेली जा रही वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले से पहले हर्षित राणा को भारतीय टीम में शामिल किया गया है। हर्षित ने अपना रिहैब पूरा कर लिया है और वह चेन्नई में टीम से जुड़ेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने हर्षित को तीसरे वनडे के लिए भारतीय टीम में शामिल किए जाने की जानकारी दी है। बीसीसीआई ने बताया कि हर्षित ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में अपना रिहैब पूरा कर लिया है और वह अब पूरी तरह से फिट हैं। हर्षित को आयरलैंड-इंग्लैंड और एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय टी20 टीम में भी शामिल किया गया है।

सार समाचार

महिला टी20 विश्व कप: एलेने-मैथ्यूज की शानदार गेंदबाजी, वेस्टइंडीज ने स्कॉटलैंड को 7 रनों से हराया

नई दिल्ली। महिला टी20 विश्व कप 2026 में वेस्टइंडीज का शानदार प्रदर्शन जारी है। टूर्नामेंट के 12वें मुकाबले में कैरेबियाई टीम ने लीड्स (इंग्लैंड) के हेडिंग्ले क्रिकेट स्टेडियम में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्कॉटलैंड को 7 रनों से हराया। वेस्टइंडीज से मिले 154 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए स्कॉटलैंड की पूरी टीम 146 रन बनाकर ऑलआउट हुई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी स्कॉटलैंड की शुरूआत अच्छी रही। डार्सी कार्टर और कैथरीन फ्रेजर ने मिलकर पहले विकेट के लिए 51 रनों की अहम साझेदारी निभाई। फ्रेजर को 20 रनों के स्कोर पर हेली मैथ्यूज ने पवेलियन भेजा। इसके बाद कप्तान कैथरीन ब्राइस बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकीं और बिना खाता खोले आउट हो गईं। सारा ब्राइस भी सिर्फ 4 और मेगन मैककोल 1 रन बनाकर आउट हुईं। डार्सी कार्टर ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 62 गेंदों में 8 चौकों की मदद से 59 रन बनाए, हालांकि उन्हें दूसरे छोर से बाकी बल्लेबाजों का साथ नहीं मिल सका। अंत के ओवरों में ऐल्सा लिस्टर ने 25 गेंदों में 33 रनों की पारी खेली, लेकिन वह टीम को जीत दिलाने में नाकाम रहीं। गेंदबाजी में वेस्टइंडीज की ओर से कप्तान हेली मैथ्यूज ने 19 रन देकर 3 विकेट चटकाए। वहीं, आलिया एलेने ने 11 रन खर्च करते हुए 3 विकेट अपने नाम किए। 18 ओवर के बाद स्कॉटलैंड 132 के स्कोर पर 5 विकेट मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी, लेकिन टीम ने अपने अगले पांच विकेट सिर्फ 14 रन जोड़कर गंवा दिए। इससे पहले, वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 153 रन लगाए। टीम की शुरूआत अच्छी नहीं रही। कियाना जोसेफ सिर्फ 13 रन बनाकर आउट हुईं। वहीं, कप्तान हेली मैथ्यूज 14 रन बनाने के बाद फ्रेजर की गेंद पर क्लीन बोल्ड हुईं। डिएंड्रा डॉटिन (14 रन) और जाहजारा क्लैक्सटन (16 रन) भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकीं। शेमेन कैम्पबेल ने 26 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 36 रन बनाए। अंत के ओवरों में स्टेफनी टेलर ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए महज 19 गेंदों में 47 रनों की नाबाद पारी खेली। अपनी इस पारी में टेलर ने 4 चौके और 3 छक्के लगाए।

रग्बी प्रीमियर लीग: बेंगलुरु ब्रेवहार्ट्स ने दिल्ली रेड्ज को 38-28 से हराया, चेन्नई बुल्स-दिल्ली रेड्ज का मैच ड्रॉ

हैदराबाद। रग्बी प्रीमियर लीग के सीजन 2 के तीसरे दिन पुरुषों के वर्ग में एक रोमांचक मुकाबले खेला गया, जिसमें बेंगलुरु ब्रेवहार्ट्स ने दिल्ली रेड्ज को 38-28 से शिकस्त देकर जबरदस्त वापसी की। वहीं, महिलाओं के मुकाबले में चेन्नई बुल्स और दिल्ली रेड्ज के बीच मैच 26-26 से ड्रॉ रहा। बेंगलुरु ब्रेवहार्ट्स की पुरुष टीम ने अकुइला रोकोलिसोआ के जरिए मजबूत शुरूआत की, लेकिन पैट्रिक ओडोंगो के इंटरसेप्शन ट्राई ने जल्द ही दिल्ली रेड्ज को बराबरी पर ला दिया। इसके बाद शिल्टन वैन विक ने दो बार स्कोर करके बेंगलुरु की बढ़त फिर से हासिल की, लेकिन फिर लुसियानो गोंजालेज और ओडोंगो ने रेड्ज को बढ़त दिलाने में मदद की। दूसरे हाफ की शुरूआत में ही वैन विक ने अपनी हैट्रिक पूरी की, जबकि गोंजालेज ने एक और शानदार व्यक्तिगत ट्राई से जवाब दिया। नगारोही मैकगार्वी ने ब्रेवहार्ट्स को आगे रखा और फिर आखिरी क्वार्टर में रयान एप्स के लॉन्ग-रेंज प्रयास ने जीत पक्की कर दी। हैदराबाद के गाचीबोवली स्थित गंती मोहना चंद्र बालयोगी एथलेटिक स्टेडियम में खेले गए महिलाओं के मुकाबले में लक्ष्मी ओराओन ने मुंबई ड्रीमर्स को बेहतरीन शुरूआत दिलाई, लेकिन सवाना बॉडर ने ट्राई और कन्वर्जन के जरिए चेन्नई बुल्स को आगे कर दिया।

अंतिम मिनटों में टूटा भारत का सपना, जर्मनी ने एफआईएच हॉकी प्रो लीग में 2-1 से हराया

रॉटरडैम । भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एफआईएच हॉकी प्रो लीग 2025-26 के रॉटरडैम चरण में शुक्रवार को मौजूदा विश्व चैम्पियन जर्मनी के खिलाफ शानदार संघर्ष किया, लेकिन अंतिम क्षणों में मैच हाथ से निकल गया और भारत को 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। भारत के लिए जुगराज सिंह ने अपने 100वें अंतरराष्ट्रीय मुकाबले को यादगार बनाते हुए गोल दागा, लेकिन जर्मनी ने अंतिम चार मिनट में दो गोल कर मुकाबला अपने नाम कर लिया। मुकाबले की शुरूआत में भारतीय टीम ने आक्रामक खेल दिखाया और गेंद पर नियंत्रण बनाए रखते हुए जर्मनी को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। मजबूत रक्षापंक्ति के कारण विश्व चैम्पियन टीम पहले हाफ में स्पष्ट अवसर नहीं बना सकी। दूसरे क्वार्टर में भारत ने तेज दबाव बनाते हुए जर्मनी को लगातार गलती करने पर मजबूर किया। अभिषेक ने भारत के लिए एक अच्छा मौका बनाया, लेकिन टीम बढ़त हासिल नहीं कर सकी। तीसरे क्वार्टर में भारत को पहला पेनाल्टी कॉर्नर मिला और जुगराज सिंह ने 38वें मिनट में जोरदार ड्रैग फ्लिक लगाकर भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी। यह उनके करियर के 100वें अंतरराष्ट्रीय मैच का खास पल बन गया। जर्मनी ने तीसरे क्वार्टर के अंत में लगातार हमले किए, लेकिन भारतीय गोलकीपर मोहित एचएस ने शानदार बचाव करते हुए बढ़त कायम रखी।

महिला टी20 विश्व कप: टीम इंडिया की स्टार गेंदबाज श्रेयंका पाटिल टूर्नामेंट से बाहर

नई दिल्ली। महिला टी20 विश्व कप के दौरान भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है। भारतीय टीम की स्टार स्पिन गेंदबाज श्रेयंका पाटिल टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। उनके टखने की चोट की वजह से महिला टी20 विश्व कप 2026 से बाहर होना पड़ा। बुधवार को नीदरलैंड्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले के दौरान लगी थी। श्रेयंका को चोटिल होने के बाद स्ट्रेचर की मदद से मैदान से बाहर ले जाना पड़ा था। नीदरलैंड्स के खिलाफ पावरप्ले का आखिरी ओवर डालते हुए उनका टखना बुरी तरह से मुड़ गया था, जिसके बाद उन्हें तुरंत ग्राउंड छोड़कर जाना पड़ा था। इस चोट के बाद श्रेयंका मैच में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए नहीं लौट सकी थीं।

एमिलियो गे का अर्धशतक, इंग्लैंड ने पहली पारी में बनाये छह विकेट पर 222 रन

द ओवर। एमिलियो गे (53) और कप्तान जो रूट (46) रनों की पारियों के दम पर इंग्लैंड ने दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने के समय न्यूजीलैंड के खिलाफ छह विकेट पर 222 रन बना लिये है। और वह अभी भी न्यूजीलैंड के पहली पारी में बनाये गये स्कोर से 169 रन पीछे है। न्यूजीलैंड को 391 रनों पर सिमटने के बाद बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड को पहला झटका आठवें ओवर में बेन डकेट (36) रनआउट के रूप में लगा। 17वें ओवर में स्मिथ ने जेकब बेथेल (नौ) रन का शिकार कर लिया। इसके बाद कप्तान जो रूट ने एमिलियो गे के साथ पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 74 रन जोड़े। 36वें ओवर में विलियम्स ओरूर्क ने एमिलियो गे को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। एमिलियो गे ने 114 गेंदों में नौ चौके लगाते हुए (53) रनों की पारी खेली। 41वे ओवर में मैट हेनरी ने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे जो रूट (46) को पगबाधा आउट किया। उन्होंने अपनी पारी में 57 गेंदों का सामना किया और आठ चौके लगाये। हैरी ब्रूक और जेम्स रू (24-24) रन बनाकर पांचवें और छठें विकेट के रूप में आउट हुये। दूसरे

व्यापार

सार समाचार

अमेरिका-ईरान शांति समझौते से भारत को बड़ी आर्थिक राहत, पेट्रोल-डीजल और एलपीजी समेत रोजमर्रा की चीजों के दाम होंगे सस्ते

नई दिल्ली। अमेरिका और ईरान के बीच हुए ऐतिहासिक शांति समझौते से भारत के लिए आर्थिक राहत के द्वार खुल गए हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य से कच्चे

तेल और गैस की आपूर्ति सामान्य होने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें गिरने की प्रबल संभावना है। इसके प्रभाव से भारत में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस (एलपीजी) के दाम कम होंगे, जिससे आम जनता को महंगाई से बड़ी राहत मिलेगी। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का सकारात्मक असर न केवल परिवहन लागत पर, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर भी दिखेगा। डीजल सस्ता होने से माल ढुलाई का खर्च घटेगा, जिससे फल-सब्जियों और खाद्यान्न की कीमतों में कमी आएगी। साथ ही, पेट्रोकेमिकल्स सस्ते होने से साबुन, डिटर्जेंट, प्लास्टिक पैकेजिंग, रेडीमेड कपड़े और सौंदर्य प्रसाधन जैसी दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी सस्ती हो जाएंगी। इस समझौते से दवाइयों, सिरिंज और मेडिकल उपकरणों की निर्माण लागत में कमी आएगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं और सस्ती होंगी। इसके अतिरिक्त, विमानन ईंधन के दाम घटने से हवाई सफर सस्ता हो सकता है। महंगाई दर में गिरावट आने से आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावना बढ़ेगी, जिससे आम लोगों के होम, कार और पर्सनल लोन की ईएमआई का बोझ भी कम होगा।

आईटी सेक्टर में भारी बिकवाली से सेंसेक्स 800 अंक लुढ़का

मुंबई। आईटी सेक्टर की कंपनियों में भारी बिकवाली के दबाव में शुक्रवार को शुरूआती कारोबार में बीएसई का सेंसेक्स 800 अंक गिर गया लगातार पांच दिन की तेजी के बाद सेंसेक्स 557.12 अंक टूटकर 76,852.86 अंक पर खुला। आईटी कंपनियों में बिकवाली से इसकी गिरावट और बढ़ी। खबर लिखे जाते समय यह 811.19 अंक (1.05 प्रतिशत) नीचे 76,598.79 अंक पर रहा। अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी एक्सेंचुअर के इस साल का राजस्व अनुमान घटाने के बाद उसका शेयर गुरुवार को 18 प्रतिशत टूट गया। अमेरिका में सूचीबद्ध भारतीय आईटी कंपनियों में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली और इसका असर आज घरेलू बाजार पर दिखा। इस समय इंफोसिस का शेयर आठ प्रतिशत से अधिक की गिरावट में है। टीसीएस का शेयर छह फीसदी और टेक महिंद्रा तथा एचसीएल टेक्नोलॉजीज का पांच प्रतिशत से अधिक नीचे चल रहा है। सेंसेक्स में इन चार आईटी कंपनियों के बाद सबसे अधिक गिरावट एचडीएफसी बैंक, इटरनल, टाटा स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा और हिंदुस्तान यूनीलिवर के शेयरों में है। एनटीपीसी, एयरटेल, सन फार्मा, रिलायंस इंडस्ट्रीज और ट्रेंट के शेयर फिलहाल बढ़त में हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक 176.80 अंक गिरकर 23,991.20 अंक पर खुला। खबर लिखे जाते समय यह 220.85 अंक यानी 0.91 प्रतिशत उतरकर 23,947.15 अंक पर था। कमजोर निवेश धारणा से वृहत बाजार में भी बिकवाली हावी है। स्वास्थ्य और फार्मा को छोड़कर सभी सेक्टर दबाव में हैं। आईटी के साथ टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद, रियल्टी, ऑटो, वित्त, बैंकिंग और एफएमसीजी समूहों के सूचकांक भी लाल निशान में हैं।

जियो आईपीओ का इंतजार खत्म, 27 करोड़ शेयरों तक का फ्रेश इश्यू लाएगी कंपनी

- जियो प्लेटफॉर्म्स के बोर्ड ने आईपीओ दस्तावेज को मंजूरी दी
- सेबी, बीएसई और एनएसई के पास दाखिल होगा ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस

मुंबई। देश के सबसे चर्चित क्लब में से एक माने जा रहे जियो प्लेटफॉर्म्स के सार्वजनिक निर्गम की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने स्टॉक एक्सचेंजों को दी जानकारी में बताया कि जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के बोर्ड ने 27 करोड़ इक्विटी शेयरों तक के फ्रेश इश्यू को मंजूरी दी है। इन शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर होगी। इश्यू प्राइस बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के जरिए तय किया जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 49वीं वार्षिक आम बैठक में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश डी. अंबानी ने बताया कि जियो प्लेटफॉर्म्स के बोर्ड ने ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस को मंजूरी दे दी है और इसे आज सेबी के पास दाखिल किया जाएगा। कंपनी ने बीएसई और एनएसई को दी सूचना में भी कहा है कि यह आईपीओ आवश्यक नियामकीय मंजूरियों के अधीन रहेगा। एजीएम में मुकेश अंबानी ने इसे रिलायंस परिवार और उसके लाखों शेयरधारकों के लिए भावनात्मक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि रिलायंस और उसके शेयरधारकों का संबंध गर्व, विश्वास, सम्मान और साझा विकास पर आधारित एक गहरा और पवित्र रिश्ता है। मुकेश अंबानी ने कहा, जियो की प्रस्तावित लिस्टिंग दुनिया को यह दिखाएगी कि भारत वैश्विक स्तर, वैश्विक क्षमता और वैश्विक मूल्य वाली टेक्नोलॉजी कंपनियां बना सकता है। मैं आपको और सभी संभावित नए निवेशकों को आश्वस्त करता हूं कि जियो का भविष्य और भी उज्ज्वल है। उन्होंने यह भी कहा कि इस वर्ष वैल्यू क्रिएशन का सबसे महत्वपूर्ण मील का पत्थर जियो का निकट भविष्य में आने वाला आईपीओ है। उनके अनुसार, यह रिलायंस शेयरधारकों के लिए बड़ा वैल्यू अनलॉक करेगा और नए निवेशकों के लिए आकर्षक निवेश अवसर पेश करेगा। जियो ने पिछले दस वर्षों में भारत के डिजिटल परिदृश्य को बदलने में निर्णायक भूमिका निभाई है। मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो ने जब अपनी यात्रा शुरू की उस समय वॉइस महंगी थी, डेटा महंगा था और स्पीड कमजोर थी। जियो ने वॉइस को मुफ्त और हाई-स्पीड डेटा को किफायती बनाया, आज जियो का यूजर बेस 52.4 करोड़ को पार कर चुका है। कंपनी का 5जी सब्सक्राइबर बेस 26.8 करोड़ से अधिक है, जो चीन के बाहर किसी एक देश के ऑपरेटर के लिए सबसे बड़ा है। जियोएयरफाइबर भी 1.3 करोड़ कनेक्टेड होम्स तक पहुंच गया है और जियो दुनिया का सबसे बड़ा फिक्स्ड वायरलेस ब्रॉडबैंड ऑपरेटर बन गया है। जियो की अगली ग्रोथ यात्रा पांच प्रतिबद्धताओं पर आधारित होगी। इनमें जियो टू 5जी को भारत की अगली डिजिटल छलांग की नींव बनाना, जियोएयरफाइबर के जरिए हाई-स्पीड होम ब्रॉडबैंड को देश के हर हिस्से तक पहुंचाना, भारतीय उद्यमों और छोटे कारोबारों को डिजिटल बनाना, हर जगह और हर व्यक्ति तक एआई पहुंचाना और भारत की टेक्नोलॉजी को दुनिया तक ले जाना शामिल है। जियो आईपीओ की औपचारिक प्रक्रिया शुरू होना केवल एक लिस्टिंग इवेंट नहीं है। यह भारत की टेक्नोलॉजी क्षमता, रिलायंस शेयरधारकों के वैल्यू अनलॉक और जियो की अगली ग्रोथ यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है।

रिलायंस ने एफएमसीजी कारोबार को 2030 तक एक लाख करोड़ रुपये पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा

मुंबई। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने एफएमसीजी कारोबार को विनिर्माण और निर्यात से जोड़कर वित्त वर्ष 2029-30 तक एक लाख करोड़ रुपये पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 49वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए रिलायंस रिटेल की प्रबंध निदेशक ईशा अंबानी पिरामल ने कहा कि रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (आरसीपीएल) की निकट अवधि की महत्वाकांक्षा वित्त वर्ष 2030 तक एक लाख करोड़ के राजस्व तक पहुंचने की है। कंपनी भविष्य में देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनियों में से एक बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है और भविष्य में वैश्विक प्लेटफॉर्म पर अपनी मजबूत उपस्थिति बनाना चाहती है। वित्त वर्ष 2025-26 में आरसीपीएल का कुल राजस्व 22,000 करोड़ रुपये रहा था।

निर्यात और फ्रेंचाइज बिक्री के जरिये उसके उत्पाद 40 से अधिक देशों में मौजूद हैं। रिलायंस रिटेल ने भी 31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही में 20 हजार स्टोर का आंकड़ा पार कर लिया। पिछले वित्त वर्ष उसका कुल राजस्व 3,70,026 करोड़ रुपये रहा। श्रीमती पिरामल ने कहा कि रिलायंस रिटेल किसानों और आपूर्ति श्रृंखला के भागीदारों के साथ अपनी साझेदारी को भी मजबूत कर रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी ने 40 हजार से अधिक किसानों के साथ मिलकर 110 कलेक्शन सेंटर के जरिये करीब 5.7 लाख टन ताजे फल और सब्जियां खरीदीं।

उन्होंने कहा कि रिलायंस अब उपभोक्ता कारोबार को विनिर्माण और निर्यात से जोड़ने की तैयारी कर रही है। कंपनी पेय पदार्थों, रोजमर्रा की जरूरत के सामान, फूड पार्क्स, परिधान और किफायती इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़े पैमाने पर विनिर्माण प्लेटफॉर्म बना रही है। अगले तीन साल में आरसीपीएल एकीकृत फूड पार्क्स के नेटवर्क पर 30,000 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश करेगी।

कोयला गैसीकरण भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण: रेड्डी

मुंबई। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने बृहस्पतिवार को कहा कि कोयले से गैस बनाना देश की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और इससे आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। रेड्डी ने सतही कोयला एवं लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की प्रोत्साहन योजना पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि गैसीकरण परियोजनाओं में निवेश से देश में सिनगैस, मेथनॉल, हाइड्रोजन, एथेनॉल, यूरिया और विमानन ईंधन सहित कई उत्पादों का घरेलू उत्पादन संभव होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में इन उत्पादों का बड़ी मात्रा में आयात किया जाता है, लेकिन कोयला गैसीकरण के जरिए इनका उत्पादन देश में बढ़ाया जा सकता है। इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी, आयात पर निर्भरता घटेगी और उर्वरक, इस्पात, रसायन, परिवहन एवं स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों में नयी औद्योगिक मूल्य श्रृंखलाओं का विकास होगा। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे, कोयला मंत्रालय के सचिव विक्रम देव दत्त, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, कोयला क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के प्रतिनिधि, उद्योग जगत के नेता, प्रौद्योगिकी प्रदाता, निवेशक तथा अन्य हितधारक शामिल हुए।

पांच दिन की तेजी के बाद प्रमुख सूचकांकों में गिरावट, आईटी कंपनियों पर दबाव

मुंबई। आईटी और बैंकिंग सेक्टर के दबाव में घरेलू शेयर बाजारों में पांच दिन की तेजी के बाद प्रमुख सूचकांकों में गिरावट देखी गई। बीएसई का सेंसेक्स 607.08 अंक (0.78 प्रतिशत) गिरकर 76,802.90 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक 154.90 अंक यानी 0.64 प्रतिशत नीचे 24,013.10 अंक पर बंद हुआ। पिछले कारोबारी दिवस पर दोनों सूचकांक छह सप्ताह के उच्चतम स्तर पर रहे थे। अमेरिकी शेयर बाजारों में गुरुवार को आईटी कंपनियों में हुई बिकवाली का असर आज घरेलू शेयर बाजारों आईटी सेक्टर पर देखा गया। सेंसेक्स में सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाली चार कंपनियों में सभी आईटी कंपनियां हैं। प्रमुख सूचकांकों के विपरीत वृहत बाजार में तेजी रही। निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 0.10 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 0.42 प्रतिशत ऊपर बंद हुआ। आईटी सेक्टर का सूचकांक 3.65 प्रतिशत गिर गया। रियल्टी, तेल एवं गैस, बैंकिंग, वित्त, ऑटो और एफएमसीजी सेक्टरों में भी गिरावट रही। फार्मा और स्वास्थ्य सेक्टरों के सूचकांक बढ़त में रहे। सेंसेक्स में इंफोसिस का शेयर साढ़े छह फीसदी से अधिक टूट गया। टीसीएस में साढ़े तीन फीसदी और एचसीएल टेक्नोलॉजीज तथा टेक महिंद्रा में ढाई फीसदी की गिरावट रही। एचडीएफसी बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर दो से ढाई प्रतिशत तक नुकसान में रहे। रिलायंस इंडस्ट्रीज और हिंदुस्तान यूनीलिवर के शेयर एक प्रतिशत से ज्यादा फिसल गये। कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा स्टील, एशियन पेंट्स, भारतीय स्टेट बैंक, मारुति सुजुकी, अल्ट्राटेक सीमेंट और बीईएल के शेयर भी लाल निशान में बंद हुए। इटरनल का शेयर दो प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा। भारती एयरटेल, पावरग्रिड और एनटीपीसी में एक से दो प्रतिशत तक तेजी रही। टाइटन, सन फार्मा, आईटीसी, ट्रेंट, एलएंडटी, बजाज फिनसर्व और आईसीआईसीआई बैंक के शेयर भी बढ़त में रहे।

घर पर बनाएं क्रीमी और टेस्टी कुल्फी

कुछ लोग दूध पकाते समय शुरुआत में ही दूध और फ्लेवर इस्तेमाल करने लग जाते हैं। हालांकि, ऐसा करने से बचना चाहिए। हमेशा जब दूध गाढ़ा हो जाए, तभी चीनी डालो। अगर आप शुरुआत में चीनी डालोगे तो दूध जल्दी गाढ़ा नहीं होगा। आप इसी समय इलायची, केसर, या गुलाब जल डाल सकते हो।

गर्मी का मौसम आते ही हम सभी कुछ ना कुछ ठंडा खाना चाहते हैं और इसलिए सबसे पहले याद आती है कुल्फी की। ठंडी-ठंडी और मीठी-मीठी कुल्फी खाकर बेहद मजा आ जाता है। अमूमन हम सभी बाजार से कुल्फी लाकर खाते हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो इसे घर पर भी बेहद आसानी से बना सकते हैं। हो सकता है कि आपने भी घर पर कुल्फी बनाई हो, लेकिन घर पर कुल्फी बनाने का एक नुकसान यह है कि वह बाजार जैसी क्रीमी और टेस्टी नहीं बनती है। कभी उसमें बर्फ जम जाती है, तो कभी वो बहुत सख्त हो जाती है। अगर आपने भी अक्सर इस समस्या का सामना किया है और आपको लगता है कि आप परफेक्ट कुल्फी नहीं बना सकते तो आप गलत है। दरअसल, कुछ ऐसे आसान व छोटे-छोटे हैक्स हैं, जो आपकी कुल्फी को टेस्टी व क्रीमी बनाने में मदद करते हैं।

दूध को करें गाढ़ा: अगर आप घर पर कुल्फी बना रहे हैं तो ऐसे में दूध को अच्छी तरह गाढ़ा करें और कुल्फी बनाने के लिए फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल करें। आप दूध को धीमी आंच पर 30-40 मिनट तक उबालो। साथ ही, दूध को बीच-बीच में चलाते रहो, वरना वह नीचे लग जाएगा।

चीनी और फ्लेवर सही तरह से करें इस्तेमाल

कुछ लोग दूध पकाते समय शुरुआत में ही दूध और फ्लेवर इस्तेमाल करने लग जाते हैं। हालांकि, ऐसा करने से बचना चाहिए। हमेशा जब दूध गाढ़ा हो जाए, तभी चीनी डालो। अगर आप शुरुआत में चीनी डालोगे तो दूध जल्दी गाढ़ा नहीं होगा। आप इसी समय इलायची, केसर, या गुलाब जल डाल सकते हो।

> मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करना अच्छा विचार

ड्राई फ्रूट्स को ना भूलें: कुल्फी बनाते समय ड्राई फ्रूट्स डालना ना भूलें। आप काजू, बादाम, पिस्ता बारीक कट करके डालो। साथ ही, अगर आप थोड़ा सा पेस्ट बनाकर डालोगे तो और इससे क्रीमी टेक्सचर मिलेगा।

मिल्क पाउडर का करें इस्तेमाल: अगर आपको क्रीमी कुल्फी खाना अच्छा लगता है तो ऐसे में कुल्फी तैयार करते समय मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करना अच्छा विचार है। मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करने से कुल्फी स्मूथ बनती है और इससे आइस क्रिस्टल्स नहीं बनते हैं।

बेहतर रैंकिंग के लिए महत्वपूर्ण सही रणनीति

'नीट' परीक्षा के लिए अब सिर्फ एक महीने से भी कम समय बचा है। सिलेक्शन यकीनी बनाने को हर परीक्षार्थी को गंभीरता के साथ इस दौरान 90 से 95 फीसदी अब तक पढ़े गये सिलेबस को अच्छी तरह से फिर से दोहरा लेना होगा। सही रणनीति व कुछ टिप्स इन दिनों इस्तेमाल किये जाएं तो बेहतर रैंकिंग की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं।

नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट (अंडरग्रेजुएट) यानी मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए होने वाली देश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा 'नीट' के लिए अब सिर्फ एक महीने से भी कम समय बचा है। जानकारी के मुताबिक आगामी 3 मई को पूरे भारत में नीट परीक्षा आयोजित की जायेगी। सिलेक्शन यकीनी बनाने को हर परीक्षार्थी को पूरी गंभीरता के साथ इस बचे हुए महीने में 90 से 95 फीसदी अब तक पढ़े गये सिलेबस को अच्छी तरह से फिर से दोहरा लेना होगा। इसमें रिविजन+प्रैक्टिस+एक्यूरेसी सौ फीसदी रहनी चाहिए। अगर इस तरीके से अंतिम महीने में फोकस रखेंगे, तो निश्चित रूप से रैंक हासिल कर लेंगे, जिससे नीट परीक्षा क्लियर की जा सके। कहते हैं जो छात्र अप्रैल महीने को पूरे फोकस के साथ पढ़े गये सिलेबस को दोहराने में लगाते हैं, मेडिकल एग्जाम पास करना उनके लिए आसान होता है। हालांकि कोई भी परीक्षा सिर्फ ट्रिक से नहीं पास की जा सकती, हर परीक्षा को पास करने के लिए ईमानदारी से और गहराई से सिलेबस को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। फिर भी अगर रिविजन का ढंग स्मार्ट हो, तो न केवल अपनी मेरिट बेहतर बनायी जा सकती है बल्कि टॉपर्स के ग्रुप में शामिल होने का अवसर भी हाथ लग सकता है, तो जानिये बचे हुए इस महीने को किस तरह स्मार्ट ढंग से इस्तेमाल किया जाए कि नीट परीक्षा में अच्छी रैंक के साथ पास हों।

> नीट परीक्षा में अच्छी रैंक के साथ पास हों।

रणनीति-1 : गेम चेंजर होता है बायोलॉजी का पेपर

नीट परीक्षा में पूछे गये 50 फीसदी सवाल बायोलॉजी से होते हैं। इसलिए परीक्षा बेहतर मेरिट से पास करने के लिए बायोलॉजी को अपने फोकस में लाना होगा। इसके लिए आपको सिर्फ एनसीईआरटी की छठी से 12वीं तक की किताबों पर फोकस करना होगा। टिक किये गये महत्वपूर्ण सवालों को इन दिनों में हर दिन दो से तीन बार रिविजन करना होगा। साथ ही डायग्राम, टेबल्स और उदाहरण न केवल याद रखने होंगे कि बल्कि इतने प्रभावशाली ढंग से इनका इस्तेमाल करना होगा ताकि 340 से लेकर 360 अंक तक हासिल किए जा सकें।

रणनीति-2 : केमिस्ट्री के विषय में करें स्मार्ट रिविजन

केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का प्रश्नपत्र 180 नंबर का होता है और आप उसमें 150 से 170 अंक हासिल कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आप गंभीर और बेहद प्रभावाशाली छात्र हैं। बायोलॉजी के बाद नीट एग्जाम में दूसरा महत्वपूर्ण पेपर केमिस्ट्री का ही होता है। इसकी तैयारी करते समय कुछ बातों पर सतर्कता से ध्यान देना होता है। खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हुए रिएक्शन के साथ, इस रिएक्शन का नाम पता होना भी जरूरी है। केमिस्ट्री की तैयारी करने में भी एनसीईआरटी की किताबों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। केमिस्ट्री के फार्मूला अच्छी तरह से रटें और सवाल को हाल करते समय जरूरत पड़े तो परीक्षा पुस्तिका के ही एक हिस्से में न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लें।

रणनीति-3 : रैंक बनाती है फिजिक्स

अगर बायोलॉजी नीट एग्जाम के आधे नंबर की हकदार होती है, तो फिजिक्स का पेपर रैंक बनाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। फिजिक्स के पेपर की तैयारी करते हुए हर दिन न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें, इनमें 50-60 सवाल ऐसे महत्वपूर्ण होते हैं, जिनसे दो-तीन सवाल हर बार आते हैं। फार्मूला शीट पर रिवाइज करें। कमजोर पाठों पर ज्यादा फोकस करें। फिजिक्स का पेपर भी 180 नंबर का होता है, जिसमें अगर 140 से 160 के बीच में नंबर ले आते हैं, तो मेरिट भी ठीक-ठाक बन सकती है।

रणनीति-4 : मॉक टेस्ट पर फोकस

नीट एग्जाम में नियमित रूप से मॉक टेस्ट करने से न सिर्फ टाइम मैनेजमेंट बेहतर रहता है बल्कि तैयारी भी बहुत अच्छी हो जाती है। हर हफ्ते दो से तीन फुल सिलेबस टेस्ट के मॉक टेस्ट देना परीक्षा के पहले के एक महीने में बहुत जरूरी है। यह टेस्ट ओएमआर शीट पर ही देने की प्रैक्टिस करें और हर टेस्ट के बाद तीन से चार घंटे तक अपने टेस्ट किए हुए पेपर का एनालिसिस करें और ध्यान से देखें कि कौन से सवाल लगातार गलत हो रहे हैं।

एआई नवाचार की अगली लहर का नेतृत्व

नौकरियों को समाप्त करने के बजाय, एआई उत्पादकता को बढ़ाने की संभावना रखता है। "एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की उत्पादकता बढ़ा सकता है। उन्हें प्रतिस्थापित करने के बजाय, यह उन्हें कई लोगों के काम करने और पूरी तरह नए उत्पाद व सेवाएं बनाने में सक्षम बना सकता है।

> सबसे बड़ा साझा अवसर विश्वसनीय, सुरक्षित और लागत-प्रभावी एआई सिस्टम बनाना है, जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों में अपनाया जा सके।

फरवरी 2026 में अमेरिका और भारत के शोधकर्ता और विशेषज्ञ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) में अमेरिका-भारत शोध सहयोग निर्माण पर कार्यशाला के लिए मोहाली में एकत्र हुए। इस कार्यक्रम की मेजबानी प्लाक्षा यूनिवर्सिटी ने अमेरकी दूतावास नई दिल्ली के सहयोग से की थी। इसका उद्देश्य स्पष्ट था: संवाद से आगे बढ़कर एआई अनुसंधान में स्थायी और व्यावहारिक साझेदारियां बनाना।

इस कार्यशाला ने प्रगति के साथ-साथ विकास के क्षेत्रों को भी उजागर किया। अमेरिका अग्रिम एआई अनुसंधान में अग्रणी बना हुआ है, जबकि भारत एक विशाल और कुशल प्रतिभा समूह तथा व्यापक वास्तविक-विश्व अनुप्रयोग संदर्भ प्रदान करता है। विशेषज्ञों ने सहयोग को मज़बूत करने के लिए वित्तपोषण और संस्थागत प्राथमिकताओं को और अधिक समन्वित करने के अवसरों की भी पहचान की। इन निष्कर्षों ने उन शोधकर्ताओं के साथ गहन चर्चाओं के लिए आधार तैयार किया जो अमेरिका-भारत एआई पहलों को आकार दे रहे हैं।

सहयोग का स्तर

"वास्तव में, अमेरिका-भारत सहयोग एआई में बहुत उच्च स्तर पर है," कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सैन डिएगो के कंप्यूटिंग, सूचना और डेटा विज्ञान स्कूल के विशिष्ट प्रोफेसर और डीन राजेश गुप्ता कहते हैं। "मैं यह इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं भारत में छह एआई स्कूलों के निर्माण में शामिल हूं, और अमेरिका की फाउंडेशन उन्हें मदद दे रही हैं।"

इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के प्रोफेसर राजीव बरुआ कहते हैं कि सहयोग अधिक रणनीतिक और संस्थागत होता जा रहा है। "पूरकता स्पष्ट है: अमेरिका अग्रिम अनुसंधान और वैश्विक उत्पाद पारिस्थितिकी तंत्र में गहराई प्रदान करता है, जबकि भारत व्यापक स्तर पर उत्कृष्ट प्रतिभा और विविध वास्तविक-विश्व अनुप्रयोग संदर्भ प्रदान करता है," वह कहते हैं। "सबसे बड़ा साझा अवसर विश्वसनीय, सुरक्षित और लागत-प्रभावी एआई सिस्टम बनाना है, जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों में अपनाया जा सके।"

बरुआ ने कार्यशाला से तीन प्रमुख निष्कर्षों को रेखांकित किया: संस्थानों के बीच सहयोग को सक्षम बनाने के लिए साझा अनुसंधान अवसंरचना का निर्माण, शिक्षा को एक प्रभाव-गुणक के रूप में उपयोग करना, और शुरुआत से ही एआई सिद्धांतों जैसे सुरक्षा, संरक्षा और मजबूती को शामिल करना।

शैक्षणिक सेतु का निर्माण

शिक्षा और प्रतिभा विकास दीर्घकालिक सहयोग की नींव बने हुए हैं। गुप्ता ऐतिहासिक उदाहरणों का उल्लेख करते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर की ओर संकेत करते हैं। "अमेरिकी सरकार ने आठ अमेरिकी विश्वविद्यालयों को साथ लाकर आईआईटी कानपुर के निर्माण में मदद की। उन विश्वविद्यालयों को शायद कभी पता भी नहीं था कि कानपुर कहां है, लेकिन उन्होंने संपर्क स्थापित किए," वह कहते हैं।

आज, भारत के उभरते एआई संस्थान समान साझेदारियों से लाभ उठा सकते हैं। "आईआईटी पलक्कड़, आईआईटी रोपड़ और आईआईटी गुवाहाटी सहित कई भारतीय संस्थानों में अब एआई पर केंद्रित स्कूल हैं। इन संस्थानों को अमेरिकी साझेदारों से जोड़ना सहयोग को तेज कर सकता है," गुप्ता कहते हैं। वह जोड़ते हैं कि सहयोग अक्सर जमीनी स्तर से शुरू होता है। "लोग सोचते हैं कि सहयोग के लिए बड़ा बजट या उच्च-स्तरीय समझौता चाहिए। लेकिन वास्तव में यह जमीनी स्तर से शुरू होता है," वह समझाते हैं। "यदि हाई स्कूल और ग्रेजुएट स्तर के विद्यार्थी इन नए विषयों को सीखना शुरू करते हैं, तो वे भविष्य के लिए प्रतिभा स्रोत बन जाते हैं, जैसे आईआईटी बने।"

बरुआ प्रतिभा पाइपलाइन और सहयोग को मज़बूत करने के लिए व्यावहारिक उपायों पर जोर देते हैं। "द्विपक्षीय कार्यक्रम जो द्वि-राष्ट्रीय टीमों का समर्थन करते हैं और वास्तविक दुनिया पर प्रभाव डालने पर जोर देते हैं, विशेष रूप से प्रभावी होते हैं," वह समझाते हैं। "सफल सहयोग में तीन विशेषताएं होती हैं: स्पष्ट रूप से परिभाषित लक्ष्य, कोड, डेटा या बेंचमार्क जैसे साझा संसाधन, और सह-मार्गदर्शन, यात्राओं और नियमित कार्यशालाओं के माध्यम से निरंतर व्यक्तिगत संपर्क।"

सफल साझेदारियां अमेरिका की बौद्धिक स्वतंत्रता की संस्कृति से भी लाभान्वित होती हैं, जहां व्यक्ति उम्र या डिग्री की परवाह किए बिना चुनौतियों को स्वीकार कर सकते हैं, जिससे सीमाओं के पार नवाचार को बढ़ावा मिलता है।

प्रभाव और संभावनाएं

एआई का उदय इस सवाल को भी उठाता है कि समाज स्वायत्त प्रणालियों पर नज़र कैसे रखे। गुप्ता कहते हैं कि जहां पारंपरिक मशीनें मानव निर्देशों का पालन करती हैं, वहीं एआई प्रणालियां तेजी से स्वायत्त निर्णय लेने लगी हैं, जिससे संचालन फ्रेमवर्क आवश्यक हो जाते हैं। "चूंकि मशीनें केवल भौतिक नियमों का पालन करती हैं, सामाजिक नियमों का नहीं, इसलिए हमें ऐसी संचालन व्यवस्थाएं विकसित करनी होंगी जो एआई का मार्गदर्शन करें," वह कहते हैं।

गुप्ता इस बात पर जोर देते हैं कि मानव अनुभव से विकसित कौशल जैसे संचार, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, रचनात्मकता और शिल्प कौशल मूल्यवान बने रहेंगे। कुछ पारंपरिक कौशल जैसे प्लंबिंग, बढ़ईगीरी और कारीगिरी भी अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं क्योंकि वे जटिल क्षमताओं पर निर्भर करते हैं, जिन्हें मशीनें अभी तक पूरी तरह से दोहरा नहीं पाई हैं।

नौकरियों को समाप्त करने के बजाय, एआई उत्पादकता को बढ़ाने की संभावना रखता है। "एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की उत्पादकता बढ़ा सकता है। उन्हें प्रतिस्थापित करने के बजाय, यह उन्हें कई लोगों के काम करने और पूरी तरह नए उत्पाद व सेवाएं बनाने में सक्षम बना सकता है," गुप्ता बताते हैं। वह अनुमान लगाते हैं कि नवाचार की अगली लहर में चिकित्सा से लेकर डिजिटल सेवाओं तक अत्यधिक व्यक्तिगत उत्पाद शामिल होंगे।

आगे देखते हुए, बरुआ आने वाले दशक में नेतृत्व के लिए तीन आधार रेखाएं बताते हैं: साझा अनुसंधान अवसंरचना, विश्वसनीय एआई के लिए साझा मानक, और मजबूत प्रतिभा पाइपलाइन। गुप्ता जोड़ते हैं कि जब एआई तकनीक वर्तमान में परिपक्वता में दस में से तीन या चार के स्तर पर है, तो इसकी संभावनाएं अपार हैं। वह कहते हैं, "सुविचारित नीतियों और सहयोग के साथ, आगे के अवसर अत्यंत व्यापक हैं।"

● गिरिराज अग्रवाल

रोबोटिक्स टेक्नीशियन

अवसरों से भरपूर और सुरक्षित कैरियर

उद्योगों, व्यवसायों व सेवा क्षेत्र में ऑटोमेशन लगातार बढ़ रहा है। यानी ज्यादातर कार्यों के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। ऐसे में हर जगह ह्यूमन के बजाय रोबोट काम करते नजर आएंगे। उनके संचालन, मैंटेनेंस व रिपेयर आदि के लिए रोबोटिक्स टेक्नीशियन की जरूरत होगी। ऐसे में रोबोटिक्स टेक्नीशियन का कैरियर बहुत तेजी से उभर रहा है।

आज का औद्योगिक परिदृश्य बहुत तेजी से बदल रहा है। फैक्ट्री से लेकर अस्पताल तक, वेयर हाउस से लेकर कृषि फॉर्म तक हर जगह रोबोट्स काम कर रहे हैं। स्मार्ट मशीन और ऑटोमेशन अब केवल बड़े उद्योगों तक ही सीमित नहीं रहे बल्कि रोजमर्रा के कामकाज में भी हिस्सा बंटा रहे हैं। इस बदलाव के कारण भविष्य में सबसे ज्यादा जो टेक्नीशियन चाहिए होंगे, वे निःसंदेह रोबोटिक्स टेक्नीशियन होंगे। यही कारण है कि इन दिनों रोबोटिक्स टेक्नीशियन का कैरियर न सिर्फ वर्तमान के लिए बल्कि भविष्य को ध्यान में रखकर भी बहुत तेजी से उभर रहा है।

आखिर कौन होता है रोबोटिक्स टेक्नीशियन

रोबोटिक्स टेक्नीशियन वह शख्स होता है, जो रोबोटिक टेक्निक में माहिर होता है। यह रोबोटिक मशीनों, ऑटोमेटिक सिस्टम इंस्टॉलेशन के अलावा ऑपरेशन मेंटेनेस तथा रिपेयरिंग के काम में दक्ष होता है। कुल मिलाकर यह इंजीनियर नहीं होता बल्कि वह व्यक्ति होता है, जो रोबोट्स को जमीन पर काम करने के लायक बनाये रखता है। जब रोबोट में किसी तरह की गड़बड़ी आ जाती है, तो वह इस गड़बड़ी को दूर करता है यानी जहां इंजीनियर रोबोट्स के डिजाइन बनाता है, वहीं टेक्नीशियन उन्हें काम करने के लायक बनाये रखता है।

तकनीक और व्यवहार का संगम

रोबोटिक्स टेक्नीशियन का काम केवल मशीन ठीक करना ही नहीं है बल्कि यह एक बहुआयामी जिम्मेदारी है, जिसमें शामिल होता है- रोबोटिक सिस्टम की इंस्टॉलेशन, सेंसर, कंट्रोल सिस्टम और मोटर्स की जांच, खराबी की पहचान करना और उसमें सुधार करना, प्रोग्रामिंग की बेसिक कमांड को समझना व मशीनों की नियमित सर्विसिंग। वास्तव में आज के समय में रोबोट केवल मैकेनिकल नहीं बल्कि ये सॉफ्टवेयर आधारित भी हैं। इसलिए टेक्नीशियन को इलेक्ट्रॉनिक और बेसिक प्रोग्रामिंग की समझ में भी माहिर होना जरूरी है।

रोजगार के अवसर

एक रोबोटिक टेक्नीशियन के लिए लगातार रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो रही है। इन्हें उद्योग के कई क्षेत्रों में एक प्रमुख टेक्नीशियन के रूप में देखा जा सकता है। मसलन

● मैन्यूफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आज रोबोटिक टेक्नीशियन इसलिए बड़ी संख्या में मौजूद हैं, क्योंकि मैन्यूफैक्चरिंग इंडस्ट्री करीब-करीब ऑटोमेशन में चली गयी है यानी इस इंडस्ट्री को रोबोट ही संभालते हैं।

● ई- कॉमर्स कंपनियां जैसे अमेजोन, फ्लिप कार्ट अपने वेयर हाउसेज में ऑटोमेडेट रोबोट्स को तैनात करते हैं, इसलिए इन जगहों पर रोबोटिक्स टेक्नीशियन को भी रखना जरूरी हो जाता है।

● सर्जिकल रोबोट्स और मेडिकल उपकरणों के रख-रखाव में भी आज ये बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसलिए जहां इनकी मौजूदगी है, वहीं इन पर किसी तरह की कमी होने पर इन्हें दुरुस्त करने के लिए रोबोटिक टेक्नीशियन रखने भी जरूरी होते हैं। इसलिए हेल्थ केयर क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में रोबोटिक्स टेक्नीशियन मौजूद हैं।

● कृषि क्षेत्र में व्यवस्थित तरीके से स्मार्ट फार्मिंग ड्रोन और रोबोट्स कर रहे हैं, न कि इंसान। इसलिए हर समय काम के लायक बनाये रखने के लिए रोबोटिक टेक्नीशियन भी जरूरी हो गये हैं।

● होटल, मॉल, एयर पोर्ट आदि जगहों पर सर्विस रोबोट्स का उपयोग बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसलिए इन जगहों में रोबोटिक्स टेक्नीशियन की जरूरत पड़ती है।

ऐसे बनें रोबोटिक्स टेक्नीशियन: इस क्षेत्र में प्रवेश के लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई जरूरी नहीं है, लेकिन तकनीक की समझ बहुत जरूरी है। 10वीं या 12वीं पास उम्मीदवार भी रोबोटिक टेक्नीशियन बन सकते हैं बशर्ते उन्होंने आईटीआई से इलेक्ट्रीशियन, फिटर और इलेक्ट्रॉनिक का डिप्लोमा किया हुआ हो। इसके अलावा डिप्लोमा इन रोबोटिक्स/मैकट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल वाले भी रोबोटिक्स टेक्नीशियन बन सकते हैं। छह महीने से लेकर एक साल तक का रोबोटिक्स टेक्नीशियन कोर्स भी उपलब्ध है तथा पीएलसी और ऑटोमेशन ट्रेनिंग के जरिये भी रोबोटिक टेक्नीशियन बना जा सकता है। वहीं इंडस्ट्रियल रोबोटिक टेक्नीशियन सर्टिफिकेशन के जरिये भी इस रोबोटिक टेक्नीशियन के क्षेत्र में एंट्री मिलती है।

जरूरी कौशल

रोबोटिक्स टेक्नीशियन बनने के लिए ये कुशलताएं होनी जरूरी हैं : इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की समझ, मैकेनिकल सिस्टम का ज्ञान, प्रॉब्लम सॉलविंग एबिलिटी, बेसिक कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग का ज्ञान, टीम वर्क और संचार कौशल।

सैलरी और कैरियर ग्रोथ

रोबोटिक्स टेक्नीशियन की शुरुआती तनख्वाह 15 से 30 हजार रुपये प्रतिमाह होती है और 3 से 5 साल का अनुभव होने के बाद यह वेतन 40 हजार से 80 हजार रुपये प्रतिमाह होनी संभव है। अगर किसी पेशेवर को अनुभव पांच साल के ऊपर का है और दक्षता है, तो 8 से 15 लाख रुपये सालाना का पैकेज मिलना मुश्किल नहीं होता। यह सबसे फ्यूचर प्रूफ कैरियर है। क्योंकि 2030 तक भारतीय ही नहीं बल्कि दुनियाभर की इंडस्ट्री का लगभग 80 फीसदी काम आटोमेटिक हो जायेगा, तब अधिकतम काम रोबोट्स ही संभालते नजर आएंगे। इसलिए आने वाले दिनों में रोबोटिक्स टेक्नीशियन की मांग तेजी से बढ़ने वाली है।

संपादकः अली आदिल खान द्वारा सांई प्रिंटिंग प्रेस डी-85, न्यू अशोक अगर, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, यूपी से मुद्रित कराकर सी-148, साउथ मोती बाग,पो. चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021 से प्रकाशित किया।
RNI No.: DELMUL/2012/47011 | Email:timesofpedia@gmail.com | समाचार चयन एवं प्रकाशन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार तथा समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे।